बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 292

# अमेरिका की घटती वैश्विक भूमिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के तुरंत बाद दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे एक महाशक्ति जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसी महत्त्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का नेतृत्व करने से कदम पीछे खींच रहा है। इनमें से पहला आदेश, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत 2015 के पेरिस समझौते से अमेरिका का बाहर निकलना है। वहीं दूसरा आदेश, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को छोड़ना है। ये दोनों ही निर्णय ट्रंप के अमेरिका प्रथम (अमेरिका फर्स्ट) एजेंडे को दर्शाते हैं। सवाल यह है कि इनसे बाहर निकलने का अमेरिका को क्या फायदा होगा और क्या इससे बाकी दुनिया, खासतौर पर विकासशील देशों पर वाकई कोई असर पड़ेगा जो दुनिया की आबादी का 83 फीसदी हिस्सा हैं।

सबसे पहले पेरिस समझौते से बाहर निकलने की बात पर आते हैं। पिछली बार जब अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने ऐसा किया तब यह कदम विफल रहा क्योंकि उस समय समझौते के मुताबिक किसी देश को समझौते से बाहर होने के लिए चार साल की समय-सीमा की आवश्यकता थी। लेकिन तब तक जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए और अमेरिका इस समझौते में फिर से जुड़ गया। इसके अलावा 30 अमेरिकी राज्यों और कई स्थानीय निकायों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के कार्यक्रमों पर अमल करना जारी रखा और समझौते का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। हालांकि अब इस समझौते से निकलने की समयसीमा एक वर्ष है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते में अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का कार्यकारी आदेश अन्य देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने और समझौते को अपनाने में अमेरिका के योगदान को सीमित करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान स्थापित अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना भी बंद कर दी जिसे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों के माध्यम से फंड देने के लिए स्थापित किया गया था ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके।

ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही निवेश बैंकों ने ग्रीन फंडों से निकलने के संकेत देने शुरू कर दिए थे जो वैसे भी विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से अपर्याप्त है और अब तो यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रभाव से जुड़े सभी शोध रोक दिए हैं और फिर से पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया है जिससे 2035 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 61-66 फीसदी तक घटाने के अमेरिका के लक्ष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहा है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जन करने वाले देश के द्वारा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कार्रवाई रोकना, जलवायु संकट की गंभीरता के प्रति नकारात्मक संकेत देता है जो ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ाने में ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार रहा है।

डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के निकलने असर जल्द ही महसूस किया जाएगा क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका अपनी सदस्यता शुल्क देना बंद कर देगा जिसे वह अनुचित मानता है। डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका ने दिया और अब इसके निर्णय का तत्काल असर यह होगा कि कई महत्त्वपूर्ण वैश्विक शोध कार्यक्रमों की फंडिंग के लिए जोखिम बढ़ जाएगा जो बीमारियों और टीके के विकास के लिए हैं जिनमें चेचक, कोविड, फ्लू और महामारी के चलते उभरने वाली कई बीमारियां शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ के माध्यम से ही अमेरिका गरीब देशों के बच्चों के लिए स्वच्छ जल, भोजन और टीके से जुड़े कार्यक्रमों के लिए मदद देता है। डब्ल्यूएचओ से हटने से अमेरिका भी प्रभावित होगा क्योंकि यह बीमारियों से जुड़े वैश्विक सूचना डेटाबेस से बाहर हो जाएगा जिनमें इन्फ्लुएंजा की नई किस्म भी शामिल है। हालांकि इस तरह की आलोचना बिल्कुल जायज है कि डब्ल्यूएचओ में सुधार की आवश्यकता है लेकिन इससे अलग हो जाना इसका जवाब नहीं हो सकता है। यह संभव है कि चीन इस कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करे जैसा कि उसने कोविड महामारी के दौरान ट्रंप द्वारा डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने के बाद 3 करोड़ डॉलर देने का वादा किया था। अब सवाल है कि क्या यह दुनिया के हित में है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र अपना नैतिक नेतृत्व दुनिया के सबसे शक्तिशाली अधिनायकवादी शासन के हवाले कर रहा है।

बिनय सिन्हा

# सुस्त पड़ता सरकारी उपक्रमों का विनिवेश

**आरआईएनएल में नए सिरे से पूंजी डालना बताता है कि सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश पर सरकार का रुख कितना बदला है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य**

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मुश्किलों से जूझ रही सरकारी कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को उबारने के लिए 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी। यह सरकारी कंपनी विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को चलाती है। पैकेज के तहत आरआईएनएल में 10,300 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जानी है और 1,140 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण को सात फीसदी गैर संचयी वरीयता शेयर पूंजी में बदली जानी है, जिसे 10 साल बाद भुनाया जा सकता है।

इस साल आरआईएनएल की कुल देनदारी बढ़कर 35,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। कर्ज अदायगी और ब्याज भुगतान से वह चूक भी चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि इन फैसलों से आरआईएनएल की वित्तीय दिक्कत कम हो सकेगी। साथ ही उसकी कार्यशील पूंजी बढ़ेगी और धीरे-धीरे वह अपनी पूरी क्षमता से चलते हुए सालाना 73 लाख टन स्टील बनाने लगेगी।

परंतु इक्विटी के लिए पैसा कहां से आएगा? इस्पात मंत्रालय के 2024-25 के बजट में आरआईएनएल को यह राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी के लिए केवल 620 करोड़ रुपये का पूंजीगत आवंटन किया गया है और यह पूंजी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को 'अन्य' मदों से खुद जुटानी है। मुश्किलों से जूझ रहे स्टील प्लांट के लिए भी बजट में केंद्रीय रकम का इंतजाम नहीं किया गया था। बजट भाषण में यह जरूर कहा गया था कि आंध्र प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

ऐसे मामलों में पैसा पूरक अनुदान मांगों के माध्यम से जुटाया जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि केंद्र का वास्तविक व्यय बोझ बढ़ेगा। हां दूसरे मदों में इतनी ही रकम बचा ली गई तो केंद्र पर बोझ नहीं पड़ेगा। आरआईएनएल के मामले में अच्छी खबर यह है कि शायद अनुपूरक अनुदान मांग की जरूरत ही न पड़ेगी और कंपनी को दी जा रही राशि केंद्रीय बजट पर बोझ नहीं बढ़ाएगी। 2024-25 के बजट में लगभग 62,593 करोड़ रुपये की राशि नई योजनाओं में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित की गई। नवंबर 2024 खत्म होने तक नई योजनाओं पर इस राशि का बहुत कम हिस्सा खर्च किया गया था। माना जा रहा है कि आरआईएनएल में पूंजी इसी आवंटित राशि से डाली जाएगी और सरकार की व्यय योजना में यह पहले ही शामिल है। इसके लिए अच्छे वित्तीय नियोजन की आवश्यकता है।

बहरहाल इसमें बुरी खबर यह है कि सरकार ने आरआईएनएल के निजीकरण की योजना त्याग दी है। याद रहे कि जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की इसी कैबिनेट समिति ने आरआईएनएल में सरकारी हिस्सेदारी की 100 फीसदी बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। खबरों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय के एक समूह को अधिकार दिया था कि कि वह संभावित निवेशकों से बात करके यह निर्णय करे कि आरआईएनएल की अनुषंगी कंपनियों को निजीकरण की योजना में शामिल किया जाए या नहीं। आरआईएनएल 2016-17 से ही घाटे में है। केवल 2018-19 में उसने 97 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ कमाया था। लागत कम करने की कोशिश में वह कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी लाई थी मगर उसके वित्तीय प्रदर्शन पर इसका खास असर नहीं पड़ा।

ऐसा लगता है कि आरआईएनएल के निजीकरण का जनवरी 2021 का निर्णय किसी और युग में लिया गया था। 2021-22 का केंद्रीय बजट इसके कुछ दिन बाद सामने आया था। उसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस और नीलाचल इस्पात निगम जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश अगले कुछ महीनों में पूरा करने का सरकार का इरादा जताया गया था। एयर इंडिया को जनवरी 2022 में और नीलाचल इस्पात को जुलाई 2022 में टाटा समूह के हाथ बेच दिया गया। मगर बाकी सभी विनिवेश के सौदे या तो अटके हैं या रद्द कर दिए गए हैं।

सरकारी उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश की जिस रणनीति को सरकार से हरी झंडी दी ही, उस पर भी बहुत धीमी प्रगति हुई है। बेशक हाल ही में फेरो स्क्रैप निगम को एक जापानी कंपनी के हाथों 320 करोड़ रुपये में बेचा गया है, लेकिन विनिवेश से हासिल होने वाली राशि के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को आम तौर पर घटाया ही गया है और इस साल से तो विनिवेश से मिलने वाली रकम का बजट में अलग से उल्लेख करना ही बंद कर दिया गया है। अब इसे विविध पूंजीगत प्राप्तियों के मद में डाला जा रहा है। सरकार के रुख में इस बदलाव की अनदेखी नहीं की जा सकती।

ऐसे में आरआईएनएल को उबारने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार रणनीतिक निवेश की अपनी ही नीति पर कितनी धीमी रफ्तार से चल रही है। आरआईएनएल के मसले पर सरकार के रुख में यह बदलाव 2024 के आम चुनाव के बाद एकदम साफ नजर आने लगा है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में खबरें आईं कि अदाणी समूह आरआईएनएल को खरीदने की कोशिश कर रहा है। सरकार की रणनीतिक विनिवेश की नीति के तहत जनवरी 2023 में इसका निजीकरण कर दिया जाना था। मगर यह विचार फौरन त्याग दिया गया।

इसके लिए नीतिगत रुख में परिवर्तन जिम्मेदार है या केंद्र में गठबंधन सरकार इसकी वजह है। जून 2024 में सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ी तो आरआईएनएल को विनिवेश की सूची से तुरंत निकाल दिया गया। आरआईएनएल आंध्र प्रदेश में है, जहां केंद्र की गठबंधन साझेदार तेलुगू देशम पार्टी की सरकार है। सितंबर 2024 में सरकार ने आरआईएनएल का विलय दूसरी सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करने की भी सोची थी। आरआईएनएल की जमीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के हाथ बेचने पर भी विचार हुआ। मगर आखिर में करदाताओं की रकम झोककर उसे बचा लिया गया।

क्या सरकारी उपक्रमों के पोषण और उनकी परिसंपत्तियों की कीमत बढ़ाने के नाम पर इस नीतिगत बदलाव को सही ठहराया जा सकता है? अपनी निवेश योजनाओं के लिए रकम जुटाने और संसाधन बढ़ाने की सरकारी उपक्रमों की क्षमता पिछले पांच साल में बहुत कम हुई है। उन्होंने 2019-20 में आंतरिक संसाधनों तथा बजट के अलावा संसाधनों से 6.4 लाख करोड़ रुपये निवेश किए थे, जो 2023-24 में 3.2 लाख करोड़ रुपये ही रह गए। इसीलिए केंद्र की बजट सहायता पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। 2023-24 में उनके कुल पूंजीगत व्यय में सरकारी योगदान 61 फीसदी रहा, जो 2019-20 में 25 फीसदी ही था यानी पांच साल में सरकारी उपक्रमों का प्रदर्शन सुधरने के बजाय सरकार पर उनकी निर्भरता बढ़ी है।

पिछले पांच साल में इन सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश से उनकी माली सेहत में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। इससे लग रहा है कि कि रणनीतिक विनिवेश की नीति असल में उलटी होकर सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक निवेश की नीति बन गई है। 2024-25 में इन उपक्रमों को अपने दम पर 3.7 लाख करोड़ रुपये कमाने थे, जो 5.45 लाख करोड़ रुपये की बजट सहायता के साथ 9.13 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में मदद करते।

क्या सरकारी उपक्रम 2025-26 में ज्यादा आंतरिक संसाधन जुटा पाएंगे? अपने पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी बजट पर उनकी निर्भरता कम होगी? और क्या सरकार इनके रणनीतिक विनिवेश पर वापस ध्यान देगी? इस बारे में तस्वीर कुछ हद तक 1 फरवरी को साफ होगी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का बजट पेश करेंगी। अगर उसमें भी तस्वीर साफ नहीं होती तो बेहतर होगा कि औपचारिक घोषणा कर सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति बदल दी जाए।

# कंटेंट की भरमार में धुंधला होता बाजार

**ऐपल** टीवी प्लस पर प्रसारित हो रहे 'स्लो हॉर्सेस' में स्लॉ हाउस की कहानी दिखाईगई है, जो एमआई5 से खारिज किए गए लोगों का ठिकाना है। मगर ये स्लो हॉर्सेस रीजेंट पार्क के शानदार दफ्तर में बैठे आम एजेंटों के मुकाबले ज्यादा हरकत में रहते हैं और ज्यादा उत्पात मचाते हैं। ऐपल टीवी प्लस पर इस जासूसी शो का चौथा सीजन आ रहा है, जिसमें गैरी ओल्डमैन ने इन स्लो हॉर्स के उस बेढंगे बॉस की भूमिका बेजोड़ तरीके से निभाई है, जिसे कोई पसंद ही नहीं करता। मुझे ऐपल टीवी प्लस का पता देर से चला। दूसरी ओर डिज्नी के बैनर तले बनी बैरी जेनकिंस की 'मुफासा' प्यारी फिल्म है, जिसमें द लॉयन किंग की शुरुआत दिखाई गई है। जिस रात आईमैक्स थिएटर में मैंने यह फिल्म देखी कमोबेश पूरा थिएटर खाली पड़ा था। उसी हफ्ते गौरव भारद्वाज का भव्य स्तर पर बनाया गया नाटक 'हमारे राम' भी आया। कवितामय संवादों वाले इस नाटक में अद्भुत राम-रावण संवाद दिखाया गया है। राम की शानदार भूमिका राहुल भूचर ने निभाई है आशुतोष राणा ने तो मंच पर रावण को जीवंत ही कर दिया है।

ये कहानियां पिछले दो हफ्तों में मैंने स्ट्रीमिंग सेवा पर, सिनेमा हॉल में और मंच पर देखी हैं। इनके अलावा मैंने ऐपल टीवी प्लस पर जेसन सडेकिस के 'टेड लासो' के तीन सीजन देखे और नेटफ्लिक्स पर क्रिस्टोफर मैक्वेरी की 'मिशन इंपॉसिबलः डेड रेकनिंग पार्ट वन' देखी। इसके अलावा कुकिंग, शाहरुख खान, जाकिर खान, कपिल शर्मा और ग्राहम नॉर्टन आदि के सैकड़ों रील्स या शॉर्ट वीडियो भी थे। मैं रोजाना तीन अखबार पढ़ती हूं, महीने में चार पत्रिकाएं और किताबें पढ़ती हूं। आजकल मैं नॉर्डिक देशों के लेखकों को जमकर पढ़ रही हूं। मगर इस सबके बीच मुझे काम भी करना होता है। हम जो फिल्में, शो और नाटक देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, वे अलग-अलग हो सकते हैं मगर उनकी कहानी ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले लैपटॉप, टेलीविजन या फोन इस्तेमाल करने वाले 52.3 करोड़ भारतीयों में से ज्यादातर के लिए एक जैसी है। सच कहूं तो देखने, पढ़ने या समझने के लिए सामग्री यानी कंटेंट भरा पड़ा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 में समाचार, मनोरंजन और सोशल मीडिया कंटेंट की ऑनलाइन खपत ही रोजाना 2.5 घंटे की थी। टीवी पर रोजाना चार घंटे कार्यक्रम देखे जाते हैं और दूसरे माध्यम भी मिला लें तो एक-तिहाई भारतीय तो रोज करीब 7-8 घंटे इनमें खपाते हैं। (ध्यान रहे कि यह लेख उन 52.3 करोड़ भारतीयों के बारे में है, जिन्हें जरूरत से ज्यादा कंटेंट मिल रहा है। मगर एक बड़ा बाजार वह भी है, जो अभी सस्ते स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़े टीवी का इंतजार कर रहा है)।

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

सरकारी दूरदर्शन और इकलौते अखबार के दौर में पले-बढ़े शख्स के तौर पर मेरे लिए उदारीकरण के बाद की यह बाढ़ गजब की रही है। आज भारत में 900 से अधिक समाचार चैनल हैं, हजारों अखबार हैं और 860 से ज्यादा रेडियो चैनल हैं। हम साल में 1600 से ऊपर फिल्में बनाते हैं। इसके बाद 2018 में स्ट्रीमिंग शुरू हो गई और देखने के लिए कंटेंट की बाढ़ आ गई। अब 60 से अधिक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं और एक दर्जन से अधिक ऐप संगीत स्ट्रीम कर रहे हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस या एआई से डबिंग या सबटाइटल तैयार करने का काम बेहद तेज रफ्तार से हो सकता है, जिससे मीडिया कंपनियां पहले से कम खर्च में शो, फिल्म, टेक्स्ट आदि तैयार कर पाएंगी। इसका मतलब है कि पहले ही कंटेंट में डूब रही दुनिया में कंटेंट का नया जमावड़ा हो जाएगा।

इससे तीन सवाल पैदा होते हैं। पहला, इन सबका अंत कहां होगा? शायद तब, जब इंसानों के पास कहने के लिए कहानी ही नहीं होंगी। दूसरा, इसका अर्थ क्या है? शायद मानव इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रमित उपभोक्ता? एक शोध कहता है कि स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले औसतन 8 सेकंड तक ही कहीं टिक पाते हैं। यह गोल्डफिश से भी कम है, जो लगातार 9 सेकंड तक कुछ टिककर देख पाती है। इतना कम ध्यान देने वाले उपभोक्ताओं को आप कहानी कैसे सुनाएंगे या उत्पाद कैसे बेच पाएंगे? बाजार में अरबों विकल्प हैं, जो बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रसारकों, स्ट्रीम करने वालों, प्रकाशकों, बाजारविदों और इनफ्लुएंसरों के बीच अब कहानी सुनाने की ही होड़ है। बाजार कितना बड़ा है, देख लीजिए : यूट्यूब पर ही हर मिनट 500 घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं। इतना ज्यादा कंटेंट हमारे दिमाग पर किस तरह असर डाल रहा है, दुनिया भर में इस पर अध्ययन किया जा रहा है।

हैरत की बात नहीं है कि कि चीजों का आनंद लेने, सराहने और उन पर चर्चा करने की हमारी क्षमता कम हो रही है। शायद इसीलिए स्टारडम कम हो रहा है, बहुत कम फिल्में सफल हो रही हैं और गूगल, मेटा जैसे प्लेटफॉर्मों की तूती बोल रही है। इससे पहले मीडिया का पूरा अर्थशास्त्र इस बात पर चलता था कि कोई सामग्री कितनी बार देखने के काबिल है। कोई कामयाब फिल्म, शो या संगीत लंबे अरसे तक चलता रहता था और उसे तैयार करने वाली कंपनी के पास कमाई के खूब मौके होते थे। अब गूगल और मेटा मुश्किल से चौथाई कीमत पर सभी श्रेणियों और स्थानों के दर्शकों को यह सब कंटेंट मुहैया करा रही हैं। दोबारा देखना भूल जाइए, उपभोक्ताओं को कोई किताब या शो याद रह जाए तो ही बड़ी बात है।

पहले इंटरनेट और उसके बाद सोशल मीडिया ने जिस तरह कंटेंट को सर्वसुलभ बना दिया, उससे मनोरंजन करने वालों और पाने वालों, सूचना देने वालों और लेने वालों, लेखक और पाठक, श्रोता और संगीतकार के बीच का भेद समाप्त हो गया। ऑनलाइन दुनिया खुली हुई है, दुनिया भर में फैली है और वहां कोई भी कुछ भी पेश कर सकता है। लोग बच्चों के बारे में बता रहे हैं, पाक कला के जौहर दिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि वे हस्तियों की कितनी अच्छी नकल कर लेते हैं। जब सब लोग कंटेंट बनाएंगे तो देखेगा-सुनेगा कौन? यही तीसरा सवाल है।

इस भीड़भाड़ ने मीडिया कारोबार के सामने गहरा संकट पैदा कर दिया है। गुणवत्ता की अपेक्षा बढ़ रही हैं, लागत बढ़कर दो या चार गुना हो गई है। पैसे कमाने के लिए जूझ रही स्ट्रीमिंग सेवाएं काफी हद तक टीवी की तरह हो रही हैं। कमाई बढ़ाने के लिए अब वे भी विज्ञापन दिखा रही हैं और खेल, गेम्स तथा लोकप्रिय कार्यक्रम शामिल कर रही हैं। फिल्मकार अपने दर्शकों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पिछले साल मेरी बातचीत लेखक और विज्ञापन जगत की शख्सियत प्रसून जोशी से हुई थी। वह इस दौर को 'कंटेंट का अपच' कह रहे थे। यह गजब की उथल-पुथल का दौर है, जिसके आखिर में शायद अमृत निकल आए।

## आपका पक्ष

**अमेरिकी राष्ट्रपति के साहसिक निर्णय**

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साहसिक निर्णयों पर प्रकाशित लेख और संपादकीय 'मागा की वापसी' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले साहसिक निर्णयों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपने देश के हितों को संरक्षित किया है और टैरिफ और मौद्रिक नीति से ही अपने उद्योग व्यापार, कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। विदेशी नागरिकों के आव्रजन पर नियंत्रण और अमेरिका में जन्मे उनके संतानों के जन्मसिद्ध अधिकार को समाप्त करके बड़ी संख्या में इस्लामिक और अफ्रीकी देशों की बढ़ती अमेरिकी नागरिकों की जनसंख्या पर रोक लगाना प्रशंसनीय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और जलवायु परिवर्तन और संरक्षण पर वैश्विक संगठन केवल विकासशील देशों को ही प्रताड़ित कर रहे थे। इसलिए अमेरिकी वित्तीय सहायता के बिना इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। आतंक पोषण करने वाले देशों को अमेरिकी विरोध का सामना करना पड़ेगा, यह स्पष्ट हो रहा है। वर्तमान में आतंकवाद ने पूरे विश्व को विचलित किया है और आतंक को समर्थन देने वाले देशों का वैश्विक बहिष्कार और उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई आवश्यक और अपेक्षित है। चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, ईरान के लिए राह बहुत कठिन होने वाली है। अमेरिका के कठोर और साहसिक निर्णयों से भारत पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि टेक्नोलॉजी, रक्षा सौदों और व्यापार में प्रगति अवश्यंभावी है। ऐसे ही कठोर निर्णय भारत को भी लेने चाहिए। यह कहना और भविष्य को रेखांकित करना अभी जल्दबाजी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अनिश्चितता की ओर जा सकती है। डॉनल्ड ट्रंप को अपनी प्राथमिकताएं अच्छी तरह पता हैं और वह दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं इसलिए उनके निर्णय 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' को सत्यनिष्ठा से आगे बढ़ाएंगे। भारत को किसी आशंका की आवश्यकता नहीं है।

*विनोद जौहरी, दिल्ली*

विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को अमेरिका में सीनेटर मार्क वार्नर से मिले और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की

**ऑस्ट्रेलिया में जंक फूड विज्ञापनों पर प्रतिबंध**

ऑस्ट्रेलिया ने 1 जुलाई, 2025 से सार्वजनिक परिवहन पर जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाकर स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करना है। शोध यह स्पष्ट करते हैं कि जंक फूड के विज्ञापनों का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मोटापा और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं। यह प्रतिबंध माता-पिता और समाज को यह संदेश देता है कि स्वस्थ आहार को महत्त्व देना चाहिए। भारत के लिए भी यह एक प्रेरणास्रोत कदम हो सकता है। जंक फूड की बढ़ती प्रवृत्ति ने बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। बड़े विज्ञापन माध्यमों के जरिये स्वस्थ भोजन का प्रचार-प्रसार करके समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा सकती है।

*प्रो. आरके जैन, बड़वानी*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। सरकार ने वर्ष 2021 में नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छात्रों से संवाद भी किया।

## ट्रंप का आदेश

### एच-1बी वीजा सुधार

**डोनाल्ड** ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा सुधारों से वीजा व्यवस्था की विकृतियां बड़ी सीमा तक दूर होंगी और भारतीय पेशेवरों को लाभ होगा। एच-1बी वीजा लंबे समय से कुशल विदेशी कामगारों, खासकर भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2023 में एच-1बी वीजा प्राप्त करने वालों में 72 प्रतिशत भारतीय थे, इसलिए इस कार्यक्रम में किसी सुधार का भारतीय पेशेवर समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीसा व्यवस्था में आमूल सुधार शुरू किए हैं तथा चयन प्रक्रिया को लाटरी-आधारित व्यवस्था के बजाय वेतन-आधारित माडल में बदल दिया है। 17 जनवरी, 2025 से लागू होने वाले इन परिवर्तनों का लक्ष्य वीजा प्रक्रिया को सहज बनाना तथा अत्यधिक कुशल पेशेवरों को प्राथमिकता देना है। एच-1बी वीजा कार्यक्रम की शुरुआत 1990 में की गई थी और इसका उद्देश्य अमेरिकन कंपनियों को विशिष्ट कौशल वाले विदेशी कामगारों की सेवा लेने की अनुमति देना था। यह टेक् व उभरते क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं और इनसे कंपनियों को कौशल की कमी पूरी करने में सहायता मिली है। अकेले वर्ष 2023 में 386,000 एच-1बी वीजा जारी ए् गए थे जिनमें से लगभग तीन चौथाई भारतीय नागरिकों को मिले थे। इस कार्यक्रम से न केवल कौशल की कमी को संबोधित कर अमेरिकन अर्थव्यवस्था को लाभ मिला, बल्कि इससे भारत-अमेरिका

संबंधों को भी प्रतिभा एवं खोज के हस्तांतरण से भी लाभ हुआ। सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन लाटरी-आधारित व्यवस्था के बजाय वेतन-आधारित चयन प्रक्रिया है। इस सुधार से सुनिश्चित होगा कि अत्यधिक कुशल पेशेवर को प्रतियोगी वेतनों पर प्राथमिकता दी जाएगी जिससे कार्यक्रम ज्यादा 'प्रतिभा प्रमुख' बनेगा। इसके साथ ही अब अमेरिका में रह रहे भारतीय पेशेवर अपने एच-1बी वीजा का नवीनीकरण वहीं रह कर करवा सकेंगे। इससे महंगी तथा समय लगने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्रा से मुक्ति मिलेगी। एफ-1 वीजा पर अमेरिका में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि अब इनका एच-1बी वीसा में हस्तांतरण ज्यादा प्रभावी रूप से हो सकेगा जिससे कॅरियर में प्रगति सहज बनेगी।

अब शोध उन्मुख संस्थानों को वार्षिक वीजा सीमा से बाहर रखा गया है जिससे अकादमिक और वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा मिलेगा। इन सुधारों का उद्देश्य खासकर भारतीय पेशेवरों और छात्रों को लाभ पहुंचाना है। वेतन को प्राथमिक आधार बनाने से टेक्नोलोजी, इंजीनियरिंग व स्वास्थ्यरक्षा जैसे अत्यधिक मांग वाले क्षेत्रों में भारतीय कुशल कामगार ज्यादा आसानी से वीसा प्राप्त कर सकेंगे। सहज प्रक्रिया तथा देश में ही रह कर नवीनीकरण से पेशेवरों और उनके परिवारों में अनिश्चितता दूर होगी। सर्वोत्तम कौशल बनाए रखना सुनिश्चित कर ये परिवर्तन अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग और मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के सुधारण प्रतिभा प्राप्ति और आर्थिक प्रगति के प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वीजा नीतियों को अमेरिकन बिजनेसों की आवश्यकताओं से जोड़ने तथा प्रतिभा को पुरस्कृत कर ये परिवर्तन खोज एवं क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। हालांकि, ये सुधार सही दिशा में एक कदम हैं, पर इसके लिए वीसा धारकों तथा सेवायोजकों पर कठोर निगरानी जरूरी होगी। एच-1बी वीसा सुधार के इस कदम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, पर इससे छोटी कंपनियों के समक्ष चुनौतियां भी बढ़ेंगी जो प्रतियोगी पर कम वेतन का प्रस्ताव करती हैं। इसके साथ ही इस परिवर्तन से भारतीय पेशेवरों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने कॅरियर विकल्पों को उच्च-वेतन वाली भूमिकाओं के अनुरूप निर्धारित करें। इसके परिणामस्वरूप अकादमिक व गैर-मुनाफे वाले क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।

# रेणुका जी बांध का महत्व

हिमाचल प्रदेश की गिरि नदी पर आधी शताब्दी पहले रेणुका जी बांध की कल्पना की गई थी। इससे भारत के 6 राज्यों में पानी व ऊर्जा संकट दूर करने में सहायता मिल सकती है।

**केएस तोमर**
(लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हैं)

हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण गिरि नदी पर 58 वर्ष पहले रेणुका जी बांध परियोजना की कल्पना की गई थी, लेकिन अंतत: अब दशकों के विलंब के बाद इसे गेम-चेंजर माना जा रहा है। इस उल्लेखनीय पहल से जहां दिल्ली का भयानक जल संकट दूर होगा, वहीं हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को टिकाऊ रूप से बिजली मिलेगी। वित्तीय लाभों के साथ ही यह बांध संघीय सहयोग तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 6,946 करोड़ की इस परियोजना की नीव 27 दिसंबर, 2021 को रखी थी।

अब इसकी 95 प्रतिशत प्रक्रियागत बाधायें दूर होने के बाद वैश्विक टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे और इसके निर्माण का रास्ता साफ होगा। अनुमान है कि अब इस पर 8,262 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो पांच प्रति वार्षिक वृद्धि है। 2030 में पूरी होने की आशा वाली इस परियोजना को 2032 में सक्रिया किया जाएगा जो दिल्ली तथा इसके अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगी। दिल्लीवासियों के लिए यह बांध 58 साल पुराना सपना साकार होने की तरह है।

इसमें भंडारित जल हथिनीकुंड बराज से होकर वजीराबाद और ओखला बैराजों से गुजरता हुआ दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को मिलेगा। दिल्ली में रोज 1,200 मिलियन गैलन-एमजीडी पानी की मांग है और गर्मी में उसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। रेणुका जी बांध से मिलने वाला 275 एचजीडी पानी इस कमी को पूरा करेगा, घरेलू सप्लाई को गति देगा तथा औद्योगिक विकास व ढांचागत विकास में अत्यंत सहायक भी बनेगा।

हरियाणा इसमें सबसे ज्यादा 47.82 प्रतिशत यानी 555.95 करोड़ खर्च करेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश 31.05 प्रतिशत यानी 361.04 करोड़, राजस्थान 9.34 प्रतिशत यानी 108.58 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली क्रमश: 36.67 करोड़, 30.17 करोड़ तथा 70.25 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इस प्रकार राज्य इस महत्वपूर्ण परियोजना में 1,162,66 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। मूल रूप से इस परियोजना का लक्ष्य दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रगति दिखाना था, पर विलंब के कारण इसके निर्माण में 5-6 महीनों का विलंब हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से डिजाइन स्वीकृति तथा टेंडर प्रक्रिया में तेजी आई है, पर स्थानीय स्तर पर तनाव बना हुआ है। जनसंघर्ष समिति ने परियोजना अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने पुनर्वास प्रयासों के लिए बहुत कम रकम निर्धारित की है। इसके अलावा विस्थापित परिवारों के लिए समुचित मुआवजे का प्राविधान नहीं है।

एक्टिविस्टों की मांग है कि सार्वजनिक कार्य विभाग के अनुमानों की तुलना में भुगतान अधिक होना चाहिए और वर्तमान मुआवजा नाकाफी है। एचपी पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना इन आरोपों को खारिज करते हुए बताते हैं कि 1,573 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं और 90 बेघर परिवारों को पुनर्वास विकल्प दिए गए हैं। इससे हिमाचल प्रदेश को हर साल 66 करोड़ रुपये की 200 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। दिल्ली ने 270 करोड़ फंड हस्तांतरित कर दिया है जिससे 300 करोड़ की बिजली मशीनरी का 90 प्रतिशत भुगतान हो गया है। इससे परियोजना का महत्व स्पष्ट होता है। रेणुका जी बांध हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित होगा जो अपने भौगोलिक व जलविज्ञान लाभों के दृष्टिकोण से बांध के लिए आदर्श स्थल है। यमुना की सहायक गिरि नदी इसमें निरंतर जल प्रवाह सुनिश्चित करेगी। इस स्थल का असाधारण सांस्कृतिक महत्व भी है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की माता देवी रेणुका के नाम से जुड़ा है। इस क्षेत्र में पौराणिक रेणुका झील भी है। यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जहां पूरे साल तीर्थयात्री आते रहते हैं।

देवी रेणुका और भगवान परशुराम के प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार यह परियोजना धार्मिक महत्व के साथ तकनीकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है जो आने वाली अनेक पीढ़ियों तक दिल्ली की प्यास और ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार है। 8,262.28 करोण की रेणुका जी बांध परियोजना में 148 मीटर ऊंचा चट्टानों से बना ढांचा होगा जो 6 राज्यों को पानी और बिजली सप्लाई करेगा। इससे 1,508 हेक्टर जमीन डूबेगी तथा इससे 7,000 निवासी विस्थापित होंगे जिनमें 346 बेघर परिवार भी शामिल हैं।

यह परियोजना 41 गांवों और 25 पंचायतों में फैली होगी। जनवरी, 2019 में 6 लाभार्थी राज्यों के साथ केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमओयू हस्ताक्षर करवाने में सफलता पाई। 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को वित्तीय समर्थन देने की स्वीकृति दी जिससे यह परियोजना कार्यरूप में परिणत हो सकी। डहाऊ गांव के निकट स्थित बांध में 498 मिलियन क्यूबिक मीटर जल एकत्र होगा जिसे प्रमुख बैराजों के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इससे दिल्ली को प्रति सेकेंड 23,000 लीटर जल प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही 40 मेगावाट पनबिजली उत्पादन से हिमाचल प्रदेश को हर साल 120 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। तकनीकी विशेषज्ञों का अनुमान है कि गिरि नदी के प्रवाह में 110 प्रतिशत वृद्धि होगी जिससे गर्मी के मौसम में लगातार पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी। इस प्रकार रेणुका जी बांध दीर्घकालीन लाभ, दिल्ली के लिए बेहतर जल उपलब्धि, सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा ऊर्जा उत्पादन का मार्ग खोलता है। यह एक प्रकार से सहयोगी संघवाद तथा ढांचागत विकास का भी प्रतीक है।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 90 प्रतिशत लागत वहन करने की स्वीकृति के बाद परियोजना की वित्तीय बाधा दूर हुई। इससे राज्यों की ओर से आने वाला धन प्रवाह भी आसान हुआ और दिल्ली ने फौरन अपने हिस्से का 1,066 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। केन्द्र सरकार ने परियोजना पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने इसे जल शक्ति अभियान तथा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना से भी जोड़ा जिससे बांध का महत्व रेखांकित होता है। परियोजना में तेजी से अनुमतियां मिलने, जीवन्त मध्यस्थता तथा फंडिंग की प्रतिबद्धता से राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रकट होती है। इस परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष के मध्य तक शुरू हो जाएगा तथा इसके पूरे होने का समय 2032 रखा गया है। ऐसे में समय पर क्रियान्वयन के लिए गंभीर निगरानी की जरूरत है। रेणुका जी बांध सहयोगी संघवाद का बहुत अच्छा उदाहरण है जहां केन्द्र और राज्य मिल कर चुनौतियों का सामना करते हैं।

टिकाऊ विकास के प्रतीक के रूप में रेणुका जी बांध राजनीतिक इच्छाशक्ति अंतर-राज्य सहयोग और जटिल चुनौतियों से निपटने में सामुदायिक सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्तंभ है। हिमाचल प्रदेश को 'हरित ऊर्जा केन्द्र' के रूप में बदलने तथा दिल्ली की पानी की आवश्यकता पूरी करने वाली यह परियोजना समावेशी विकास तथा पर्यावरण संरक्षण का भी उल्लेखनीय उदाहरण है।

# हिंसा त्यागकर शांति को अपनाएं

"सच्चा परिवर्तन प्रतिशोध में नहीं, बल्कि प्रेम और शांति के दिव्य गुणों से फिर से जुड़ने में निहित है।"

**ब्रह्मकुमार निकुंज**
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हिंसा हमारी संस्कृति बन गई है। इसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे सैकड़ों युद्धों में देखा जा सकता है या इसे ब्रह्मांड भर के शहरों और घरों में हर दिन होने वाली असंख्य हिंसक घटनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। तो, आखिर किस वजह से हिंसा इतनी फैल गई है, जबकि लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं?

हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास हिंसा की एक महाकाव्य गाथा है, जिसमें सापेक्ष शांति के प्रसंग भी शामिल हैं। हिंसा, सूक्ष्म और स्थूल, प्रकट और गुप्त, पिछले दो सहस्राब्दियों में सत्ता के लिए मानवता की खोज की परिभाषित शक्ति रही है। साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धार्मिक धर्मयुद्ध और सदियों से सामाजिक-राजनीतिक विद्रोह बड़े पैमाने पर हिंसा से प्रेरित थे। हिंसा मानव मानस में इतनी गहराई से समा गई है, इसका एक प्रमुख कारण यह है कि एक ओर, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इसे उचित ठहराते हैं या इसे उचित ठहराते हैं। 21वीं सदी में, जिसमें हम सभी जीने का दावा करते हैं, मीडिया, खासकर टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्मों द्वारा हिंसा को चतुराई से महिमामंडित किया गया है।

एक ऐसी दुनिया जो हिंसा पर इतनी अधिक निर्भर है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसके निवासियों के लिए रहना तेजी से खतरनाक होता जा रहा है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि आज हिंसा राजनीतिक और सामाजिक न्याय की तलाश का साधन बन गई है। लोग भगवान के नाम पर लोगों की हत्या करते हैं और बाद में, जब धर्म के रखवाले इन हत्याओं को धर्म के रूप में उचित ठहराते हैं, जब इसका इस्तेमाल किसी नेक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इन सबके बीच, एक सवाल यह उठता है कि

क्या कोई इतनी हिंसा को उचित ठहरा सकता है? या, क्या हिंसा कभी अधर्म को जड़ से खत्म कर सकती है?

अच्छा!!!! धर्म पर विजय पाने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं के सच्चे धर्म को समझना होगा। हम सभी को यह समझना चाहिए कि अच्छाई या बुराई मानव आत्मा के गुण हैं और मृत्यु के बाद भी ये गुण या संस्कार अगले जन्म में चले जाते हैं। यह संस्कार व्यक्ति के अगले जन्म में उसके कर्म के अनुसार बदल सकता है या मजबूत हो सकता है। इसलिए, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति को मार सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में मौजूद बुराई को नष्ट नहीं कर सकता। इसके बजाय, यह नफरत और बदले की भावना के कारण और भी बढ़ जाएगा। याद रखें!! एक बुरे काम के लिए वर्तमान या अगले जन्म में कर्म के नियम के अनुसार दंडित होना ही पड़ता है, क्योंकि एक प्राकृतिक न्याय प्रणाली है जो अचूक और शाश्वत रूप से काम करती है। इसलिए, किसी को कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई गलत काम करके गलत का बदला लेता है, तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं!

सच्चाई यह है कि इस मामले में, दोनों व्यक्तियों को कुछ कष्ट सहकर अपने-अपने गलत कार्यों के लिए भुगतान करना होगा क्योंकि दूसरों के प्रति दुर्भावना से किया गया कोई भी कार्य हिंसा है और इससे कर्ता को दुख अवश्य मिलता है। इसलिए, एक व्यक्ति देश के कानूनों से बच सकता है, लेकिन उसके कर्म उसे जल्द या बाद में पकड़ लेंगे। हम सभी को धर्म शब्द के पीछे के दर्शन को समझने की जरूरत है। सही मायने में धर्म का मतलब है शांति और प्रेम जैसे शाश्वत आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार जीना। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और सद्भावना बाँटते हैं तो उस व्यक्ति में भी वैसी ही भावनाएँ जागृत होती हैं।

इसके विपरीत, जब हम दूसरों से घृणा करते हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं तो उनमें भी दुर्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। ईश्वर ने हमारे लिए जो संसार बनाया था वह पूरी तरह से अहिंसक और सामंजस्यपूर्ण संसार था जहां कोई बुराई नहीं थी। अच्छाई हमेशा विद्यमान रहती है; जब हम अपने वास्तविक मूल्यों से दूर होने लगते हैं तो हम नकारात्मक प्रवृत्तियों के गुलाम बन जाते हैं। हम सभी सर्वशक्तिमान की संतान हैं जो प्रेम, शांति और आनंद का सागर है, इसलिए उसके गुण हमारे भी शाश्वत गुण हैं, है न? इसीलिए सभी मनुष्य घृणा का विरोध करते हैं। वे कभी भी प्रेम या आनंद का विरोध नहीं करते। वह हमेशा सभी के प्रति दयालु और परोपकारी है, इसलिए वह हिंसा को कैसे उचित ठहरा सकता है?

और पृथ्वी पर शांति और सद्भाव वापस लाने का एकमात्र तरीका है कि हम आध्यात्मिक रूप से खुद को सशक्त बनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताएं दूर करें। इससे दुनिया से हिंसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और दुनिया वैसी ही शांत और शांतिपूर्ण हो जाएगी जैसी वह थी।

## आप की बात

### असंभव को संभव बनाना

**भारत** में जब नवाचार और दृढ़ इच्छाशक्ति की चर्चा होती है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे चमकता है। वे एक ऐसे द्रष्टा हैं जो विचारों को वास्तविकता बनाने का साहस रखते हैं। उन्होंने एक अभूतपूर्व विचार को जन्म दिया है जो शौचालय के पानी को पुन: उपयोग कर 300 करोड़ रुपये की वार्षिक आय का सपना साकार करता है। यह प्रयास न केवल आर्थिक प्रगति की दृष्टि से नई नींव रखता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। शौचालय का जल कृषि और उद्योग में पुन: उपयोग करने से नदियों और जलस्रोतों पर दबाव कम होगा, जिससे जल का संरक्षण होगा और हमारी पृथ्वी को नई सांस मिलेगी। यह वेस्ट टू वेल्थ का महान उदाहरण है, जहां गडकरी जी ने इसे साकार करने के लिए प्रभावी कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इस नवाचार का मूल सिद्धांत है कि बुद्धिमत्ता से संसाधनों का उपयोग कर हम आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह एक प्रेरणा है कि नई सोच और ठोस कार्यवाही देश को कैसे अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अंतत:, यह पहल एक आर्थिक रणनीति से कहीं अधिक है; यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बदलाव की नई कहानी लिखता है और भारत को विश्व मंच पर एक अनोखी पहचान देता है। यह स्पष्ट करता है कि जहां नवाचार और दृढ़ इच्छाशक्ति मिलती है, वहां असंभव की कोई जगह नहीं।

**- आरके जैन**, बड़वानी

### नेताजी बोस का योगदान

**भारत** की स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन की भूमिका को अक्सर महत्व दिया जाता है, लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा है? क्या सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रभाव भी इसमें महत्वपूर्ण था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को सार्वजनिक किए जाने से आधुनिक भारतीय इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। नेताजी के विद्वान जनरल जीडी बख्शी की अभी तक प्रकाशित न हुई किताब में क्लेमेंट एटली के साथ बातचीत प्रकाशित की गई है। इन बातचीत में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में नेताजी की सेना की भूमिका सर्वोपरि थी, जबकि अहिंसक आंदोलन की भूमिका को न्यूनतम बताया गया था। सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था। लेकिन क्लेमेंट एटली के बयान से यह स्पष्ट होता है कि सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रभाव भी इसमें महत्वपूर्ण था।

**- विभुक्ति बुपक्या**, खाचरोद, मप्र

### रहस्यमय बीमारी

**वर्तमान** परिदृश्य में हम आधुनिकरण और तकनीकी युग में तो चल रहें है पर कुछ पहलू चुनौती बनकर उभरते हैं। विगत समय से जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी खोफ पैदा करने में पीछे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में रहस्यमय बीमारी पैर पसार कर खौफनाफ मंजर भरा माहौल निर्मित कर रही है। इस बीमारी से 7 दिसम्बर 2024 से अब तक गांव के तीन परिवारों में 17 मौत हों चुकी है। जो दु:ख दर्द की प्रकाष्ठ को तो पार करती है, साथ ही चिंतनीय भी है। की आखिर ऐसी कोन सी बीमारी है जो इतने कम समय में 17 लोगों को गिल गई। और तो और सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इन परिवारों में नए 4 मरीज और मिले। गांव में सनसनी सी फैल गई की क्या रहस्य है, कोन सी बीमारी है। संदेह जताने वाली बात यह लग रही की जिन 17 लोगों की मौत हुई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न्यूरोटाक्सिन जहर की पुष्टि हुई। इस रहस्यवाली बीमारी से खोफ का माहोल हे साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 16 विशेषज्ञों के अलावा कई संस्थानों के बड़े डॉक्टर बीमारी का कारण जानने के लिए रातदिन जुटे हैं। ईस बीमारी से दिमाग और नर्वस सिस्टम डैमेज हों रहा है। कुछ भी हो उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने इतने कम समय में इतने लोगों को खो दिया। स्वाभाविक है गांव में रहस्यमय मौत का मंजर चल रहा और लोग सहमे सहमे हैं।

**- योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

### नकदी वितरण अनुचित

**चुनावी** आश्वासन हो अथवा राज्य की योजनाएं, जाति विशेष के विद्यार्थियों के लिए हो अथवा पन्थ मजहब के आधार पर, महिलाओं को अथवा किसानों को ... किसी को भी किसी भी आधार पर नकद राशि खाते में देना न तो समाज कल्याण है न ही राष्ट्र कल्याण अपितु भ्रष्टाचार का एक वीभत्स रूप है जो अपने देश के राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक न्याय के नाम पर सतत बढ़ता जा रहा है और इससे बढ़ रहा है सामाजिक विखंडन, विद्वेष और राष्ट्रीय असुरक्षा। समाज का कोई वर्ग यदि वंचित है तो उसको उसकी आवश्यकता पूर्ति का दायित्व केवल राज्य का ही नहीं शेष समाज का भी है और हिन्दू समाज में ऐसी अपार संभावना है। राज्य को सभी के प्रति समानता का व्यवहार करना ही उचित है अर्थात यदि राज्य के पास कोई अतिरिक्त मुद्रा कोष ऐसा है जिसके वितरण से राज्य को कोई वित्तीय हानि न हो तो उसका वितरण सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। एक और विकृति का अन्त अपेक्षित है वह है किसी भी संसाधन को नि:शुल्क उपलब्ध करवाना। इस पर तुरन्त विराम नहीं लगा तो न केवल वित्तीय वरन सामाजिक समरसता के लिए भी यह अत्यन्त घातक सिद्ध होगा।

**- डॉ जय प्रकाश**, अंबाला छावनी

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
**responsemail.hindipioneer@gmail.com**
पर भी भेज सकते है।

## चिंतन

# आतंकवाद को फन फैलाने से पहले ही कुचलना जरूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को फरीदकोट में तिरंगा फहराने वाले थे। अचानक पंजाब सरकार ने इस कार्यक्रम में बदलाव का ऐलान कर दिया है। अब फरीदकोट में कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री कहां तिरंगा फहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है। पूरी खबर पढ़ने पर यह सामान्य फेरबदल लग रहा होगा, लेकिन यह सब इतना सहज है नहीं। क्योंकि प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में यह बदलाव आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद किया है। खुद को एसएफजे चीफ बताने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी कि जो उल्टा चलता है, उसका हश्र पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जैसा होगा। उसने एक वीडियो जारी करके कहा था कि फरीदकोट रेलवे स्टेशन और नेहरू स्टेडियम में उसने खालिस्तानी नारे लिखवाए हैं। यहां भगवंत मान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले हैं। सिख युवा कमर पर बम न बांधें और तिरंगा हाथ में न लें। अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आ चुकी है। सरकारें बदलने के साथ बहुत कुछ बदलता है। इसके पीछे मंशा साफ है कि एक आतंकी क्या कहना चाह रहा है। होना तो यह चाहिए था कि पंजाब सरकार वहीं कार्यक्रम करके उसे मुंहतोड़ जवाब देती, लेकिन आयोजन में बदलाव करके घुटने टेकने जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राज्य सरकार पीछे हटी हो। बीते दो साल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यही कारण है कि पाकिस्तान से सटे पंजाब में कट्टरता एक बार फिर रंग दिखाने लगी है। सिख फॉर जस्टिस का स्वघोषित सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठकर पंजाब और हरियाणा में आतंकी साजिश रचता रहता है। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हमले के केंद्र में भी पन्नू ही रहा है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन को भी सपोर्ट करने के आरोप लगे थे। पिछले साल मई में हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे बंधे नजर आए थे। मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया था कि घटनास्थल से ही वीडियो बनाकर पन्नू को शेयर किए गए थे। एसआईटी ने 247 लोगों के एक मॉड्यूल का पता लगाया था, जिसमें 15 तो विदेशी थे। पंजाब के पटियाला में पन्नू ने खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठन ने खालिस्तानी मुर्दाबाद मार्च निकालने का ऐलान किया था। मार्च निकालने के बाद खालिस्तान समर्थकों ने विरोध किया और दोनों समुदायों के बीच तनाव ऐसा बढ़ा कि पत्थरबाजी और बवाल में तब्दील हो गया था। पंजाब के अजनाला में खालिस्तानी समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे ने खूब बवाल मचाया, लेकिन सरकार शांत बनी रही। हालात ये हैं कि खालिस्तान समर्थक संगठनों और आतंकियों की मौजूदगी कनाडा से लेकर दुबई, पाकिस्तान, यूके और ऑस्ट्रेलिया तक है। ये वहीं रहकर एक बार फिर आतंक की चिंगारी को सुलगाने की कोशिशों में लगे हैं। इन्हें नेस्तानाबूद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंजाब सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि पंजाब को हरसंभव सहायता दे ताकि ऐसे सांपों का फन कुचला जा सके जो देश की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयास में लगे हैं।

सियासत
योगेश कुमार सोनी

# वोटरों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी

आम आदमी पार्टी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ने भी बड़े-बड़े वादों की झड़ियां लगा दी। इससे एक बात तो तय हो चुकी है किसी भी दल के पास कोई मजबूत एजेंडा नहीं है। दरअसल जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति की शुरुआत दिल्ली वालों को फ्री चीजें देकर की थी और वह बीते दो बार के चुनाव में इस आधार पर कामयाब भी हुई लेकिन उन्होंने अपने फॉर्मेट को नहीं बदला और इस बार भी फ्री के सामान को बढ़ाकर परोसना शुरू कर दिया। उन्हें हर बार की तरह लग रहा है कि फिर से ऐसे ही बात बन जाएगी लेकिन समीकरणों के आधार पर राह इतनी आसान दिख नहीं रही। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से जनता का मन कुंठित है।

आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर राजधानी में तीनों सक्रिय पार्टी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ने भी बड़े-बड़े वादों की झड़ियां लगा दी। इससे एक बात तो तय हो चुकी है किसी भी दल के पास कोई मजबूत एजेंडा नहीं है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी ने फ्री शिक्षा, बीस हजार लीटर फ्री पानी, 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को फ्री का इलाज, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18000 रुपये, महिलाओं को हर महीने के 2100 रुपये व किराएदार को फ्री बिजली के अलावा तमाम बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं, वहीं दूसरी ओर उस ही फॉर्मेट में कांग्रेस ने फ्री राशन कीट, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, हर नागरिक को 25 लाख तक का फ्री इलाज, बेरोजगार युवाओं को हर माह 8500 रुपये, व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण देने के अलावा तमाम बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। वहीं तीसरी पार्टी, केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी जो कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, वह भी रेवड़ियां बाटने में पीछे नही हैं। बीजेपी की ओर से एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, गर्भवती महिलाओं को 21000 रुपये, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करना, महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, झुग्गियों में पांच रुपये में राशन व वरिष्ठों नागरिकों को 3000 रुपये तक की पेंशन देने के अलावा और भी कई बड़े वादे कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमें संकल्प से सिद्धि की ओर जाना है। ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया है। तीनों पार्टियों के चुनावी वादे बताने के लिए इसलिए जरूरी हैं कि चूंकि जिस तरह दिल्ली वालों को सामान की तरह योजनाओं को बेचा जा रहा है उससे एक बात तो तय है कि सेल बंपर है।

दरअसल जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति की शुरुआत दिल्ली वालों को फ्री चीजों को देकर की थी और वह बीते दो बार के चुनाव में इस आधार पर कामयाब भी हुई लेकिन उन्होंने अपने फॉर्मेट को नहीं बदला और इस बार भी फ्री के सामान को बढ़ा कर परोसना शुरू कर दिया और उन्हें हर बार की तरह लग रहा है कि फिर से ऐसे ही बात बन जाएगी लेकिन समीकरणों के आधार पर राह इतनी आसान दिख नहीं रही। जैसा कि केजरीवाल समेत पार्टी के सभी चोटी के नेताओं को शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा और बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से जनता का मन कुंठित है और लोगों ने यह मान लिया कि आम आदमी पार्टी भी अन्य पार्टियों की तरह राजनीति ही कर रही है, चूंकि केजरीवाल जब अपने पहले कालखंड में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम राजनीति नहीं काम करने आए हैं। दरअसल शराब घोटाले से एक वर्ग बिल्कुल कटता दिखाई पड़ रहा है, चूंकि एक समय पर दिल्ली के हर इलाके में इतने सारे शराब के ठेके खुल गए थे जिससे जनता में अच्छी खासी नाराजगी है। वहीं

दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि आम आदमी पार्टी का जिस पार्टी यानि कांग्रेस की बुराइयां गिनवाते या उसका अंत करके उदय हुआ था उसके साथ ही गठबंधन करके वह जनता के सवाल के घेरे में खड़े हो चुके चूंकि अभी लोकसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं हुआ तो लोग उस बात को अभी भुले भी नहीं है।

यहां अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। जिस कांग्रेस ने शीला दीक्षित की सरकार में एक लंबे समय तक दिल्ली में राज किया, वह आज मात्र एक नई पार्टी की तरह अपनी पृष्ठभूमि तलाश रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीते तीन बार से एक भी सीट नहीं ला पाई। लेकिन दिल्ली को लेकर कांग्रेस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बीते लगभग दशक भर पहले जिस तरह बीजेपी ने देश के मानचित्र से कांग्रेस को गायब सा कर दिया था लेकिन बीते पांच वर्षों में कांग्रेस ने कुछ राज्यों में चुनाव जीतकर कमबैक किया है। उससे लगा था कि दिल्ली में कुछ चमत्कार होने की संभावना है लेकिन सच तो यह निकला कि कांग्रेस जिस तरह बाकी राज्यों में ऊर्जा से चुनाव लड़ी दिल्ली में वैसे पांच प्रतिशत भी नहीं दिखा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती थी अर्थात मात्र उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है। वैसे तो कई बातें हैं जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस चुनावी लड़ाई में कहीं नहीं दिख रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली में एक महीने तक यात्रा निकाली लेकिन राहुल गांधी उसमें एक बार भी नहीं आए और उस समय ही एहसास हो चुका था कि मामला गड़बड़ है।

इसके अलावा दिल्ली चुनावों को लेकर न कोई प्रेस कांफ्रेंस करना या सोशल मीडिया पर कोई ब्यान न देना भी बहुत कुछ कह रहा था। इस मामले को लेकर विशेषज्ञों द्वारा यह माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में आप व कांग्रेस ने अघोषित गठबंधन कर लिया, मतलब कांग्रेस केवल दिखाने के लिए ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब दिल्ली वालों के सामने सवाल यही है कि वह किस ओर जाए। चूंकि चुनावी रेवड़ियां तो सभी बढ़-चढ़कर बांट रहे हैं लेकिन तथ्यात्मक बातें कोई भी नहीं कर रहा। निश्चित तौर पर चुनौतियां आम आदमी पार्टी के समक्ष है चूंकि किला उसको बचाना है। वहीं दिल्ली जीतना बीजेपी के लिए सम्मान की बात है। चूंकि वह बीते दशक भर में ऐसे राज्यों में चुनाव जीत चुकी, जहां कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

जैसा कि इस बार भी दिल्ली में सातों सांसद बीजेपी के हैं और आप व कांग्रेस का गठबंधन भी एक सीट तक नहीं जीत पाया था। यहां दिल्ली की जनता का मिजाज भी समझना बहुत मुश्किल है चूंकि बीते चुनावी अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली वालों को केन्द्र में बीजेपी ही चाहिए लेकिन विधानसभा में नहीं लेकिन इस बार कितना और कैसा चमत्कार करती है वह भी देखना होगा। खेल लहर का है या गुणवत्ता का, यह तो अब जनता का मिजाज बताएगा चूंकि हर दल अपनी शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के चुनाव में रोमांच इसलिए भी बढ़ जाता है चूंकि यह देश की राजधानी है। लेकिन हाल ही में तमाम राजनीतिक दलों की स्थिति देखकर यह लगता है कि कोई अपने कामों को गिनवाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। सभी का रेवड़ियों पर ज्यादा जोर है लेकिन शायद उनको यह समझना होगा कि जनता ऐसे वादों से ऊपर आकर सोचने लगी है। हालांकि चुनाव में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और सभी पार्टियां मतदाताओं को बरगलाने में एड़ी-चोटी का जोर भी लगा रही हैं और अब देखना यह होगा कि किस्मत किस पार्टी की चमकेगी।

(लेखक राजनीतिक समीक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

## दो टूक
आचार्य श्रीहरि

# डब्ल्यूएचओ ने खुद खोदी अपनी कब्र

विश्व स्वास्थ्य संगठन पर डोनाल्ड ट्रम्प की मार पड़ी है। ट्रम्प ने डब्ल्यूएचओ को अनाथ बना दिया, हाशिये पर खड़ा कर दिया, बेमौत मरने के लिए चौराहे पर छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रम्प के शब्द बहुत कड़े हैं और काफी मारक क्षमता वाले हैं। उन्होंने कहा कि मै डब्ल्यूएचओ को सजा दे रहा हूं, उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा और वह हाशिये पर खड़ा होकर बेमौत मरेगा। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग हो गया। अमेरिका के अलग होने से डब्ल्यूएचओ एक तरह से अपंग हो जाएगा, उसके कई कार्यक्रमों और योजनाओं पर विराम लग जाएगा। उसकी भूखमरी से उत्पन्न बीमारियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियानों की कटौती होगी और कमजोर भी होगा। चीन की तरफदारी कर और चीन के गुनाहों के प्रति आंख मूंद कर डब्ल्यूएचओ ने अपनी कब्र खोद खोदी है। गुनहगारों के प्रति सहानुभूति रखना या फिर उसके प्रति हमदर्दी रखना हमेशा आत्मघाती होता है और अपनी क्रब्र खोदने जैसा ही होता है। इस विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्भरता अमेरिका पर कुछ ज्यादा ही थी। डब्ल्यूएचओ का अठारह प्रतिशत से अधिक दानकर्ता अमेरिका ही था। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ को अमेरिका तकनीकी सहित अन्य सहयोग भी करता था। अमेरिका के इस निर्णय से उसके मित्र देश भी इसी तरह के प्रतिबंधित और आघात वाले कदम उठा सकते हैं और डब्ल्यूएचओ से अपना पींड छुड़ा सकते हैं। डब्ल्यूएचओ की अपनी कुछ कमजोरियां ऐसी हैं कि जिससे वह हाथी का सफेद दांत बन गया है। चीन और रूस जैसे बड़े देशों का मोहरा बन गया है, बीमारियों से लड़ने और बीमारियों के खिलाफ सशक्त अभियान चलाने में डब्ल्यूएचओ जरूर विफल रहा है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी दुनिया को सिर्फ बीमारियों के डर को दिखाने और उसके नाम पर मनोरंजन करने में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। कोरोना काल इसका उदाहरण है। जब कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुनियाभर में लाखों मौतें हुई तो फिर डब्ल्यूएचओ सिर्फ कागजी शेर ही दिखाई दिया। उसके पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई योजना नहीं थी और न ही उसकी तैयारियां ऐसी थी कि जिससे गरीब देशों को कोरोना बीमारी से राहत मिलती। अपनी अर्थव्यवस्था को बलिदान कर दुनिया के देश इस कागजी शेर को क्यों गतिशील रखने के काम करें? विचारण के विषय यही हैं। ट्रम्प की डब्ल्यूएचओ से दुश्मनी कोरोना काल की है। ट्रम्प की चार साल पूर्व हुई हार के पीछे डब्ल्यूएचओ को माना गया है। कोरोना संकट के दौरान ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और जनता के बीच कोरोना को लेकर गुस्सा था और उस गुस्से के शिकार डोनाल्ड ट्रम्प हुए थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि कोरोना चाइनिज वायरस है। चीन ने अमेरिका और यूरोप को तबाह करने के लिए कोरोना वायरस छोड़ा है। तथ्य भी यही था कि कोरोना बीमारी चीन से बाहर की दुनिया में गयी थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन पर कोरोना वायरस फैलाने के सरेआम आरोप लगाये थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि चीन को अपनी करतूत के कारण जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दुनिया भर में जो संहार हुआ है, जो क्षति हुई है उसकी सजा चीन को मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प ने डब्ल्यूएचओ से चीन की जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा था। डब्ल्यूएचओ ने यह भी नहीं माना था कि कोरोना बीमारी का वायरस चीन की करतूत है। जबकि चीन से नहीं तो यह बीमारी कहां से आयी थी? यह तय करने और या फिर खोज करने में डब्ल्यूएचओ विफल रहा था। एक प्रश्न यह भी उठा था कि डब्ल्यूएचओ के पास इतना संसाधन होने और इतनी स्वास्थ्य शक्तियां होने के बावजूद वह असहाय क्यों रहा? जबकि इस संगठन के पास हजारों स्वास्थ्य वैज्ञानिक और कर्मचारी हैं, जिनका प्रथम कार्य ही बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाना और रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाना था। डब्ल्यूएचओ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता जरूरी है। डब्ल्यूएचओ ने अपने बयान में खुद यह माना है कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विशेष स्थान रखता है। चीन की तरफदारी कर, चीन के प्रति आंख मूंद कर डब्ल्यूएचओ ने अपनी कब्र खुद खोदी है। चीन के लिए मानवाधिकार और मानवता कोई अर्थ नहीं रखता है। चीन एक तानाशाही वाला देश है और उसकी नीतियां लूटो और राज करो वाली है। चीन के फेर में पड़कर कई अफ्रीकी देश, श्रीलंका और पाकिस्तान भी कंगाल हो गये। अमेरिका की तरह चीन कभी भी डब्ल्यूएचओ की सहायता नहीं करेगा। फिर डब्ल्यूएचओ के एचआईवी, मलेरिया और तपेदिक जैसी दर्जनों बीमारियों के खिलाफ चलने वाले अभियान कैसे चलेंगे, यह सोचने वाला विषय है?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

# जीवन का प्रथम अनुबंध किसको माना है?

संकलित
## दर्शन

अनुबंध चतुष्टय में 'अधिकारी' को प्रथम अनुबंध स्वीकार किया गया है। मानव की आध्यात्मिक और लौकिक यात्रा के निर्विघ्न संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोक में इसके लिए योग्यता या पात्रता पद का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है, किसी कार्य के निष्पादनार्थ पात्रता प्राप्त करना।सामान्यतः प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र नहीं होता। इसलिए अनधिकारी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सफल और लोकमंगलकारी हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु अधिकारी (पात्र) व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सफल भी होता है और लोकमंगलकारी भी। इसलिए अधिकारी आत्मिक और जागतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव जीवन का प्रथम अनुबंध है। इसीलिए इसे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। वेदांत में अधिकारी को परिभाषित करते हुए कहा गया-जिसने विधिवत ज्ञान प्राप्त कर काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है। नित्य, नैमित्तिक और उपासनादि कर्म करने से जिसकी बुद्धि परिष्कृत और अंतःकरण निर्मल हो चुका है, ऐसा पापरहित व्यक्ति ही विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी है। विश्वामित्र आदि ऋषियों ने अधिकारी समझकर ही राम को विविध आयुध प्रदान किए, जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके। जैसे अधिकारी व्यक्ति का ज्ञान लोकमंगल के लिए होता है, उसी प्रकार अधिकारी को प्रदान की गईं शक्तियां समाज, देश और मानवता की रक्षा के लिए होती हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी अनधिकारी को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका दुरुपयोग ही हुआ है।

# सुदर्शन रूप में भक्त की प्रेत से रक्षा

संकलित
## प्रेरणा

संत अनंतकृष्ण बाबा जी के पास एक लड़का सत्संग सुनने के लिए आया करता था। संत से प्रभावित होकर बालक द्वारा दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर बाबा जी ने कहा कि महामंत्र का 11 लाख जप करके आओ उसके बाद विचार करेंगे। लगभग कुछ महीनों के पश्चात जप की संख्या पूरी करने के बाद वह बाबा के पास पुनः आया। बाबा ने बालक को कहा 11 लाख और जप करके आना। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे साधक जीवन में प्रवेश किए हुए, उसके मन में श्रद्धा की कमी होने लगी । वह एक दिन कहीं जा रहा था रास्ते में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक ने उससे अपने बारे में पूछा, उसने अपनी उपासना के बारे में बताया । तांत्रिक ने पूछा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो, साधना करते हो उससे तुम्हे कुछ अनुभुति हुई? हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सब काम प्रेत कर दिया करेगा, बालक ने तांत्रिक से साधन की विधि जानी और शीघ्र ही थोडे मंत्रो के जप से ही सिद्ध प्राप्ति कर ली। उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध हुआ नहीं। तांत्रिक ने कहा पुनः प्रयास करो। इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर पूछा कि तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते हो? उस प्रेत ने कहा मैं तो जैसे ही इसके थोड़े निकट जाता हूं, इसके पीछे एक सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नही सकता। अवश्य ही कोई शक्ति इसकी रक्षा करती है।

## अंतर्मन

## आज की पाती

### आत्महत्याएं करते छात्र चिंता का विषय

वैसे तो इस दौर में पूरी युवा पीढ़ी ही भयावह मानसिक व्याधि से विचलित है, इनमें विशेषतः छात्र विपलन गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। हमारे देश में प्रति 100 में 15 से अधिक छात्र आत्महत्या से प्रभावित हो रहे हैं। वे अवसाद, चिंता और आत्मघात से पीड़ित पाए जा रहे हैं। कठिन प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई-लिखाई में अनुशासन आदि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। उससे न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों, बल्कि पूरे समाज की चिंता बढ़ती गई है। पारिवारिक दबाव, शैक्षिक तनाव और पढ़ाई में अव्वल आने की महत्वाकांक्षा ने छात्रों के एक बड़े वर्ग को गहरे मानसिक अवसाद में डाल दिया है। अभिभावकों के

## करंट अफेयर

# द. अफ्रीका से श्रद्धालुओं के महाकुंभ आने की उम्मीद

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुम्भ में दक्षिण अफ्रीका से हजारों श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद है। जोहानिस्बर्ग में भारत के महावाणिज्यदूत महेश कुमार ने बुधवार शाम कहा, '13 जनवरी को महाकुम्भ की शुरुआत के बाद से कुछ ही दिनों में उन लोगों के लिए सौ से ज्यादा वीजा जारी किए जा चुके हैं जो इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं और कई लोगों ने इसमें शामिल होने के लिए अपने प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) कार्ड का इस्तेमाल किया है।' कुमार 'महाकुंभ 2025- वेयर स्पिरिचुएलिटी मीट्स टेक्निकल इनोवेशन' नामक संगोष्ठी की मेजबानी कर रहे थे, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने इस आयोजन के इतिहास और आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डाला। कुमार ने कहा, 'ट्रैवल एजेंट विशेष पैकेज भी तैयार कर रहे हैं, जिससे महाकुम्भ में लोगों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।' उन्होंने कहा, 'महाकुम्भ में शामिल होने के इच्छुक लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और इसी को देखते हुए यह संगोष्ठी आयोजित की गई है।' दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण कार्यकर्ता एवं 'सेव सॉइल मूवमेंट' के नेता रसेके नकादिनेग महाकुम्भ में जाएंगे। उन्होंने कहा, 'इस तरह का अगला महाकुम्भ साल 2169 में होगा।

## ऑफ बीट

# ढीला पायजामा देखते ही आग पकड़ सकता है

ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) ने पिछले साल बच्चों से जुड़े उत्पाद बनाने वाली कुछ कंपनियों के 'नाइटवियर' को बाजार से वापस लेने के लिए कम से कम नौ नोटिस जारी किए, क्योंकि इन कपड़ों में आसानी से आग लगने का जोखिम था, लेकिन कंपनियों ने इन पर आवश्यक चेतावनी संदेश नहीं प्रकाशित किए थे। सबसे ताजा नोटिस ई-कॉमर्स वेबसाइट टेमू पर उपलब्ध अंधेरे में चमकने वाली एक टी-शर्ट के संबंध में जारी किया गया था। दरअसल, क्वींसलैंड में आठ साल की एक बच्ची उस समय बुरी तरह से झुलस गई, जब हवा से फैली चिंगारी उसकी इस टी-शर्ट पर गिरी और देखते ही देखते इसने आग पकड़ ली। इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया में उत्पादों से जुड़े सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियों को उजागर किया है। हालांकि, ज्यादातर कंपनियां कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए चेतावनी संदेश तो प्रकाशित करती हैं, लेकिन वे इन खतरनाक ज्वलनशील कपड़ों का उत्पादन और बिक्री नहीं रोकतीं। इससे सुरक्षा का सारा दारोमदार खरीदारों पर आ जाता है, जो चेतावनी संदेश वाले उत्पाद तो खरीद लेते हैं, लेकिन इसके (चेतावनी) मायने नहीं समझ पाते।

## ट्रेंड

### क्रिकेट टीम को बधाई

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ उनकी शानदार जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। अभिषेक शर्मा की दमदार पारी मैच का असली आकर्षण थी। उनके आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं, और वे अपनी जीत की लय जारी रखें।
-जे.पी. नड्डा, भाजपा अध्यक्ष

### नेताजी को कोटि-कोटि नमन

'नेताजी' सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व ने आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी थी, आज उनकी पावन जयंती 'पराक्रम दिवस' पर लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हे श्रद्धांजलि दी। 'नेताजी' को कोटि-कोटि नमन!
-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

### ट्रेन हादसे से व्यथित हूं

महाराष्ट्र के जलगांव में हुए भीषण ट्रेन हादसे की खबर बेहद दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करें कि घायलों का बेहतर इलाज हो।
-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

### गंगा स्नान से जीवन सफल

महाकुंभ में गंगा स्नान करके जीवन सफल हुआ। पहली बार उस स्थान पर पहुंच कर मंत्र उच्चारण किए जहां मां गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। सनातन धर्म की जय।
-अनुपम खेर, अभिनेता

## अपने विचार

हरिभूमि कायार्लय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 24 जनवरी 2025

# जीवन की गरिमा

**असम में** विदेशी नागरिकों को लंबे समय से डिटेंशन सेंटर में रखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी कई लिहाज से अहम है। इस मामले में राज्य सरकार का जो रुख सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि वह इन विदेशी नागरिकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को लेकर पर्याप्त गंभीर नहीं है।

**अधिकारों का सवाल** | सुप्रीम कोर्ट के पास आए इसी मामले की बात करें तो 270 लोगों को असम के डिटेंशन सेंटर्स और ट्रांजिट कैंपों में लंबे समय से रखा जा रहा है। अदालत के सामने आए तथ्यों के मुताबिक, इनमें से कुछ लोगों को तो वहां रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। स्वाभाविक ही सवाल उठता है कि आखिर इन्हें वहां क्यों रखा गया है और इन्हें इनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। उसमें इतनी देर क्यों हो रही है?

AI Image

अवैध घुसपैठियों का मामला

**जवाब में लापरवाही** | हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने में भी राज्य सरकार के अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार का यही कहना था कि ये सब विदेशी हैं और इन्हें फॉरिनर्स ट्राइब्यूनल्स की ओर से विदेशी घोषित कर दिए जाने के बाद ही डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। लेकिन सरकारी हलफनामे में इन्हें हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ना ही यह जानकारी दी गई है कि इन्हें स्वदेश भेजने की दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं।

**घुसपैठियों पर राजनीति** | इस मसले को अगर पिछले कुछ वर्षों में विदेशी घुसपैठियों पर तेज हुई राजनीति के संदर्भ में देखें तो कथित घुसपैठियों के खिलाफ कई गैरजिम्मेदार बयान भी देखने को मिल जाते हैं। इससे किसी कारण भारत में रह रहे विदेशियों के खिलाफ नफरत का माहौल बनता है और यह सवाल भी उठता है कि क्या सरकारी अधिकारियों के व्यवहार या फैसले पर उस माहौल का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है।

**संविधान की गारंटी** | शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेखांकित करना जरूरी समझा कि देश के संविधान की ओर से दिए गए जीवन के अधिकार की गारंटी यहां रह रहे सभी लोगों के लिए है चाहे वे विदेशी ही क्यों न हों। अवैध तौर पर देश में घुस आए लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर की जाए, लेकिन इस क्रम में उनके जीवन की गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए।

## रोज़-ब-रोज़

# कुंभ में 'मोनालिसा'

शैलेंद्र पांडेय

**लिओनार्दो द** विंची की मोनालिसा क्यों मुस्कुरा रही है, पांच सदी बाद भी यह सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन कुंभ में ब्लॉगर्स ने एक नई मोनालिस तलाश ली और वहां उसकी मुस्कान और आंखों की चमक को डिकोड करने की कोशिशें जारी हैं। इतनी होड़ मची है इसके लिए कि सुनने में आया, माला बेचने वाली मोनालिसा को उसके पिता ने वापस घर भेज दिया। लेकिन, अब बात करने के लिए मोनालिसा की बहन मिल गई है।

इसी तरह की डिकोडिंग चल रही है साधु-संतों के मामले में। कबीरदास कह गए हैं कि साधु कहावन कठिन है। उन्होंने तो चेताया भी है कि निश्चल रहने वाला ही इस सफर में सफल हो सकता है, वरना गिर पड़ेंगे। लेकिन, बात वही है कि लिओनार्दो की तरह उनके दौर में भी स्मार्टफोन तो थे नहीं। कुंभ समागम है साधु-संतों का, लेकिन फोन के कैमरों को ऐसे साधु-संत चाहिए, जो मोनालिसा की पेंटिंग की तरह रहस्यमयी हों। रहस्य है नहीं तो गढ़ा जा रहा। मदद के लिए AI टूल हैं ही। तो कभी IIT वाले बाबा निकल कर आ जा रहे हैं, कभी बाल बाबा और कुछ नहीं तो कोई बिल्ली ही म्याऊं-म्याऊं करती ट्रेंड करने लग रही है।

डिजिटल दुनिया में चल रहा कुंभ अलग है बिल्कुल। ब्रैंडिंग ऐसी है कि हर कदम पर चमत्कार दिख रहा है। एमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि जब आप कमरे में नहीं होते और लोग आपके बारे में बातें करते हैं, वही आपका ब्रैंड है। तो हो अब यह रहा है कि अपने-अपने ब्रैंड गढ़ने की कोशिशें हो रही हैं, जिनके बारे में डिजिटल रूम में बातें होती ही रहें। लेकिन इसका फायदा क्या है सिवाय वायरल होने के? कुछ भी नहीं। फिर भी यह लगातार हो रहा है। पिछले साल इसी वक्त यह अयोध्या में हुआ था, उसके बाद केदारनाथ और बदरीनाथ में हुआ। मूल बात छोड़कर डिजिटल वर्ल्ड सारी इधर-उधर की बातों पर फोकस बनाने में तुला था। इसी डिजिटल दुनिया में एक विडियो देखने को मिला, जिसमें चिमटा लेकर एक बाबा मोबाइल थामे एक युवक के पीछे पड़े हैं। उन्हें बेकार के सवाल पसंद नहीं। यही बात कई विडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, बस बनाने वाले किसी तरह से उन्हें सुन लें।

## एकदा

# क्लीवलैंड की सहजता

**19वीं सदी** का आखिरी दौर था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड थे। उस दिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि यात्रियों का दम घुट रहा था। उसी ट्रेन में अमेरिका के साहित्यकार रिचर्ड गिल्डर भी थे। वह भीड़ और घुटन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका जाना भी जरूरी था। सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी उन्हें ख्याल आया कि राष्ट्रपति क्लीवलैंड भी उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। क्लीवलैंड लेखक गिल्डर का बहुत सम्मान करते थे। गिल्डर ने सोचा कि 'बस, अब काम बन गया। राष्ट्रपति के पास बैठकर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सफर भी आराम से कट जाएगा और कुछ बातें भी हो जाएंगी।' गिल्डर पूरी गाड़ी का चक्कर लगा आए। जब क्लीवलैंड नहीं दिखे तो उन्होंने गार्ड से पूछा, 'राष्ट्रपति महोदय कहां बैठे हैं?' गार्ड उन्हें सामान रखने वाले एक डिब्बे के पास ले गया और बताया, 'वह बैठे हैं हमारे राष्ट्रपति।' गिल्डर के मनोभावों को पढ़कर राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने कहा, 'अरे मित्र, आज भीड़ बहुत है। इस महिला के साथ छोटा बच्चा भी है। इनके पास बैठने के लिए स्थान नहीं था, तो अपनी सीट इन्हें दे दी और मजे से इस पेटी पर बैठा हूं।' गिल्डर सच्ची मानवता के इस अभूतपूर्व दृश्य को अपने हृदय में कहीं गहरे अंकित करते हुए राष्ट्रपति क्लीवलैंड की सहजता पर मुग्ध हो रहे थे।

Subrata Dhar

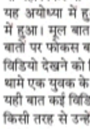

संकलन : ललित गर्ग

अपनी दूसरी पारी में डॉनल्ड ट्रंप अधिक आक्रामक हैं और उनके सपने पहले से बड़े

# ट्रंप के मेगा शो पर मोहित है अमेरिका

मनीष गुप्ता, न्यूयॉर्क से

**अमेरिका में** ऐसा यूफोरिया पिछली बार साल 1984 में देखने को मिला था। तब रॉनल्ड रीगन ने राष्ट्रपति चुनाव में वॉल्टर मोंडेल को हराकर इतिहास रचा था। रीगन ने 50 में से 49 राज्यों में जीत हासिल की थी और 'आमूलचूल परिवर्तन' का वादा किया था। लेकिन, सत्ता में आते ही साफ हो गया कि केवल बहुमत के दम पर बदलाव लाना आसान नहीं है। खुद की रिपब्लिकन पार्टी में पुराने घाघ नेताओं, मठाधीशों की राजनीति और पार्टी के तंत्र को बदलना रीगन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

**अलग कहानी** | अब चार दशक बाद ऐसा लगता है, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। हालांकि इस बार कहानी कुछ अलग है। यह रिपब्लिकन पार्टी का नहीं, ट्रंप का राज है। बतौर राष्ट्रपति अपनी पहली पारी में ट्रंप की टीम कमजोर थी, वह खुद भी वॉशिंगटन के तौर-तरीकों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। लेकिन, इस बार के डॉनल्ड ट्रंप पिछले वाले ट्रंप के सुपर अवतार हैं।

**वफादारों की टीम** | ट्रंप की टीम ट्रंप loyalist पहले है, पार्टी के प्रति वफादारी तो बाद में आती है। रिपब्लिकन पार्टी में किसी की मजाल नहीं कि कुछ कह सके। जो पद पहले पार्टी के दूसरी पायदान पर आने वाले नेताओं को मिलते थे, अब बाहर बंट चुके हैं और ये मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।

**शोमैन फिर मंच पर** | शपथ ग्रहण के पहले ही दिन ट्रंप ने अपनी शैली के अनुरूप 'शोमैनशिप' का प्रदर्शन किया। उन्होंने पारंपरिक रूप से वाइट हाउस में आयोजित होने वाले हस्ताक्षर समारोह को बदलते हुए, वॉशिंगटन डी.सी. के कैपिटल वन एरिना में पब्लिक स्टेज पर बैठकर समर्थकों के सामने कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। आलोचक हैरान हैं, समर्थक उत्साहित।

**सुपर अवतार**

- राष्ट्रपति की टीम में ट्रंप loyalists
- दूसरे रिपब्लिकन नेता किनारे किए गए
- वॉशिंगटन में टेक अरबपतियों की पैठ

**धड़ाधड़ आदेश** | इस असाधारण कदम के तहत ट्रंप ने लगभग 200 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 78 उनके पूर्ववर्ती जो बाइडन के आदेशों को निरस्त करने से संबंधित थे। इन आदेशों में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकालना, दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और संघीय कर्मचारियों के लिए टेलीवर्क नीतियों को समाप्त करना शामिल था।

**इतिहास पर नजर** | राष्ट्रपति पद पर ट्रंप के पहले दिन की सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मंच पर आते ही 'सुनहरे अमेरिका' का वादा दोहराया। 'ट्रंप युग' केवल आने वाले चार बरसों को ही नहीं देख रहा है, वह इतिहास में अपनी जगह बनाना चाहते हैं।

**जनता को संदेश** | ट्रंप प्रशासन के दूसरे दिन की गतिविधियां इतनी जोरदार रहीं कि वॉशिंगटन की गलियों तक में हलचल महसूस की गई। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ट्रंप ने टीवी स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। ऐसा लगा जैसे वह पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हों कि 'अमेरिका जाग गया है।'

**विरोधियों पर निशाना** | इससे पहले, बाइडन प्रशासन के वाइट हाउस में अक्सर एक खामोशी और ठंडक छाई रहती थी। ट्रंप ने आलोचकों पर व्यंग्य करते हुए कहा, 'वाइट हाउस अमेरिका की नई गति का प्रतीक बनेगा, न कि सुस्ती का स्मारक।'

**नया युग, नई परिभाषा** | अमेरिका में एक नया शब्द ट्रेंड कर रहा है, Broligarchy। यह शब्द ट्रंप युग के लिए बिल्कुल सटीक लगता है। जहां रूस में व्लादिमीर पूतिन ने अपने ओलिगार्क्स बनाए थे, वहीं ट्रंप ने अमेरिका के टेक अरबपतियों को एक नया मंच दिया है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, सैम ऑल्टमैन - सब वॉशिंगटन में नियमित रूप से देखे जा रहे हैं।

**उम्मीद का नया दौर** | डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फिर से 'गोल्डन ऐज' की उम्मीद जगाई है। गालिब के शब्दों में, 'हम को उन से वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है।' उनके आलोचक चाहे जितनी भी शंकाएं उठाएं, यह कहना मुश्किल है कि जनता में उत्साह नहीं है।

**बड़ा और आक्रामक सपना** | चार दशक पहले रीगन ने अमेरिका को 'शाइनिंग सिटी ऑन अ हिल' का सपना दिखाया था। ट्रंप का सपना शायद उससे भी बड़ा और ज्यादा आक्रामक है। अब देखना है कि यह 'गोल्डन ऐज' इतिहास में एक चमकदार अध्याय बनता है या फिर अधूरे वादों की कहानी। लेकिन फिलहाल, शो जारी है।

*(लेखक फिल्मकार, कॉलमनिस्ट और राइटर हैं)*

# क्या हमारी देह में दौड़ रहा तारों का कार्बन

मुकुल व्यास

**कार्बन** हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सभी कार्बनिक अणुओं की रीढ़ है, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और DNA जैसी चीजें शामिल हैं। कार्बन के अणु ऊर्जा ले जाने से लेकर कोशिकाओं के निर्माण तक शरीर के हर काम के लिए जरूरी हैं। लेकिन यह कार्बन आया कहां से? वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन के परमाणु तारों की भट्ठियों में बने और आकाशगंगाओं में लंबा चक्कर काटने के बाद हमारे शरीर का हिस्सा बने।

**ब्रह्मांडीय सैलानी** | कार्बन के इन परमाणुओं को हम ब्रह्मांडीय सैलानी भी कह सकते हैं। अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने कार्बन की इस ब्रह्मांडीय यात्रा के बारे में उल्लेखनीय खोज की है। उनका कहना है कि ये कार्बन एक विशाल रीसाइक्लिंग सिस्टम का हिस्सा हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की तारा-निर्माण फैक्ट्रियों को चालू रखता है। उनके निष्कर्ष इस बात पर नई रोशनी डालते हैं कि हमारी मिल्की-वे जैसी आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय सर्कुलेशन की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से नए तारे बनाने की अपनी क्षमता को कैसे बनाए रखती हैं। हमारे जैसे ग्रह इन तारा-निर्मित परमाणुओं को उनकी संरचना में शामिल करके बनाए जाते हैं। चाहे पृथ्वी के कोर का लोहा हो, वायुमंडल की ऑक्सिजन हो या हममें मौजूद कार्बन, ये सभी तत्व तारों की भट्ठियों में बने हैं।

**कच्चे-पक्के तारे** | वैज्ञानिकों का कहना है कि तारों की फैक्ट्री में बने परमाणु अपनी उत्पत्ति की आकाशगंगा का चक्कर विशाल ब्रह्मांडीय धाराओं पर लगाते हैं, जो आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष में फैलती हैं। वैज्ञानिक इन धाराओं को 'सर्कमगैलेक्टिक मीडियम' कहते हैं। ये धाराएं एक विशाल कन्वेयर बेल्ट जैसी होती हैं जो सामग्री को बाहर धकेलती हैं और इसे वापस आकाशगंगा के अंदरूनी हिस्से में खींचती हैं। यहां गुरुत्वाकर्षण और अन्य बल इस कच्चे माल को ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं और यहां तक कि नए तारों में इकट्ठा कर सकते हैं। नए अध्ययन की प्रमुख लेखक समंता गार्जा ने कहा कि इस मीडियम को एक विशाल ट्रेन स्टेशन के रूप में देखा जा सकता है जो लगातार सामग्री को बाहर धकेल रहा है और उसे वापस अंदर खींच रहा है।

AI Image

ज्ञान-विज्ञान

**रीसाइक्लिंग सिस्टम** | यह खोज 2011 की एक सफलता पर आधारित है जब वैज्ञानिकों ने पहली बार पुष्टि की थी कि तारा बनाने वाली आकाशगंगाएं सर्कमगैलेक्टिक मीडियम से घिरी हुई हैं। तब उन्होंने ने इस क्षेत्र में ऑक्सिजन युक्त गर्म गैसें पाई थीं। अब गार्जा की टीम ने दिखाया है कि ठंडी सामग्री, विशेष रूप से कार्बन भी इस ब्रह्मांडीय रीसाइक्लिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। गार्जा ने कहा कि यह मीडियम कार्बन और ऑक्सिजन दोनों के लिए एक विशाल भंडार की तरह काम करता है।

**विशालकाय व्यास** | इस सिस्टम का पैमाना दिमाग हिला देने वाला है। हबल स्पेस टेलीस्कोप पर कॉस्मिक ओरिजिन स्पेक्ट्रोग्राफ से टीम ने अंतरिक्ष में लगभग 4,00,000 प्रकाश वर्ष तक फैले कार्बन का पता लगाया। विशेषज्ञों ने इस मापन के लिए यह अध्ययन किया कि आकाशगंगाओं के सर्कमगैलेक्टिक मीडियम में कार्बन युक्त सामग्री दूरवर्ती पिंड से आने वाले प्रकाश को किस तरह का प्रभावित करती है। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिल सकती है कि यह रीसाइक्लिंग प्रोसेस कैसे कम होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस चक्र के धीमा होने या रुकने पर क्या होगा, यह सवाल अभी बना हुआ है।

# G20 में PM मोदी ने कहा, जैसे भी हो सदस्य देशों के बीच सहमति बनाइए

2023 में भारत ने G20 की मेजबानी की थी। इसके शेरपा **अमिताभ कांत** थे। हाल ही में पब्लिश हुई अपनी किताब **'How India Scaled Mount G20'** में कांत ने इसके अंदर की कई कहानियां बताई हैं। कैसे नई दिल्ली में डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनाने के लिए किसी को मनाया गया तो किसी को 'धमकाया' गया। अमिताभ कांत से बात की NBT की **पूनम पाण्डे** ने। यहां पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश :

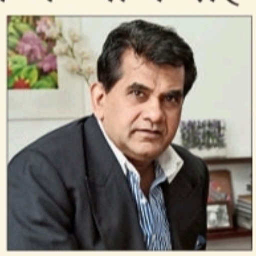

विशुद्ध राजनीति

इंटरव्यू

**■ अपनी किताब में आपने लिखा है कि नई दिल्ली डिक्लरेशन के एक पैरा को लेकर सहमति बनाने में ही 300 घंटे लगे। क्या किसी पॉइंट पर आप लोगों को लगा कि अब तो सहमति बनना नामुमकिन सा हो गया है...**

कई बार ऐसा लगा। जितनी मीडिया विदेश से आई थी, सबको यही लग रहा था कि भारत तो कर ही नहीं पाएगा। रूस-यूक्रेन क्राइसिस अपने पीक पर था। उस सहमति को बनाने में 300 घंटे लगे। 250 द्विपक्षीय बैठकें हुईं। हमारे 16 ड्राफ्ट फेल हुए और 17वां ड्राफ्ट किया। हमने बड़े बोल्ड तरीके से रिस्क लेकर सबसे कहा कि आप ये स्वीकार कीजिए, नहीं तो भारत G20 से चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश था कि अगर G20 के सदस्य देश जिम्मेदारी से मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम क्यों इसके मेंबर रहेंगे। हम जाकर ब्रिक्स के साथ काम करेंगे। यह मुझे कहना पड़ा। बाद में जब रूस इस पर अड़ा था कि सैंक्शन की लाइन जोड़ी जाए, जो कि संभव ही नहीं था क्योंकि इस पर G7 नहीं मानता। तब रूस से कहना पड़ा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वर्चुअली G20 में बोलने दिया जाएगा, तब रूस माना। अमेरिका चाहता था कि रूस और चीन पहले सहमत हों। रूस ने हां कर दिया। इसके बाद चीन को मनाने की बात आई। चीन कह रहा था, ये लाइन हटाएं कि 2026 में G20 अमेरिका होस्ट करेगा। जब लीडरशिप समिट शुरू हुई तो उसके बाद करीब सवा तीन घंटे हमने अलग से चर्चा की।

**■ रूस से नेगोशिएट करना ज्यादा मुश्किल रहा या चीन से?**

कई लोगों की अलग-अलग सब्जेक्ट पर टफ पोजिशन थी। जैसे सऊदी अरब क्लाइमेट पर बहुत टफ था। वह फॉसिल फ्यूल शब्द नहीं लाना चाहता था। चीन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, वसुधैव कुटुंबकम सबका साल भर विरोध करता रहा। उनके शेरपा को समझाना पड़ा कि हम ग्लोबल साउथ देश हैं, हमें साथ काम करना है। रूस भी यूक्रेन के मुद्दे पर बड़ा टफ था। G7 भी बड़ा टफ था। लेकिन जो अच्छी चीज हुई वह यह कि भारत हमेशा ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर काम करता रहा और उनके साथ ही आगे बढ़ा।

**■ नेगोशिएशन डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर चर्चाएं चल रही थीं कि शायद यह मुश्किल है। अंदर लगातार मीटिंग हो रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में?**

प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सहमति बन गई? मैंने कहा नहीं सर, अभी नहीं। मैंने उन्हें बताया कि चीन, रूस क्या कह रहे हैं। एक तरह से फेलियर की स्थिति आ गई थी। प्रधानमंत्री ने बड़े जोर से कहा- मैं प्रॉसेस या प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा। मुझे कंसेंसस लाकर दो। फिर सहमति बनाने में तीन-चार घंटे लगे।

**■ क्या आपको नेगोशिएशन में पूरा फ्रीहैंड मिला था? कहते हैं, आपको कुछ को 'धमकाना' पड़ा, कुछ को मनाना पड़ा...**

प्रधानमंत्री ने मुझे पूरी फ्रीडम दी थी। पीएम ने कहा था कि इंडियन प्रेसिडेंसी एंबिशस हो, इनक्लूसिव हो, डिसाइसिव हो और एक्शन ओरिएंटेड हो। यही कारण है कि हम लोगों ने बोल्डनेस व रिस्कीनेस दिखाई। जब टेंशन बहुत बढ़ी, तब भी हम लोग शांत रहे। यह मैंने एक चैप्टर में लिखा भी है। लीडरशिप इन एक्शन वॉट आई लर्न फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग G20।

## रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

**■ लोकतंत्र के खिलाफ**

यह पत्र 21 जनवरी के संपादकीय 'बयानों पर FIR' से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह फैसला लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखते हुए लिया गया है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्षी नेताओं के बयानों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करना और कानूनी कार्रवाई करना राजनीतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। यह समझ से बाहर है कि किसी नेता के राजनीतिक बयान को कानूनी प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाए। राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप आम बात है।

**वारिस अली खान,** ईमेल से

**■ खुल रहे हैं नए अवसर**

**अमेरिका द्वारा** पाकिस्तान का गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा समाप्त किए जाने और आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाने के आसार दिख रहे हैं जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। सीमा पार आतंकवाद पर अंकुश लगना भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। उधर चीन को लेकर भी नए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का रुख कड़ा होता दिख रहा है। यह स्थिति भारत के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। सरकार आर्थिक सुधारों का क्रम जारी रखे तो भारतीय उद्योग जगत वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है। भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता उसे वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। ट्रंप प्रशासन की नीतियां भारत के लिए कुशल मानवशक्ति और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में भी नए अवसर खोल सकती हैं। इन अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए।

**आर.के. जैन,** ईमेल से

**nbtedit@timesofindia.com** पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

### अंतिम पत्र

**मणिपुर में** BJP का साथ छोड़ा, JDU नेता की छुट्टी – एक खबर

– JDU में पलटी मारने का अधिकार बस एक नेता के पास है।

**शिल्पी यादव**

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

# गुरु के नज़दीक जाने का आसान रास्ता है श्रद्धा

आनंदमूर्ति गुरुमां

**मंत्र वह** ध्वनि है, जो मन को तरंगित और एकाग्र करती है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसकी ध्वनि तरंगों का हमारे शरीर और मन पर गहरा असर पड़ता है। ये ताकतवर तरंगें न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी संतुलन को भी प्रभावित करती हैं। जैसे अगर किडनी या ब्लैडर में पथरी हो तो सर्जन Lithotripsy तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ध्वनि तरंगों से पथरी को तोड़कर उसे मूत्र के जरिए बाहर किया जाता है। यह दिखाता है कि विशिष्ट शक्तियों वाली ध्वनि तरंगें हमारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।

मंत्रों में इस्तेमाल होने वाले संस्कृत के शब्द बिना उद्देश्य के नहीं होते। इनका चुनाव हमारे प्राचीन ऋषियों के आंतरिक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। मंत्रों के रूप में ये शक्तिशाली ध्वनि तरंगें हमें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर अग्रसर करती हैं। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप इन तरंगों के जरिए एक विशेष वातावरण का निर्माण करते हैं, जो आपके शरीर, मस्तिष्क और मन पर मंत्र की शक्ति का गहरा प्रभाव डालता है।

गुरु से प्राप्त मंत्र का प्रभाव अन्य किसी मंत्र से भिन्न होता है। मंत्र वही होता है, लेकिन जब वह गुरु से प्राप्त होता है, तो उसकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। मंत्र वैज्ञानिक यंत्र के समान काम करते हैं जब गुरु का प्रभाव उसमें जुड़ जाता है। गुरु की शक्ति और आशीर्वाद उन शब्दों में समाहित हो जाते हैं, जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ गुरु से प्राप्त मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसकी शक्ति आपके शरीर और मन में बदलाव लाती है। यह परिवर्तन आपके तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव डालते हैं, जिसे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सिद्ध किया गया है।

मंत्र का अभ्यास करने के लिए सही आसन की आवश्यकता होती है। जब हम नाभि, हृदय और भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र जाप करते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। शरीर की मुद्रा को सही रखना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सजग और सचेत बनाता है। मानसिक समर्पण और ध्यान के साथ मंत्र का अभ्यास करने से समय का अनुभव नहीं होता। यह सुख और शांति की अनुभूति प्रदान करता है, जैसे किसी को कोई मीठा स्वाद या मदिरा का अनुभव होता है। जब आप इस आत्मरस रूपी मदिरा का स्वाद लेते हैं, तो आप स्वयं को शांति और आनंद से भरपूर महसूस करते हैं। इसलिए मंत्र का अभ्यास न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आपको आत्म-संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनाता है।

हममें से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आंखों से नहीं दिखने वाले माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के कण कैसे चुपके से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्लास्टिक के इन कणों का सेहत पर कई स्तर पर असर पड़ सकता है। कैसे करें अपना बचाव, जानें **शमीम खान** से

# सेहत पर बढ़ता प्लास्टिक का दखल

आज पानी से लेकर कटी हुई सब्जियां, बिस्किट, सूखे मेवे, नमकीन आदि सैकड़ों चीजें पॉलीथीन और प्लास्टिक की पैकिंग में मिल रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्लास्टिक जीवन चक्र के हर चरण (उत्पादन, इस्तेमाल, रिसाइकिल, डिस्पोजेबल) में मानव सेहत के लिए खतरा छिपा है। मई 2023 में जेनेवा में हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्लास्टिक के मानव सेहत पर बढ़ते खतरे पर विस्तार से चर्चा की गई और कहा गया कि हर इनसान प्रति सप्ताह औसतन 5 ग्राम प्लास्टिक निगल रहा है।

## प्लास्टिक और हमारी सेहत

वैज्ञानिकों का दावा है कि प्लास्टिक बनाने के लिए लगभग 13,000 प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से ज्यादातर सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक पाए गए हैं। ऐसे रसायन जो बांझपन, मोटापा, मधुमेह, कैंसर, थायरॉयड, फेफड़े खराब होना, मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हो जाना जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ा देते हैं। प्लास्टिक के कुछ प्रकारों में बिस्फेनॉल-ए नामक रसायन का इस्तेमाल हो रहा है, जो भोजन या पानी के साथ रिस कर शरीर में पहुंच रहा है, यह कैंसर कारक माना जा रहा है।

## शरीर में कैसे प्रवेश करता है

**सांस द्वारा :** प्रदूषित हवा में सांस लेने से प्लास्टिक के सूक्ष्म कण फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। 2019 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया कि वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में 42 लाख असामयिक मौतें हुईं, अपशिष्ट प्रबंधन ठीक तरह से न करना इसका एक प्रमुख कारक था। द यूनाइटेड नेशंस एन्वायरन्मेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 85 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन ढंग से नहीं होता।

**खानपान :** हम जो खा रहे हैं, चाहे वो शाकाहार हो या मांसाहार, उसके साथ प्लास्टिक के कण भी निकल रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 90 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल नहीं किया जाता है, इसे लैंडफिल में भेज दिया जाता है, जला दिया जाता है या पर्यावरण में फेंक दिया जाता है। इससे हमारी मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती है और प्लास्टिक खाद्य शृंखला में भी शामिल हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 60 प्रतिशत समुद्री जीवों के पेट में प्लास्टिक है, 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 99 प्रतिशत हो जाएगा। सी-फूड्स खाने से यह प्लास्टिक के कण हमारे पेट में आ जाते हैं। इसी तरह फल व सब्जियां भी अपनी जड़ों के जरिये माइक्रोप्लास्टिक सोख लेती हैं। और प्लास्टिक कण पाचन तंत्र में चले जाते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को माना है कि सभी तरह के प्लास्टिक एक वक्त के बाद रसायन छोड़ने लगते हैं, खासकर, जिन्हें गर्म किया जाता है।

**पैकेजिंग :** विश्वभर में पैकेजिंग में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, उसमें 39 फीसदी हिस्सा प्लास्टिक का है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि सूरज की रोशनी और तापमान में बढ़ोतरी के कारण माइक्रोप्लास्टिक के कण खाद्य पदार्थों में चिपक सकते हैं। गर्म भोजन को प्लास्टिक के टिफिनों और कंटेनरों में डालने से प्लास्टिक में मौजूद रसायन भोजन में मिल सकते हैं। कटे फल, सब्जियां व अंकुरित खाद्य पदार्थ प्लास्टिक में पैक करने से प्लास्टिक कणों के एक्सपोजर की आशंका बढ़ जाती है।

## माइक्रो और नैनो प्लास्टिक

प्लास्टिक के कण जिनका आकार पांच मिलीमीटर (एक इंच का 1/4) से लेकर 1 माइक्रोमीटर (एक मीटर का दस लाखवां भाग) तक होता है, उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक हवा, पानी, मिट्टी हर जगह होते हैं। ये नॉन-बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए वातावरण को प्रदूषित करते हैं।

जो कण 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, उन्हें नैनोप्लास्टिक माना जाता है। यह कण आंत व फेफड़ों से होते हुए रक्त प्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। वहां से ये हृदय की मांसपेशियों व अन्य अंगों में जा सकते हैं, दिमाग के अलावा प्लेसेंटा को पार करके अजन्मे शिशुओं के शरीर में भी जा सकते हैं।

एन ओवरलुक्ड सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन ह्यूमन फूड नाम से हुए अध्ययन के अनुसार प्लास्टिक के कटिंग/चॉपिंग बोर्ड को एक बार 30 मिनट तक इस्तेमाल करने से एक हजार से अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण निकलते हैं, जो सब्जियों में मिलकर शरीर में जा सकते हैं।

**ब्लैक प्लास्टिक :** आजकल रंग-बिरंगे, खासकर काले रंग के प्लास्टिक बर्तनों का क्रेज है। यूके के हेरियॉट वाट यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार ब्लैक प्लास्टिक में मौजूद कुछ तत्व हार्मोन असंतुलन व न्यूरो-लॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बन सकते हैं। छोटे बच्चों में इनका अधिक एक्सपोजर मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है।

**हमारे विशेषज्ञ:** डॉ. अनुकल्प प्रकाश, प्रमुख सलाहकार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सीके बिड़ला हॉस्पिटल, गुरुग्राम।
डॉ. सुनील सेखरी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम

**2020** में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हल में हुए एक अध्ययन में पहली बार अजन्मे बच्चों के प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए थे।

**2023** में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्लास्टिक का एक्सपोजर जन्मजात विकलांगता का कारण बन सकता है।

- प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में हाल में छपे अध्ययन के अनुसार बाजार में बिकने वाली एक लीटर पानी की बोतल में 105 माइक्रो-प्लास्टिक के कण हो सकते हैं।
- फ्रांस में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप-प्लेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तेज धूप और गर्मी में प्लास्टिक बोतलों से रसायन पेय पदार्थ में मिल सकते हैं।

### मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक कहां तक पहुंच सकता है

सांस के द्वारा माइक्रो और नैनोप्लास्टिक शरीर में प्रवेश करने के बाद पूरे शरीर में फैलने लगते हैं और आकार के आधार पर विभिन्न हिस्सों में जमा हो सकते है

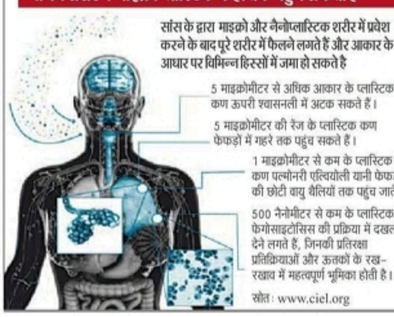


स्रोत : www.ciel.org

### बचाव के कुछ उपाय

- रसोई में कांच या स्टेनलेस स्टील के डिब्बे इस्तेमाल करें।
- प्लास्टिक की बजाय लकड़ी के ब्रश, कंघी और नेचुरल स्क्रबर्स का इस्तेमाल करें।
- शॉपिंग के लिए कपड़े के बैग बेहतर हैं।
- कचरे को पेपर बैग या कंटेनर में रखें। कागज के बैग या कपड़े वाले झोले का इस्तेमाल करें।
- दुकानों या ऑफिसों में छोटी पॉलिथीन की थैलियों में गर्म चाय न मंगवाएं।
- माइक्रोवेव में कांच, पाइरेक्स या चीनी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें।
- बोतल, लंच बॉक्स या स्टोरेज कंटेनर के तौर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें।
- प्लास्टिक कंटेनर गैस के पास न रखें।
- गर्म खाना व चाय आदि निकालने के लिए प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल न करें। एक समय उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें।

# साइनस संक्रमण से हो सकता है सिरदर्द

डॉ. विपुल पांडेय
वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर, डॉ. बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल, रोहिणी, दिल्ली

- **मेरी उम्र 45 साल है। मुझे पिछले 20 साल से अस्थमा है। बीते कुछ माह से जल्दी-जल्दी सिरदर्द, जुकाम और खांसी रहती है। ऐसा क्यों होता है? मुझे क्या करना चाहिए?**

यह एलर्जिक समस्या है। जब शरीर में एलर्जी सक्रिय होती है, तब इंफ्लेमेशन व अन्य दूसरे संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। जल्दी-जल्दी सिर दर्द, जुकाम और खंसी का होना साइनस के संक्रमण की ओर इशारा करता है। इसकी पुष्टि के लिए कुछ जांच करानी होगी। बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। क्लीनिकल जांच के बाद वे आपको जरूरी टेस्ट व दवाओं के बारे में बताएंगे।

- **मेरी उम्र 38 साल है। लगातार खांसी और जुकाम रहता है। सांस फूलने लगती है। सांस लेते समय सीटी की सी आवाज आती है। इस समस्या को आठ महीने के करीब हो गए हैं। मुझे किस डॉक्टर से मिलना चाहिए? और किस तरह की जांच करानी चाहिए? मुझे थाइरॉइड भी है।**

ये लक्षण भी एलर्जी की ओर इशारा करते हैं। जब हमारे फेफड़ों की सांस नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तब सांस लेने में समस्या होने लगती है, सांस लेते समय सीटी की आवाज आती है। ये समस्या कभी बढ़कर जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए आप समस्या की अनदेखी न करें और जल्दी ही डॉक्टर (जनरल फीजिशियन/चेस्ट फिजिशियन) को जाकर दिखाएं। वहीं आपको थायरॉइड संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी। समस्या को देखते हुए अलग-अलग तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें सीबीसी, ईएसआर, एइसी, चेस्ट एक्स रे सामान्य तौर पर शामिल हैं। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर विशेष जांच की सलाह भी दे सकते हैं।

- **मेरी उम्र 52 साल और वजन 90 किलो है। हाल में मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। शरीर में कार्बन डाई ऑक्साइड बढ़ गई थी। मुझे सांस की समस्या भी रहती है। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? मुझे क्या करना चाहिए?**

शरीर में कार्बन डाईऑक्साइड का लेवल बढ़ना ठीक नहीं है। गंभीर परिस्थितियों में इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। फेफड़ों में किसी-न-किसी तरह की खराबी आने के बाद ही कार्बन डाईऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। ऐसे में उस समस्या विशेष को ठीक किया जाना जरूरी है, अन्यथा यह समस्या दोबारा भी हो सकती है। इससे बचने के लिए फेफड़ों का खास ध्यान रखना होगा। अपनी इम्युनिटी बढ़ानी होगी। कमरे में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल रोज करें, मौसमी फल खाएं। बाहर भीड़ भरी जगहों पर न जाएं। आपको वजन कम करने की जरूरत है। जितना मोटापा अधिक, उतना फेफड़ों को फूलने की जगह कम मिलती है।

### भेजें अपने सवाल

अपनी सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं-

तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एक सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

# दिल पर असर डाल सकता है हाइपोथर्मिया

अधिक ठंड के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया दिल पर दबाव डालती है। रक्तसंचार में गड़बड़ी आने से शरीर का तापमान बहुत कम होने लगता है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। क्या है सही उपचार, बता रहे हैं, **डॉ. शरद टंडन**

हमारे शरीर का तापमान जब 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। समय पर इलाज न करने पर इससे एरिथमिया और यहां तक कि हृदय गति रुकने जैसी गंभीर दिल की जटिलताएं हो सकती हैं। यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ती है और इसके तुरंत लक्षण दिखाई नहीं देते, यही कारण है कि अकसर सही उपचार में देरी हो जाती है। जब शरीर का तापमान लगातार कम होता रहता है, तो दिल सहित महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए हाइपोथर्मिया के लक्षणों को देखते हुए तुरंत उपचार कराना चाहिए। है।

### दिल पर हाइपोथर्मिया का असर

- ठंड के जवाब में, शरीर रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर और कंपकंपी पैदा करके गर्मी बनाए रखने की कोशिश करता है। ये तरीके थोड़े समय के लिए मददगार होते हैं। अत्यधिक ठंड में बने रहने से शरीर की गर्माहट पैदा करने की यह क्षमता कम होने लगती है।
- जब ठंड की स्थिति बनी रहती है तो शरीर जितनी गर्मी पैदा कर सकता है, उससे तेजी से गर्मी खोता है। ऐसे में दिल को रक्त संचार में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है।
- जैसे-जैसे शरीर तापमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, दिल पर दबाव पड़ता है। सिकुड़ी रक्त वाहिकाओ के कारण रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है

जिससे एरिथमिया (अनियमित दिल की धड़कन), दिल की धड़कन का बहुत धीमा होना या हृदय गति रुक भी सकती है। गंभीर मामलों में, हाइपोथर्मिया दिल को पूरी तरह से रोक सकता है।

*(लेखक मेदांता गुरुग्राम के हृदय रोग विभाग से जुड़े हैं)*

### हाइपोथर्मिया के लक्षणों को पहचानना

**शुरुआती लक्षण**
कंपकंपी, त्वचा का पीला पड़ना व थकान। ये लक्षण हल्के हो सकते हैं, लेकिन इनकी अनदेखी न करें। ये शरीर और दिल पर दबाव का संकेत देते हैं।

**लक्षणों का बढ़ना**
जैसे-जैसे शरीर ठंडा होता जाता है, भ्रम, अस्पष्ट बोलना व चलने में कठिनाई होने लगती है। यह दिमाग और दिल के काम पर असर डाल सकता है।

**गंभीर चेतावनी**
कंपकंपी का बंद हो जाना एक गंभीर संकेत है कि शरीर अब गर्मी पैदा नहीं कर सकता है, जो दिल पर बहुत दबाव डालता है। तुरंत ध्यान दें। अगर हालत लगातार गंभीर हो रही है तो बेहोशी, अंगों को नुकसान और दिल की धड़कन रुक सकती है। इसमें तनाव की भी बड़ी भूमिका है।

### किन लोगों को खतरा है?

हाइपोथर्मिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा अधिक होता है- :

- लंबे समय से मधुमेह या हृदय रोगों से जूझ रहे लोग
- बुजुर्ग लोग, खासकर हृदय रोगों के शिकार। ऐसे में इनकी तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है।
- छोटे बच्चे ठंडे तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ।
- बेघर या ठंड में बहुत अधिक समय बिताने वाले लोग।

### रोकथाम और इलाज

- शरीर गर्म रखने के लिए परतों में कपड़े पहनें, खुद को सूखा रखें।
- काम के दौरान समय-समय पर किसी गर्म जगह पर कुछ समय बिताएं।
- बच्चों और बुजुर्गों को बहुत अधिक ठंड से बचाएं।
- हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखने पर उन्हें तुरंत गर्म जगह पर ले जाएं। गीले कपड़ों को सूखे, गर्म कपड़ों से बदलें और गर्म, बिना अल्कोहल वाले पेय पदार्थ दें। हृदयगति और रक्तचाप की जांच करते रहें। गंभीर मामलों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

# रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

**मेष :** मन परेशान हो सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिश्रम भी अधिक रहेगा।

**वृष :** मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग भी हैं।

**मिथुन :** मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। परिवार में भी शांति बनाए रखें। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

**कर्क :** आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर परिवार से दूर भी जा सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

**सिंह :** मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। माता की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं।

**कन्या :** आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफल रहेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

**तुला :** वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी, परंतु भागदौड़ भी अधिक रहेगी। कारोबार के लिए पिता से धन मिल सकता है।

**वृश्चिक :** मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

**धनु :** मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। परिवार के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के मौके मिलेंगे। माता की सेहत का ध्यान रखें।

**मकर :** मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। माता की सेहत का ध्यान रखें।

**कुंभ :** आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम बढ़ेगा।

**मीन :** मन परेशान हो सकता है। नौकरी में तरक्की के योग बन सकते हैं, परंतु विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। परिवार का साथ रहेगा। खर्च भी बढ़ेंगे।

### व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

24 जनवरी, शुक्रवार। शक संवत्: 04 माघ (सौर) 1946, पंजाब पंचांग: 10 माघ मास प्रविष्टे 2081, इस्लाम: 23 रज्जब 1446, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण दशमी तिथि सायं 07.25 बजे तक पश्चात एकादशी तिथि, वृद्धि योग सूर्योदय पूर्व 05.08 बजे तक पश्चात् ध्रुव योग विष्टि (भद्रा) चंद्रमा वृश्चिक राशि मे (दिन-रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 07.25 बजे तक। गंडमूल समाप्त दोपहर 12.45 बजे।

### वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मेरे शोरूम की जब से शुरुआत हुई है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। कृपया उपाय बताएं?
-कमलेश्वर सिन्हा, गोरखपुर

- आप शोरूम में अपने बैठने का स्थान बदल दीजिए। आप दक्षिण दक्षिण पश्चिम की जगह दक्षिण या पश्चिम में बैठिए।
- शोरूम का टॉयलेट उत्तर दिशा में सही नहीं है। यहां हरे रंग की पट्टी लगा दें।
- दीवार घड़ी को दक्षिण दिशा के स्थान पर उत्तर दिशा में लगाएं।
- एक हरे रंग का पौधा अपने शोरूम के टॉयलेट में रखें।
- एक गोमती चक्र से बना हुआ स्वास्तिक शोरूम के ईशान कोण में लगाएं।

### वर्ग पहेली : 7856

**बाएं से दाएं**
1. संभावित व्यय का पूर्व अनुमान; हिसाब लगाया जाना (4)
3. निस्संदेह; यथार्थ में; वास्तव में; वस्तुतः (4)
7. सादृश्य; समानता; तुलना; दृष्टांत; मिलान; वर्णन; प्रशंसा (3)
9. काट कर बनाए हुए बेल बूटे; पानी के बहाव के कारण कटी जमीन (3)
10. आत्मबल; उत्साह; साहस (4)
12. व्यवहार संबंधी तय मानक; शिष्टाचार के अधिकारिक मानक (4)
13. अधखिला फूल; कली; अंश; भाग (3)
15. किवाड़; द्वार; पट (3)
17. नामजदगी; पंजी में नाम लिखा जाना (4)
18. डरावना; भयानक; भीतिप्रद (4)

**ऊपर से नीचे**
2. झुंड; ढेर; समूह; कमरबंद; करधनी; पेटी (3)
4. ज्योति; आभा; कांति; दमक; प्रकाश (3)
5. एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक राज्य करने वाला सम्राट; महाराजाधिराज (4,3)
6. बुद्धि व धन की तुलना करने वाली एक लोकोक्ति (2,2,1,2)
7. अंत करना; अस्तित्व मिटाना; समूल नष्ट करना; समाप्त करना (4,3)
8. प्रकरण; विषय (3)
11. दबाव डालने वाला; प्रेरित करने वाला; भेजने वाला (3)
14. करने वाला; कार्यवाहक; कारण; साधन (3)
16. नीचे स्थान को भरना; छत बनाना (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

### वर्ग पहेली 7855 का उत्तर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ला | गू | 2 क | र | ना | ■ | 3 ग | ■ | 4 ख |
| ■ | ■ | रा | ■ | ■ | 5 फ | टा | फ | ट |
| 6 अ | प | मा | नि | 7 त | ■ | ग | ■ | ख |
| सं | ■ | त | ■ | ली | ■ | ट | ■ | ट |
| 8 तो | प | ■ | 9 का | न | न | ■ | 10 फू | क |
| ष | ■ | 11 स | ■ | हो | ■ | 12 अ | ■ | र |
| ज | ■ | मा | ■ | 13 ना | श | क | र | ना |
| 14 ने | वी | न | ता | ■ | ■ | ड़ | ■ | ■ |
| क | ■ | ता | ■ | 15 ते | र | न | ता | ल |

### सुडोकू : 7838

* मध्यम

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 4 | 2 | |
| | | | 2 | | | 3 | | |
| | 2 | | 8 | 4 | | 1 | | |
| | | | | | | 5 | | |
| 6 | 3 | | 9 | | 1 | | 4 | 8 |
| | | 5 | | | | | | |
| | | 8 | | 2 | 5 | | 9 | |
| | | 6 | | | 9 | | | |
| | 9 | 7 | | | | | | 4 |

**खेलने का तरीका :** दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

### हल : सुडोकू नं.7837

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |

# कीमती स्वर्ण

स्वर्ण की कीमत का लगातार बढ़ते जाना चिंताजनक व विचारणीय है। दस ग्राम सोने की कीमत का 83 हजार रुपये के करीब पहुंच जाना पहली नजर में दुनिया में चिंताजनक होती स्थिति की गवाही दे रहा है। वैसे स्वर्ण के भाव बढ़ने के अनेक कारण हैं, जिन पर गौर करना चाहिए। अव्वल तो सोने की वैश्विक मांग बढ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है। आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है, क्योंकि दुनिया में राजनीतिक अनिश्चितता दिख रही है। वास्तव में, सोने की कीमतों में दिसंबर महीने से ही बढ़त का रुख है। यह वही समय है, जब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुना। ट्रंप ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है, जिससे लोग स्वर्ण में निवेश को सबसे सुरक्षित समझने लगे हैं। आर्थिक अनिश्चितता दूर होते ही संभव है, स्वर्ण की कीमत में कुछ नरमी आए। आज भी ज्यादातर लोगों की सोच पारंपरिक है और स्वर्ण को बुनियादी निवेश माना जाता है। आज स्वर्ण में जरूरत से ज्यादा निवेश है। आम लोग ही नहीं, बड़ी-बड़ी कंपनियां, यहां तक कि सरकारें भी स्वर्ण खरीदकर इसकी वैश्विक मांग बढ़ाने में भागीदार बनती रही हैं।

स्वर्ण की कीमत मुद्राओं के अलग-अलग मूल्य और ब्याज दरों से भी प्रभावित होती है। सरकारी नीतियों की वजह से भी स्वर्ण प्रभावित होता है। अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की ताकत जैसे अंतरराष्ट्रीय कारक भी भारतीय बाजार में सोने की दरों पर प्रभाव डालते हैं। 24 कैरेट स्वर्ण की कीमत का एकमुश्त 860.0 रुपये बढ़ना और 82 हजार रुपये के आंकड़े के पार रहना तवज्जो की मांग करता है। प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत भी 99,500 रुपये के आसपास चल रही है। आशंका यही है कि अगर विश्व में राजनीतिक अनिश्चितता बनी रही, तो कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। ध्यान देने की बात है कि साल 2021 में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद से विदा हुए थे, तब प्रति दस ग्राम सोने का भाव भारत में 49,000 हजार रुपये भी नहीं पहुंचा था। दुनिया तेजी से बदल रही है, पर आर्थिक गतिविधियों को जैसे सकारात्मक रूप से बढ़ना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। शेयर बाजार में निवेश अभी भी चिंता से परे नहीं है। शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश का डूबना भी जारी है। संपत्ति व्यवसाय भी पिछले दो वर्ष से महंगाई से ग्रस्त है। मांग ज्यादा नहीं है, पर आवास, संपत्ति की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है। लोगों को लगता है कि संपत्ति में निवेश लंबे समय के लिए फंस जाएगा और उससे होने वाली कमाई भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में, घूम-फिरकर स्वर्ण पर सबकी नजरें आ टिकती हैं। मुश्किल समय में भी स्वर्ण को खरीदना और बेचना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है, तो विश्व स्तर पर उसकी मांग का बढ़ते जाना स्वाभाविक है।

**राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे लोग स्वर्ण में निवेश को सबसे सुरक्षित समझने लगे हैं।**

अब प्रश्न यह है कि स्वर्ण की कीमतों पर लगाम का उपाय क्या है? पहला उपाय तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को दुनिया के लिए चिंताजनक न बनाएं। देशों के बीच परस्पर तनाव न बढ़े। ट्रंप अगर दुनिया में एकतरफा बड़े कायाकल्प पर जोर देंगे, तो बाजार में अनिश्चितता का दौर लगातार बना रहेगा। आर्थिक विशेषज्ञ अब हिसाब लगाने लगे हैं कि ट्रंप के कड़े या स्वार्थपूर्ण कदमों से दुनिया को कितना नुकसान होने वाला है। अन्य देशों और अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी वैश्विक संगठनों-गठजोड़ों को भी संयम और समझदारी का परिचय देना होगा, ताकि बाजार में मांग-आपूर्ति, लेन-देन के बीच वाजिब संतुलन बना रहे और किसी भी चीज की कीमत बेकाबू न हो।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 24 जनवरी, 1950

### नगर-पिताओं को नेक सलाह

भारत के उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने दिल्ली के म्युनिसिपल भवन में महात्मा गांधी के चित्र का अनावरण करते हुए हमारे नगर पिताओं को बड़े काम की और नेक सलाह दी है। अगर वे सच्चाई के साथ उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो अपने कर्तव्य का यथोचित पालन करने का आत्म-संतोष अनुभव कर सकेंगे। गांधीजी ने अपने जीवन द्वारा निस्स्वार्थ जनसेवा का आदर्श प्रस्तुत किया था। म्युनिसिपल क्षेत्र में काम करने वालों को, चाहे वे वैतनिक हों या अवैतनिक, गांधीजी का म्युनिसिपल भवन में लगा चित्र उसी आदर्श की याद दिलायेगा। यदि वे सब इस आदर्श से अनुप्राणित होंगे तो इस चित्र का म्युनिसिपल भवन में अवस्थित किया जाना सार्थक होगा। यदि ऐसा न हुआ, तो जिस प्रकार अलंकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार यह चित्र भवन की शोभा तो अवश्य बढ़ायेगा, किंतु वह म्युनिसिपैलिटी की नैतिक श्रेष्ठता का द्योतक नहीं होगा। नैतिक श्रेष्ठता तो म्युनिसिपल कर्मचारियों के कर्तव्य पालन से ही उत्पन्न हो सकती है।

म्युनिसिपल कर्तव्य सीधे और सरल हैं। नगर को साफ-सुथरा रखना म्युनिसिनैलिटी का प्रधान कर्तव्य है। उसे नागरिकों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी होती है। रोशनी का इन्तजाम करना होता है, नगर के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का बोझ भी कुछ हद तक उसे उठाना पड़ता है। रोगियों की चिकित्सा में भी वह हाथ बंटाती है, हालांकि यदि नगर को साफ-सुथरा रखा जाये तो चिकित्सा की व्यवस्था करने का बोझ बहुत हद तक अपने आप घट जायेगा। म्युनिसिपल कमेटी को सड़कों, गलियों और नालियों को भी ठीक हालत में रखना होता है। नगर-पिताओं पर मुख्यतः यह जिम्मेदारी होती है कि वे म्युनिसिपल कार्यकारी तंत्र से इन कर्तव्यों को पूरा करायें। नागरिक अपने नगर-पिताओं से आशा रखते हैं कि वे केवल चुनाव के समय ही उनके दरवाजे न खटखटायें, बल्कि समय-समय पर उनके सम्पर्क पर आते रहें, ताकि उन्हें नागरिकों के अभाव का पता चलता रहे और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायता मिले। किंतु आम अनुभव यह है कि नगर-पिता चुनावों के पहले तो अपने चुनाव क्षेत्र में काफी चक्कर काटते हैं, किंतु जब एक बार चुन लिये जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। जिनके दिलों में जनता की निस्स्वार्थ सेवा की उमंग हो, उन्हें ही नगर-पिता बनने की जिम्मेदारियों को उठाने के लिये अपने-आप को प्रस्तुत करना चाहिए।

# आबादी पर नई नीति और नियंत्रण चाहिए

**एलन मस्क जैसे अमीर उद्यमी दुनिया में आबादी घटने का खतरा बता रहे हैं, पर सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत को आबादी नियंत्रण के लिए बड़े प्रयासों की जरूरत है।**

मनु गौड़ | जनसंख्या विशेषज्ञ

यहां स्कैन करें

विश्व की जनसंख्या पतन की ओर अग्रसर है। जब संपूर्ण विश्व नए साल की खुशियां मनाने में लगा था, तभी दुनिया के सबसे अमीर उद्यमी एलन मस्क ने अपने एक्स पर यह लिखकर सनसनी फैला दी कि विश्व जनसंख्या तेजी से गिरावट की ओर बढ़ रही है। जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन जैसे अनेक देशों में यह प्रवृत्ति अधिक दिख रही है।

यह ध्यान रखने की बात है कि एलन मस्क अन्य ग्रहों पर मानव बस्ती बसाने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टि से देखें, तो एक व्यवसायी को सदैव लाभ तभी होता है, जब मौजूदा परेशानियों के चलते लोग अपनी सुविधाओं व अच्छे जीवन के लिए नए उत्पादों और सुविधाओं का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक होगी, तो परेशानियां भी अधिक होंगी और आप समझ ही सकते हैं कि तब मानव बस्तियां कहां बसाई जाएंगी?

एलन मस्क के कथन को यदि हम कुछ समुदायों या देशों के संबंध में देखें, तो सही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जिस समुदाय या देश की प्रजनन दर 2.1 से कम हो जाती है, उसकी जनसंख्या में गिरावट होने लगती है। ऐसा ही वक्तव्य संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिया था, जिसकी भारत में बहुत चर्चा हुई।

यह एक सैद्धांतिक बात है, परंतु यदि हम मानव सभ्यता की प्रगति के इतिहास को देखें, तो कुछ और ही चित्र सामने नजर आता है। जहां मानव सभ्यता को तीन लाख से भी अधिक वर्ष लगे विश्व की जनसंख्या को सन 1804 में सौ करोड़ तक पहुंचाने में, वहीं मात्र अगले 123 वर्ष बाद 1927 में जनसंख्या दोगुनी, यानी दो सौ करोड़ हो गई। अगले 47 वर्ष बाद 1975 में पुनः दोगुनी, यानी चार सौ करोड़ हो गई। 1975 की तुलना में सन् 2021 में विश्व की जनसंख्या में 400 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और साल 2021 में वह 800 करोड़ के पार पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या 1,000 करोड़ हो जाएगी। जितनी तेजी से पिछले सवा दो सौ वर्षों में पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ी है, उतनी तेजी से और किसी प्रजाति की नहीं बढ़ी है।

जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ बढ़ा है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। आज पूरा विश्व इन्हीं कारणों से जहां जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रहा है, वहीं पृथ्वी पर कार्बन फुटप्रिंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की मानें, तो इंसान अपनी एक वर्ष की जरूरतों की पूर्ति के लिए अगले वर्ष के छह माह के संसाधनों पर निर्भर है, जिसे वर्ल्ड ओवरशूट डे का नाम दिया गया है। यदि ये संसाधन हमारी जमापूंजी होते, तो शीघ्र ही मानव सभ्यता का दिवालिया होना तय था। जितनी तेजी से हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उतनी तेजी से प्रकृति द्वारा उनका सृजन संभव नहीं। इसीलिए पूरा विश्व आज वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की खोज और प्रोत्साहन में लगा है।

प्रोफेसर सर स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि जिस गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कुप्रभाव भी तीव्र गति से बढ़ते जाएंगे। अगले सौ वर्षों में मनुष्य को रहने के लिए एक अतिरिक्त ग्रह की जरूरत पड़ेगी। एलन मस्क यह बात समझ रहे हैं, उन्हें मनुष्यों को किसी अन्य ग्रह पर बसाने में व्यवसाय दिख रहा है। शायद उन्हें चिंता सता रही होगी कि अगर दुनिया में आबादी घटी, तो दूसरे ग्रह पर इंसानों को बसाने की उनकी परियोजना बेकार हो जाएगी।

इसी प्रकार अगस्त 2017 में सिंगापुर में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 50 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने अधिक आबादी को सबसे बड़ा खतरा बताया। इसी क्रम में नवंबर 2018 में विश्व के 20,000 वैज्ञानिकों ने जनसंख्या को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एकाधिक मौकों पर वैज्ञानिकों ने मिलकर अपील की है कि आबादी घटनी चाहिए, पर वैज्ञानिकों की सलाह को न मानकर हम 50 वर्ष पुराने जीवन और पर्यावरण को तरस रहे हैं। वैज्ञानिकों व बुद्धिजीवियों के कथन को न मानकर आज यदि हम एलन मस्क के एक व्यवसाय से प्रेरित कथन को महत्व दें, तो मेरे विचार से यह उचित नहीं होगा।

यदि हम एलन मस्क के कथन को भारत के संदर्भ में देखें, तो जहां विश्व का 2.4 प्रतिशत भूभाग भारत के पास है और चार प्रतिशत जल संसाधन हैं, वहीं उन पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 18 प्रतिशत है। आज भारत में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या हो या प्रदूषण की, जाम होते शहरों की समस्या हो या पौष्टिक भोजन की, सूखते हुए जल स्रोतों की समस्या हो या पिघलते हुए हिमालय की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या हो या अच्छी व उपयोगी शिक्षा की, आप किसी भी समस्या की ओर देखेंगे, तो अधिक जनसंख्या की समस्या ही बाहें फैलाए खड़ी दिखाई देगी।

विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने वाला देश आज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, हमें चिंता करनी ही होगी। हमारे देश की जनसंख्या हमारे संसाधनों की तुलना में अधिक है। वर्ष 1971 की जनगणना में देश की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ दर्ज की गई और तब तक परिवार नियोजन हमारे संविधान का अंग नहीं था। वर्ष 1976 में संविधान संशोधन हुआ, जो 1 जनवरी, 1977 से प्रभावी हुआ। एक समय भारत में लगभग 62 लाख लोगों की नसबंदियां कराई गईं। इतने सभी प्रयासों के बाद भी 1981 की जनगणना में देश की जनसंख्या बढ़कर लगभग 68 करोड़ हो गई। नई जनसंख्या नीति के पालन के बावजूद भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ हो गई।

आश्चर्य नहीं, 15 अगस्त 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसंख्या विस्फोट के विषय पर देश को आगाह किया गया। कोविड 19 के समय 2021 में होने वाली जनगणना समय से नहीं हो पाई, पर आईयूएन की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ जनसंख्या में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है।

हर कदम पर देश ने बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर की है, लेकिन आज भी हमारा देश एक प्रभावी जनसंख्या नीति को तरस रहा है। हमें चिंता करनी होगी कि कहीं भारत भविष्य में कम होती जनसंख्या वाले देशों के लिए मजदूर पैदा करने वाला देश ही बनकर न रह जाए। इसलिए भारत को अपनी भावी पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए एक प्रभावी जनसंख्या नीति शीघ्र ही बनानी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# बलात्कार पर लड़कों के साथ बातचीत से आएगा बदलाव

नमिता भंडारे | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

देश के सबसे विकसित और साक्षर राज्य केरल में पिछले दिनों एक 18 वर्षीय दलित एथलीट ने खुलासा किया कि 13 साल की उम्र में उसका पहली बार यौन शोषण किया गया और अब तक 64 पुरुष उसकी अस्मत से खिलवाड़ कर चुके हैं। उसने अपने साथ पांच बार सामूहिक दुष्कर्म की भी बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और वह लड़की फिलहाल एक आश्रय-गृह में है। उम्मीद की जा सकती है कि उसे वहां जरूरी परामर्श व देखभाल मिल रही होगी।

उस लड़की का शोषण करने वाले पुरुष आखिर कौन हैं? उनकी उम्र 17 से 47 साल के बीच है। वे सब उसके पड़ोसी, पिता के दोस्त या खेल प्रशिक्षक हैं। यह वारदात दक्षिण फ्रांस के एक अन्य भयावह अपराध की याद दिलाती है, जिसमें डोमिनिक पेलिकॉट नामक शख्स अपनी 40 वर्षीया पत्नी को करीब दस साल तक ड्रग्स देता रहा और बेहोशी की हालत में उसका बलात्कार करवाता रहा। 70 से अधिक पुरुषों ने उससे दुष्कर्म किया। कहा जाता है, सिर्फ तीन पुरुषों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, हालांकि उनमें से किसी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की बीमारी, जिसमें यौन हिंसा शामिल है, किसी भौगोलिक सीमा, उम्र, शिक्षा के स्तर और आय से परे है। यह हमारे समय की सबसे खराब महामारियों में एक है कि दुनिया भर में हर तीन में से एक महिला किसी न किसी तरह यौन हिंसा का शिकार बनती है। भारत में हर दिन बलात्कार के 86 मामले दर्ज किए जाते हैं।

**पुरुष हिंसक पैदा नहीं होते। सामाजीकरण की हमारी प्रक्रिया उनमें से कई को दुष्कर्म जैसे अपराध की ओर उन्मुख कर देती है।**

जब बलात्कार की कोई घटना इतनी भयावह होती है कि वह 'राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर' दे, तब हमारे माननीय तुरंत मरहम-पट्टी जैसे उपायों में जुट जाते हैं। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की एक छात्रा के साथ यौन-उत्पीड़न के बाद दबाव में आए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिछले हफ्ते दो ऐसे विधेयक पेश किए, जिनमें यौन अपराधों के लिए सजा बढ़ाने के प्रावधान हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही वहां के हाईकोर्ट ने आरजी कर बलात्कार व हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुना दी है, लेकिन राज्य सरकार ने जघन्य बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पास कर दिया है। हालांकि, मृत्युदंड से भी यह अपराध कहां रुक सका है? दिल्ली में वर्ष 2012 के सामूहिक बलात्कार मामले के बाद संसद ने ऐसा ही कानून बनाया है। मगर कुछ हुआ है, तो सिर्फ अपराध के मामले बढ़े हैं। मसलन, साल 2012 में जहां बलात्कार के 24,923 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2022 में ये बढ़कर 31,516 हो गए।

जाहिर है, जब सख्त कानून से भी बात न बने, तो हमें उससे बेहतर समाधान का प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास है क्या? हमें पुरुषों से बात करनी चाहिए। वे सभी लोग, जिनसे हम रोज मिलते हैं। सबसे जरूरी तो यह है कि हमें लड़कों से बात करनी चाहिए। यह कारगर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में किशोरों के साथ एक गैर-सरकारी संस्थान 'ब्रेकथ्रू' द्वारा किए गए पायलट कार्यक्रम में पाया गया कि लड़कों से बात करने से उनकी सोच में सकारात्मक बदलाव आया। न केवल उन्होंने लड़कियों को अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया, बल्कि वे घरेलू कामों में अपनी मां और बहनों की मदद भी करने लगे। साफ है, हमें 'विषाक्त मर्दानगी' की अवधारणा पर चिंतन करना चाहिए। अपने देश में बहुत से लड़के ऐसे हैं, जो एक भयावह समझ के साथ विकसित हो रहे हैं। मर्दों को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, उन्हें समूह में रहना चाहिए, लड़कियों से बदसलूकी की सोच उनके अंदर पनपती रहती है। लिहाजा, जब तक हम लड़कों से बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। स्कूली पाठ्यक्रमों में, गैर-सरकारी व सरकारी संस्थाओं द्वारा इस बाबत कदम उठाने की जरूरत है।

यह एक कठिन चुनौती है, क्योंकि सोशल मीडिया के मंच भी इसी विषाक्त मर्दानगी से भरे पड़े हैं। 'स्वयं' की निर्देशक अमृता दासगुप्ता कहती हैं कि पुरुष हिंसक पैदा नहीं होते। यह समाज और सामाजीकरण की प्रक्रिया है, जो उनमें से कई को इस अपराध की ओर उन्मुख कर देती है। वाकई, हिंसा मुक्त दुनिया के लिए हमें पुरुषों व लड़कों के साथ मिलकर रूढ़िवादिता तोड़नी ही होगी। नए साल का यह भी एक संकल्प हो सकता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

# यहां संपूर्ण कहां कोई

सामान्य रूप से मनुष्य के दो तरह के चरित्र हो सकते हैं। एक, नकारात्मक चरित्र; अपराधी, समाज विरोधी और विद्रोही व्यक्ति का चरित्र और दूसरा, सुनिश्चित सिद्धांतवादी, परंपरागत, धार्मिक व सम्मानित चरित्र।

अपराधी को दंड दिया जाएगा, और यदि वह पकड़ा गया, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। समाज उसे बरबाद या नष्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह समाज के लिए खतरा है। वह आज्ञाकारी नहीं, अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और समाज उसे पसंद नहीं करता। समाज का अस्तित्व लोगों की निजता और वैयक्तिकता को नष्ट करने में ही निहित है। समाज के पास अधिक शक्ति होती है, यदि उसके चारों ओर वैयक्तिक इकाइयां न हों। यदि वहां व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विशेष होते हैं, तो उसकी शक्ति कम से कम होती जाती है। यदि पूरे समाज में अपनी वैयक्तिकता रखने वाले व्यक्ति होंगे, तो समाज के अधिकृत मुखियाओं के पास कोई शक्ति नहीं होगी, पुरोहितों और राजनेताओं के पास भी कोई शक्ति नहीं होगी। इसलिए समाज अनैतिक और असामाजिक लोगों को, उन विशिष्ट व्यक्तियों को, जिनके पास अपनी निजी नैतिक मान्यताएं हैं और जो कार्यों को अपने ढंग से करना चाहते हैं, उन्हें कुचलने और समूल नष्ट करने का प्रयास करता है।

यदि तुम समाज का अनुसरण करते हो, तो वह तुम्हारा सम्मान करता है। इसलिए प्रत्येक वह व्यक्ति, जो समाज के प्रति 'नहीं' से भरा है, वह विरोधी है। वह अपराधी बन जाता है और समाज की हां में हां मिलाने वाला सिद्धांतवादी चरित्र का व्यक्ति एक सम्मानित सज्जन बन जाता है।

यदि तथाकथित अपराधी तर्कपूर्ण पराकाष्ठा की ओर गतिशील होता है, तो वह शैतान बन जाएगा, और यदि सज्जन व्यक्ति तर्कपूर्ण पराकाष्ठा की ओर गतिशील होता है, तो वह संत बन जाएगा। संत वह व्यक्ति है, जो समाज के लिए होता है, और इसीलिए समाज उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। समाज के लिए हानिकारक चरित्र का व्यक्ति वह है, जो उसके लिए न जीकर केवल अपने लिए जीता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज उसके विरुद्ध होता है। लेकिन एक चीज है, जो दोनों में समान होती है। वे आधे होते हैं। यह बात समझ लेने जैसी है। यह सूफीवाद के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है कि संत और अपराधी, दोनों ही आधे-अधूरे हैं।

**समाज का अस्तित्व लोगों की निजता और वैयक्तिकता को नष्ट करने में ही निहित है। समाज के पास अधिक शक्ति तभी है, यदि उसके चारों ओर वैयक्तिक इकाइयां न हों।**

संत के पास केवल सुनिश्चित सिद्धांत हैं और वे निषेध व विरोध से चूक रहे हैं। इसी कारण तुम संतों को एकरस पाओगे। उनके साथ चौबीस घंटे गुजारना भी तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा होगी। वह कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, हमेशा अच्छा बना रहेगा, पर उसके पास अपने बारे में कोई अनूठापन नहीं होगा। कोई निजी स्वाद नहीं होगा, वह परंपरावादी होगा।

ओशो

**ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष**

हमें खुशी है कि भारत की संसद दुनिया की ऐसी संसद है, जिसने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। सभी विधायी संस्थाएं चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करें।

## अनुलोम-विलोम
### माननीयों की पेंशन

# काम करेंगे, तो पेंशन लेने में क्या ऐतराज

जब कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, तो फल की इच्छा रखता ही है। यह इच्छा तब और उचित जान पड़ती है, जब किसी ने अपना तन-मन-धन उस काम में खर्च कर दिया हो। जन-प्रतिनिधियों को इसी श्रेणी में रखना चाहिए। यह सही है कि कुछ जन-प्रतिनिधि जनता के विकास पर पूरा ध्यान नहीं देते, लेकिन ज्यादातर नेता अपने कार्यकाल में जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि जनादेश पाने के लिए उनको जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। ऐसे में, अगर वे वेतन-भत्ते या पेंशन आदि की इच्छा रखते हैं, तो इसमें क्या गलत है? यह समझना होगा कि कोई नेता अचानक से जन-प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना जाता। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। अपना खून-पसीना बहाना पड़ता है। अपने क्षेत्र में घर-घर घूमना पड़ता है। तब जाकर वह किसी चुनाव में जीत हासिल कर पाता है और जन-प्रतिनिधि बन पाता है। बताइए, जब कोई इतनी मेहनत करेगा, तो फल क्यों नहीं पाना चाहेगा? आलोचक महज पांच साल के कार्यकाल को देख रहे हैं, पर उस पांच साल को संभव बनाने के लिए जीवन के कितने साल खर्च होते हैं, उस पर वे ध्यान नहीं दे रहे।

कुछ यही तर्क वेतन-भत्ते को लेकर भी है। आरोप लगाया जाता है कि जन-प्रतिनिधियों को सुविधाओं के नाम पर बेहिसाब राशि दी जाती है। मगर ऐसा कहने वाले किसी जन-प्रतिनिधि के घर पर लगने वाले मजमे में शायद नहीं जाते। किसी न किसी समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग अपने जन-प्रतिनिधि के दरवाजे पर आते ही रहते हैं और उनमें से कई की खातिरदारी चाय-पानी से की जाती है। अब कल्पना कीजिए, जिस घर में सैकड़ों कप चाय रोजाना बनती हो, उस घर में राशन के लिए अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? फिर, कई लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। यह सब खर्च जन-प्रतिनिधि को अपनी जेब से करना पड़ता है। इसके लिए उनको अतिरिक्त से कुछ मदद नहीं मिलती। ऐसे में, यदि उन्हें वेतन-भत्ते नहीं दिए जाएंगे, तो वे अपने दरवाजे पर आने वाले लोगों का सत्कार कैसे कर पाएंगे?

जन-प्रतिनिधियों के लिए सबसे जरूरी है जनता। हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपने जन-प्रतिनिधि के पास पहुंचता है, तो वह समस्या के समाधान के साथ-साथ वहां सम्मान का भी आकांक्षी होता है। इसके लिए जरूरी है कि जन-प्रतिनिधियों के पास इतनी आर्थिक हैसियत हो कि वे दूसरों की मदद लिए बिना अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकें।

नरसिंहनाथ, टिप्पणीकार

# समाज सेवा के संकल्प में वेतन-पेंशन क्यों

यह विचित्र बात है कि 'जनसेवा' और 'जनसेवक' जैसे शब्दों के अर्थ अब बदल गए हैं। अब निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अब कथित जनसेवा के बहाने वेतनभोगी कर्मचारी बनने की आकांक्षा पाली जाती है और पांच साल की कथित सेवा के बाद पेंशन जैसी सुविधाओं का हकदार माना जाता है। विडंबना ही है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन इस विश्वास के साथ करती है कि वे उनके अधिकारों और कल्याण के लिए काम करेंगे, लेकिन वास्तव में इनका व्यवहार अब 'सेवा' से अधिक 'सुविधा और लाभ' की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी या निजी संस्थान में नौकरी करता है, तो उसे निश्चित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। यह वेतन उसके कार्य और प्रदर्शन के आधार पर तय होता है। पेंशन भी तभी मिलती है, जब एक लंबी अवधि तक ये काम करते हैं। मगर कथित जनसेवक के रूप में चुने गए प्रतिनिधि अपने पांच साल के काम-काज में ही वेतन, भत्ते, आवासीय सुविधाएं, पेंशन जैसी तमाम सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं। क्या यह व्यवस्था न्यायोचित है?

पेंशन का उद्देश्य है- सेवानिवृत्त होने के बाद व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। यह उन लोगों के लिए है, जिन्होंने जीवन भर समर्पित होकर काम किया है, लेकिन जब यह सुविधा पांच वर्ष के सीमित कार्यकाल के लिए दी जाती है, तो इसे न केवल संसाधनों का दुरुपयोग माना जाना चाहिए, बल्कि नैतिकता और न्याय की दृष्टि से भी गलत कहा जाना चाहिए। भारत जैसे देश में महात्मा गांधी ने तब तक तन पर एक धोती पहनना स्वीकार किया था, जब तक कि समस्त लोगों के तन न ढके जा सकें। गांधी जी को आदर्श मानने वाले हमारे जन-प्रतिनिधि आखिर किसी मुंह से इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी को आर्थिक मजबूरियों के कारण दो जून की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती?

साफ है, जन-प्रतिनिधियों की पेंशन-व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। यह व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि केवल उन्हीं जन-प्रतिनिधियों को पेंशन मिले, जिन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की हो और जिनका योगदान स्पष्ट व उल्लेखनीय हो। उनका वेतन-भत्ता भी केवल आवश्यकताओं तक सीमित हो, न कि उसे विलासिता का साधन बना दिया जाए। सुनिश्चित यही किया जाना चाहिए कि प्रतिनिधियों को केवल आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। वैसे भी, समाज-सेवा के संकल्प में वेतन-भत्ते या पेंशन आदि की जरूरत कहां है?

बलदेव राज भारतीय, टिप्पणीकार

**1.5** करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं देशभर में सक्रिय लगभग 1.4 लाख प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों से, जिनके माध्यम से दूध एकत्रित करने के साथ ही उन्हें कई संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।



आजकल

# पर्यावरण संरक्षण का भारतीय चिंतन

प्रिया शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, इंद्रप्रस्थ कालेज फार वूमेन, दिल्ली विवि

शुभम कुमार सानु
असिस्टेंट प्रोफेसर, इंद्रप्रस्थ कालेज फार वूमेन, दिल्ली विवि

**अमेरिका में एक बड़े इलाके में लगी आग से व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आग से निपटने के लिए तैयारियां और सतर्कता आवश्यक है। भारत के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि जंगलों को संरक्षित करने और आग से बचने के लिए हम दीर्घकालिक उपाय करें। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान आग की घटनाओं को घातक बना रहे हैं। इसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण के भारतीय चिंतन को भी समझना होगा, ताकि इस तरह की समस्या से समय रहते निपटा जा सके**

अमेरिका में आग से बड़े इलाके में वनों को भी नुकसान पहुंचा है। फाइल

अमेरिका के कैलिफोर्निया के लास एंजिलिस के जंगल की आग ने हाल ही में भारी तबाही मचाई है। अनुमान के अनुसार, इस भयावह आग की चपेट में आने से व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इस आग के कारण 30 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। लगभग 40 हजार एकड़ हिस्सा इस आग की चपेट में है एवं लाखों की संख्या में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ रहा है। इस आपदा ने पर्यावरण एवं जीव तंत्र को व्यापक रूप से दुष्प्रभावित किया है। आग की भयावहता इतनी है कि वैश्विक महाशक्ति माना जाने वाला अमेरिका भी इस प्रकोप के आगे विवश नजर आ रहा है।

मूल रूप से इस भयावह तबाही के लिए विशेषज्ञों द्वारा वहां विशेष भौगोलिक कारणों से उठने वाली तेज गर्म हवा, साल दर साल वर्षा के पैटर्न एवं निरंतरता में कमी, जलवाष्प की अनुपलब्धता, अत्यधिक तापमान, वनस्पतियों का निरंतर सूखते जाना, मानव की लापरवाही एवं प्राकृतिक तंत्र में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप समेत वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन आदि को प्रमुख कारक के तौर पर देखा जा रहा है। इन सबके अलावा भी कुछ आयाम हैं जो वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक साल दर साल विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दुष्प्रभाव को भयावह बना रहे हैं। इस कड़ी में मानव का पर्यावरण को ध्यान में रखे बगैर उपभोक्तावादी व्यवहार भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**अति उपभोक्तावाद** : आग की घटनाओं के लगातार बढ़ने से न केवल अमेरिका, अपितु समूचे विश्व में जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों की चर्चा हो रही है। इसके समाधान की बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण की व्यावहारिक एवं दार्शनिक समझ से प्रकृति के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के रास्ते निकलते हुए नजर आते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण संरक्षण हेतु चिंतन परिलक्षित होता है। अथर्ववेद संहिता में पृथ्वी और मानव के संबंध को माता और बालक के रूप में स्थापित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को मानवीय मूल्यों में समाहित करने हेतु भारतीय चिंतन ने पंचतत्वों में (पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश) भी देवत्व के दर्शन किए गए हैं। जबकि अमेरिका की स्थिति को देखा जाए तो लास एंजिलिस में आग की घटना व जान माल की हानि का कारण प्रकृति विरोधी सोच व कार्यशैली नजर आता है। इस प्रकार की आपदाओं के पीछे मानव स्वभाव में अतिवादिता एक प्रमुख कारण है।

पाश्चात्य जगत से उत्पन्न पूंजीवाद व निजी संपत्ति एकत्रीकरण के अधिकार की दौड़ ने एक तरफ संपत्ति अधिकार व बाजारी स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की जरूरत आधारित उत्पादन के बजाय बढ़ते उत्पादन से उत्पन्न जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। लिहाजा अनियंत्रित पूंजीवाद प्राकृतिक संसाधनों के शोषण का मुख्य कारण बन रहा है। इस दौड़ से बाहर होने का मतलब विकासशील एवं विकसित न होना भी है। अतः अनियंत्रित विकास और आपदा का संबंध गहरा है, जिसका कारण मानव व राज्य का प्रकृति के प्रति गैर एकीकृत चिंतन भी है। इसी संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन में पर्यावरण संरक्षण के बिंदु की प्रासंगिकता सिद्ध होती है।

**एकात्म मानवतावाद** : यह सिद्धांत टुकड़ों में विचार न करते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करने पर बल देता है। एकात्म मानवतावाद अर्थव्यवस्था का चिंतन उत्पादन की पद्धति के साथ करते हुए सामंजस्य का विचार करने पर जोर देता है। इसके साथ ही, यह सिद्धांत प्रकृति और पुरुष के आपसी तालमेल से प्रकृति व पुरुष पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को खत्म किए जाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित करता है। यह सिद्धांत मनुष्य में पूंजीवादी मानसिकता से उत्पन्न इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु प्रकृति को उपभोग की वस्तु न समझ, नैतिक आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु एक माध्यम मानने हेतु दृष्टिकोण देता है। साथ ही, एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत अर्थनीति को संहारात्मक न बनाते हुए सृजनात्मक होने पर जोर देता है।

**प्रकृति का शोषण** : आज वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादन हेतु प्रकृति का शोषण हो रहा है जिसका कारण आर्थिक लाभ, स्वार्थ, स्व एवं विकास की गलत धारणा है। एकात्म मानवतावाद के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय अपने पर्यावरण चिंतन में हर मनुष्य द्वारा अर्थव्यवस्था को भौतिक आवश्यकता पूर्ति का मात्र एक साधन न समझते हुए उनको समाज के प्रति दायित्वों का बोध भी करने हेतु जागरूक करते हैं। अतः अधिकार और दायित्व के परस्पर संबंध को समझते हुए एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रकृति के शोषण पर नहीं, अपितु उसके पोषण पर बल देने हेतु समस्त मानव जाति को प्रेरित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रकोप को नष्ट करने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ने मानव व्यवहार को आधारभूत माना है जिसमें विशेष रूप से 'सर्वाइवल आफ द फिटेस्ट' को ध्येय न मानकर ही अर्थनीति को स्थापित करने हेतु आग्रह किया है। जिस प्रकार मानव शरीर नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा भी है, ठीक इसी प्रकार मानव के आधार पर प्रकृति मात्र नहीं है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले कई संसाधन जीवन यापन हेतु मानव की सहायता करते हैं। इस संबंध के महत्व का बोध एकात्म मानव दर्शन मानव जाति को पुनः करने हेतु प्रेरित करता है।

## अमेरिका की आग से सबक लेने की जरूरत

विवेक मिश्र
अंतरराष्ट्रीय मामलों के अध्येता

अमेरिका में बीते दिनों एक बड़े इलाके में लगी आग ने व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। हालांकि संतोषजनक यह रहा कि तुलनात्मक रूप से जनहानि नियंत्रित रही। देखा जाए तो जंगलों में आग लगने के कई कारण होते हैं। प्राकृतिक कारणों में बिजली गिरना प्रमुख है, जो बड़े पैमाने पर जंगलों में आग फैला सकता है। इसके अलावा, गर्म और शुष्क मौसम आग की आशंका को और बढ़ा देता है। तेज हवाएं एवं सूखी घास आग के तेजी से फैलने का कारण बनती हैं। दूसरी ओर, मानव-जनित कारणों में लापरवाही से फेंका गया जलता हुआ सिगरेट का टुकड़ा, जंगलों में अनियंत्रित आग जलाना, बिजली के तारों में शार्ट सर्किट और जंगलों में पिकनिक आदि के दौरान असावधानी शामिल हैं।

भारत में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हैं। भारत के संदर्भ में वनाग्नि से होने वाले नुकसान की गहराई को समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। फारेस्ट सर्वे आफ इंडिया (एफएसआइ) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में कुल 36 प्रतिशत वन क्षेत्र आग के जोखिम में था। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य जंगलों में आग लगने की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में लगी आग ने 1,200 हेक्टेयर जंगल को बर्बाद कर दिया। वनाग्नि से न केवल पर्यावरणीय क्षति होती है, बल्कि वनों पर निर्भर आदिवासी समुदायों की आजीविका भी प्रभावित होती है। जंगलों में लगी आग का पर्यावरण पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे वनों में रहने वाले जीव-जंतुओं का निवास स्थान नष्ट हो जाता है और वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे सांस की बीमारियां होती हैं। आग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे वनस्पतियों को पुनर्जीवित होने में समय लगता है।

आग से होने वाले आर्थिक नुकसान की बात करें तो लकड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक नुकसान होता है। आग पर काबू पाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को भी भारी नुकसान होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से विस्थापन के कारण मानसिक तनाव और अवसाद की समस्या बढ़ती है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लिहाजा जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। सबसे पहले, सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए और आग का शीघ्र पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से जंगलों की निगरानी की जा सकती है। समुदायिक जागरूकता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोगों को जंगलों में आग से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

अमेरिका में लगी आग ने यह सिखाया है कि जंगलों की आग से निपटने के लिए तैयारियां और सतर्कता बेहद आवश्यक हैं। भारत के संदर्भ में भी यह अहम है कि हम अपने जंगलों को संरक्षित करने और आग से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय करें। जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान आग की घटनाओं को अधिक घातक बना रहे हैं। लिहाजा हमें सुनिश्चित करना होगा कि जंगलों को संरक्षित किया जाए और आग से बचाव के उपायों को प्राथमिकता दी जाए। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

खरी-खरी

## भैया बदल न जाना, अपने वादे निभाना

धर्मेंद्र जोशी

दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से सभी दल महिलाओं के एकमुश्त वोट पाने के लिए जुट गए हैं। अलग अलग नामों से स्कीम चलाने का वादा करते हुए महिला वोटर को लुभाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। खैर, सत्ता पक्ष जिसे अपने पिछले पांच वर्षों में किए गए जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास के नाम पर वोट मांगना था, वह भी बहनों नगद देने के दम पर सत्ता पाने को लालायित है और सत्ता से कई वर्षों से महरूम दल भी लुभाने के लिए फ्री की इतनी घोषणाएं कर रहे हैं कि जिनकी गिनती उनको खुद पता नहीं है।

अभी तक तो केवल धोती-साड़ी, चादर, बिंदी, चूड़ी और चप्पल आदि बांट कर महिला मतदाताओं को लुभाने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब तो महिलाओं के लिए बस फ्री, त्योहारों पर गैस का सिलिंडर फ्री, हर माह बैंक अकाउंट में बारह सौ रुपये से लेकर पंद्रह सौ या फिर दो-ढाई हजार तक रुपये देने के सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। परंतु एक तरफ तो महिलाओं को लुभावने वादों और रेवड़ी बांटने की संस्कृति के बल पर आकर्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में बालिकाओं के कुपोषण से सरकारें बेखबर है, बालिका शिक्षा के नाम पर पोस्टर और विज्ञापनों से ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वालों को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े देखने चाहिए।

इधर चुनावी बेला में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त-समर्थ करने का डंका पीटा जा रहा है, उधर बेटियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महिला सशक्तीकरण की हुंकार भरने वाले महिलाओं को संसद और विधानसभा में भागीदारी देने पर मौन धारण किए हुए हैं। इसके साथ ही पार्षद पति, सरपंच पति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पति स्थानीय निकायों में महिलाओं के अधिकारों का सरेआम हनन कर रहे हैं। ऐसे समय में महिला मतदाताओं का तो यही कहना है कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करके 'भैया बदल मत जाना, चुनाव जीतने के बाद अपने वादे को निभाना'।

पोस्ट

एक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए मुफ्त और समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, फिर चाहे उसे बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जाए या सब्सिडी द्वारा। यह राशन, पैसा, साड़ी इत्यादि बांटने से कहीं बेहतर है। इसके लिए सारी पार्टियों और राज्यों पर दबाव बनाया जाना चाहिए।
आसिफ आजमी @ASIFAZMI_DELHI

क्या यह कुछ अजीब नहीं लगता कि भारतीय उद्यमियों के साथ कारोबारी अनुबंध करने के लिए कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री हर साल दावोस जाते हैं। क्या यह भी उन सालाना खर्चों में से एक है, जो करदाताओं की जेब से किया जाता है?
तवलीन सिंह@tavleen_singh

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप ही रहा। बल्लेबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय बैटर्स ने अपनी दादागीरी दिखाई। अभिषेक शर्मा टी-20 के खतरनाक खिलाड़ी हैं। युवा भारतीय खिलाड़ियों ने गजब की फील्डिंग भी की। आर्चर की रफ्तार और उछाल ने आतंकित किया तो मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप सिंह खासे कारगर दिखे।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत कल का परिणाम

**क्या कोलकाता दुष्कर्म कांड के दोषी को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी?**

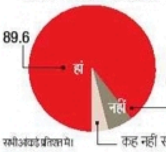


सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या दो महंगाई दरों की व्यवस्था से बेहतर नीति निर्माण में मदद मिलेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कुछ नेता हैं ले चुके कालनेमि अवतार,
बजरंगी इन पर करो तुम्हीं गदा से वार।
तुम्हीं गदा से वार नाम जो जपते झूठा,
बैठे कुर्सी पाय गाड़कर अपना खूंटा।
आगे देखि चुनाव नाम प्रभु का है लेता,
बने गुरू घंटाल फिर रहे हैं कुछ नेता!
- ओमप्रकाश तिवारी

# हवाई उड़ानों से उम्मीदों को लगेंगे पंख

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

झारखंड की उपराजधानी दुमका से हवाई सेवा शुरू होने की सुगबुगाहट के बाद अब राज्य में बोकारो समेत अन्य छोटे शहरों में भी हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। हाल ही में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दुमका एयरपोर्ट से रीजनल कनेक्टिविटी की नियमित उड़ानों के लिए सीएनएस एटीएस की सेवा एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के साथ समझौता करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे दुमका और दूसरे जिले के लोगों के हवाई सफर का सपना हकीकत में बदल जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी दुमका और बोकारो से हवाई सेवा परिचालन के लिए हरी झंडी दे दी है। एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। दुमका की बात करें तो यहां एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल और टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा सभी आधारभूत संरचना तैयार है। दुमका और बोकारो एयरपोर्ट शुरू होने से दुमका, गोड्डा, भागलपुर, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बंगाल के पुरुलिया सहित कई शहरों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने बोकारो, दुमका के बाद हजारीबाग और डाल्टनगंज के हवाई अड्डों के पुनरुद्धार की भी योजना बनाई है।

बोकारो व दुमका में विमान परिचालन शुरू होने के बाद झारखंड विमानन सेवा में पड़ोसी राज्य बिहार से एक कदम आगे हो सकता है। दुमका झारखंड के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। बंगाल से यह इलाका सटा हुआ है और राजमहल को गेटवे आफ बंगाल कहा जाता है। अकबर के काल में यह संताल परगना बहुत महत्वपूर्ण था। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यहां अकबर का टकसाल भी था। संताल परगना का भूराजनीतिक दृष्टि से भी

देवघर की तरह ही राज्य के कई और शहरों को उड़ान सेवा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। फाइल

बड़ा महत्व है। बांग्लादेश भी यहां से दूर नहीं है। यदि दुमका से उड़ान शुरू हो जाएगी तो भविष्य को देखते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नागर विमानन विभाग झारखंड के निदेशक संचालन कैप्टन एससी सिन्हा भी मानते हैं कि डीजीसीए से उड़ान के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में गति आएगी। सिन्हा के अनुसार अभी दुमका एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान के उड़ान भरने की क्षमता है। वैसे, बीते कई वर्षों से दुमका का एयरपोर्ट घरेलू विमान सेवा के लिए बनकर तैयार है। एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल और टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो चुके हैं। एयरपोर्ट को इस तरीके से तैयार किया गया है, ताकि यहां घरेलू और छोटे विमान उड़ान भर सकें। तत्काल यहां जो सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध है उसमें दुमका हवाई अड्डे से नौ से लेकर 19 सीटों वाले विमान उड़ सकेंगे। बाद में यहां की हवाई पट्टी की लंबाई चार हजार से बढ़ाकर छह हजार फीट करने की योजना है जिसके लिए जमीन अधिग्रहण व एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी होगा। तब यहां से 72 सीटों वाले विमान को उड़ने की स्थिति होगी। नागर विमानन निदेशालय यानी डीजीसीए से हरी झंडी मिल जाती है तो जल्द ही यहां से घरेलू यात्री विमानों की सेवा प्रारंभ हो सकती है। पहले चरण में दुमका से रांची, पटना और कोलकाता के लिए यात्री विमान सेवा शुरू करने की योजना है।

दुमका से घरेलू विमान सेवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई सेवाएं शुरू करने योजना की अहम कड़ी है। दुमका एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की सुगबुगाहट तो गत छह वर्ष पहले से हो रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में इस दिशा में गति लाई गई थी। अगस्त 2022 में दुमका के तत्कालीन सांसद सुनील सोरेन भी भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह किया था कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से शीघ्र विमान सेवा शुरू हो। यहां हवाई अड्डा बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आए थे तो वहां से भी नागर विमानन मंत्री ने दुमका हवाई अड्डा से शीघ्र हवाई शुरू करने का भरोसा दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि 2022 के अंत में दुमका से रांची व कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इतना तय है कि छोटे शहरों में उड़ान की ये योजनाएं लोगों की उम्मीदों को पंख लगाने के साथ ही विकास को नई उड़ान देने में सक्षम होंगी।

मंथन

# सहकारी समितियों का योगदान

दिलीप संघानी
अध्यक्ष, एनसीयूआइ व इफको एवं पूर्व सहकारिता मंत्री, गुजरात

**समाज में कायम विषमता को सहकारी समितियों के माध्यम से कम किया जा सकता है। वहीं अलगाव की बढ़ती भावना को भी इन समितियों के माध्यम से कम करने में मदद मिल सकती है**

सहकारिता रूपी नदी धाराप्रवाह बहती जा रही है। यह किसी बंधन से नहीं बांधी जा सकती है। यह जहां भी जाती है, विकास के छोटे से लेकर बड़े बीज बोती जाती है और आर्थिक समर्थन का आधार पैदा करती है। वास्तव में इसके शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक, सहकारिता सामाजिक और आर्थिक उत्थान का द्योतक है। हम सभी किसी न किसी तरह सहकारिता से जुड़े हुए हैं और इसकी यात्रा में निरंतर सहयोग कर रहे हैं।

भारत की सहकारी परंपरा प्राचीन है, जिसकी जड़ें इसकी संस्कृति और आर्थिक प्रणालियों में गहरी पैठ रखे हुए है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, गांवों की वित्तीय संरचना सहकारी ढांचे, रोजगार प्रदान करने, परिवारों का समर्थन करने और सामाजिक विकास में योगदान करने को दर्शाती हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी सहकारिता की भावना की प्रमुख भूमिका थी। रियासतों को एकजुट करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के दूरदर्शी प्रयासों और महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो' आंदोलन ने सामाजिक सहयोग का प्रदर्शन किया। सहकारी माडल की परिवर्तनकारी क्षमता पहचानते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, जो आधुनिक भारत में एक ऐतिहासिक कदम है।

**सहकारी इकोसिस्टम** : लगभग 132 साल पहले स्थापित अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने नवंबर 2024 में 107 से अधिक देशों के साथ भारत में अपनी पहली बैठक की। भारत के सहकारी इकोसिस्टम की बढ़ती ताकत को देखना सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल था। नई दिल्ली में इफको द्वारा आयोजित आइसीए वैश्विक सम्मेलन की सफल मेजबानी से भारत ने सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप-प्रधानमंत्री समेत 107 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता क्षेत्र के वैश्विक प्रभाव को मान्यता देते हुए 2025 को 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरक दृष्टि और रणनीतिक नेतृत्व ने भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक महत्व दिया है। जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण पर उनके जोर के साथ-साथ अमित शाह की सहकारी माडल की गहरी समझ ने इस क्षेत्र को दुनिया के लिए आशा की नई किरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। इस सम्मेलन की सफलता उनके अनुकरणीय नेतृत्व और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। कई अंतरराष्ट्रीय सहकारी नेताओं ने भारत के सहकारी आंदोलन के बारे में जानने और भारत में प्रमुख सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी की खोज करने में गहरी रुचि व्यक्त की। इस अनुभव ने प्रधानमंत्री के 'वसुधैव कुटुंबकम्' के दृष्टिकोण की भावना को मजबूत किया, जो हमारे राष्ट्र के मूल्यों और परंपराओं से मेल खाती है।

**सह-स्वामी एवं आपूर्तिकर्ता** : भारत की डेयरी सहकारी समितियां 'वसुधैव कुटुंबकम्' के दृष्टिकोण और सहकारिता की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से खड़ी हैं। अमूल डेयरी कोआपरेटिव की स्वप्निल यात्रा विस्मय पैदा करने वाली है। छोटे स्तर पर शुरू करके यह दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियों में से एक बन गई है। 'आणंद पैटर्न' पर आधारित अमूल की सफलता, जिसमें किसान ही सह-स्वामी होने के साथ आपूर्तिकर्ता भी है, उसने आय और लाभ का उचित वितरण सुनिश्चित किया है। इसकी सफलता आर्थिक विकास से परे है और महिला सशक्तीकरण के लिए एक मंच प्रदान करती है जो इसे देश और दुनिया भर की अन्य कृषि और डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक आदर्श खाका बनाती है। इस क्षेत्र के लिए काम करने से सहकारिता के आदर्शों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई है। मेरे प्रयासों से वर्ष 1995 में 'वसुंधरा-अमरेली' नामक संगठन की स्थापना की थी।

**सशक्त भारत का सहकारी ढांचा** : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व से सशक्त भारत का सहकारी ढांचा विकास के लिए एक प्रेरक माडल के रूप में उभरा है। ''सहकार से समृद्धि'' के दृष्टिकोण को विश्व स्तर पर स्वीकृति मिल रही है। आइसीए वैश्विक सम्मेलन ने सहकारी नीतियों को और मजबूत करने, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, नेतृत्व को बढ़ावा देने, समानता सुनिश्चित करने और सहकारिता के माध्यम से न्याय को आगे बढ़ाने के लिए आधार तैयार किया है।

विश्व में असमानता के बढ़ते विभाजन को सहकारी उपायों के माध्यम से कम किया जा सकता है। युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के बीच अलगाव की बढ़ती भावना को सहकारी समितियों के बंधन से ही कम किया जा सकता है। साझा भविष्य के लिए यह अनिवार्य है कि सहकारी आंदोलन केंद्र में रहें और न्यायसंगत आर्थिक और सामाजिक विकास करें।

ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों का व्यापक योगदान देखा जा रहा है। फाइल

*********

दैनिक जागरण
सत्य से बड़ा कोई तथ्य नहीं

# अमेरिका में भारतीय

भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार रहने की बात कहकर वही किया, जो उन्हें करना चाहिए था। यदि अमेरिका अपने यहां अवैध रूप से आए लोगों को वापस करने का फैसला करता है तो भारत को अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं बनने वाली। जहां अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि भारतीय नागरिक उसके यहां न तो अवैध रूप से प्रवेश करने पाएं और न ही उत्पीड़न की झूठी शिकायतों के आधार पर शरण पाने पाएं, वहीं भारत को यह देखना होगा कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं, उन पर लगाम लगे। इसलिए लगे, क्योंकि चोरी-छिपे वहां जाने वाले देश की बदनामी कराते हैं और उन भारतीयों की छवि भी खराब करते हैं, जो वैध तरीके से वहां गए हैं। भारत सरकार इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि अमेरिका जाने की ललक में अवैध तरीके अपनाने वाले लोग ठगी का शिकार होते हैं-कुछ भारत में और कुछ अमेरिका के पड़ोसी देशों में। कई मामले ऐसे आए हैं, जिनमें अमेरिका या यूरोप जाने की कोशिश में लोगों ने अपनी सारी जमा-पूंजी गंवा दी और फिर भी वहां नहीं पहुंच पाए। कुछ तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि वे डंकी रूट कहे जाने वाले बेहद खतरनाक रास्तों से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे।

भारत सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि में लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले गिरोह सक्रिय हैं। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का वीजा और वहां नौकरी दिलाने का फर्जी दावा करने वालों ने बाकायदा अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये ठगी की दुकानें हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई नहीं करतीं। भारत सरकार को ऐसे राज्यों को आवश्यक निर्देश देने चाहिए। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे लोग वैध और सुरक्षित तरीके से विदेश जा सकें। यदि सरकारी एजेंसियां इसमें सहायक बन जाएं तो विदेश में नौकरी का लालच देकर ठगी करने वाले स्वतः हतोत्साहित होंगे। भारत को इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा कि ट्रंप प्रशासन की नई नागरिकता नीति से कहीं वे भारतीय दंपती संकट का सामना न करने पाएं, जो अमेरिका गए तो वैध तरीके से हैं, लेकिन उनके पास वहां की नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है। इनमें अधिकांश एच-1बी वीजा धारक हैं। ट्रंप ने घोषणा की है कि 20 फरवरी के बाद ऐसे दंपतियों की संतानों को नागरिकता देने की सुविधा खत्म कर दी जाएगी। भारत को अमेरिका को यह बताना होगा कि इस नीति से वही घाटे में रहेगा। इस पर हैरानी नहीं कि खुद अमेरिका में ट्रंप की नई नागरिकता नीति का विरोध हो रहा है।

# सराहनीय पहल

हर साल बाढ़-सुखाड़ की पीड़ा झेलने वाले बिहार के किसानों की समस्या को जड़ से खत्म करने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। बाढ़ से सुरक्षा व सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए बिहार सरकार ने एकीकृत योजना तैयार की है। विश्व बैंक से ऋण लेकर इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक की टीम से विचार-विमर्श भी शुरू कर दिया गया है। प्रस्तावित परियोजना में तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, बराजों के आधुनिकीकरण, नहरों के पुनर्स्थापन तथा पक्कीकरण और नदियों के गाद प्रबंधन सहित कई तरह के कार्य को शामिल किया गया है। निश्चित रूप से किसानों के लिए बिहार सरकार की यह अच्छी पहल है। हर वर्ष किसान बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से जूझते हैं। उत्तर बिहार में गत वर्ष भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। वैसे यहां हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ आती है। तटबंधों के सुदृढ़ होने से बाढ़ को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। इस राज्य के निवासियों के साथ प्रकृति की विडंबना देखिए कि जहां बाढ़ नहीं आती, वहां के किसान सुखाड़ की समस्या से परेशान रहते हैं। नहरों की स्थिति अच्छी नहीं है। गर्मी के दिनों में बिहार की कई नहरें सूखे का मार झेलती हैं। किसानों को बारिश के पानी का इंतजार करना पड़ता है। उत्तर बिहार के जिलों में ही लगभग 4,377 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल है, लेकिन इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में भी नहरों से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। इसी तरह दक्षिण बिहार में भी भोजपुर, रोहतास और यहां तक कि पटना जिले की नहरों की हालत अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसे में नहरों के पुनर्स्थापन तथा पक्कीकरण की सूचना राहत देने वाली है।

> नदी जल का बेहतर प्रबंधन करते हुए सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने की पहल सराहनीय है

# खतरा बने गैर सरकारी संगठन

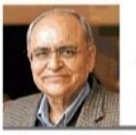

बलबीर पुंज

**निःसंदेह कुछ एनजीओ समाज कल्याण में संलग्न हैं, पर यह भी सच है कि कई भारत विरोधी शक्तियां एनजीओ के रूप में देश को कमजोर करने में लगी हैं**

भारत को अस्थिर करने वाली आंतरिक-बाहरी शक्तियों के कई मुखौटे हैं। ऐसा ही एक भोला दिखने वाला नकाब एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) है। बीते दिनों आयकर विभाग ने आक्सफैम इंडिया सहित पांच बड़े एनजीओ के दफ्तरों पर छापा मारा। गहन जांच से सामने आया कि ये संगठन बाह्य-धनबल के दम पर देश की औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इस संदर्भ में एक हालिया घटनाक्रम और भी चौंकाने वाला रहा और वह यह कि एनजीओ द्वारा समाज में मजहब के नाम पर वैमनस्य फैलाने वालों का बचाव किया जा रहा है। यह मामला 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा है। इस मामले में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुस्लिम बहुल इलाके में उन्मादी भीड़ ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन की हत्या कर दी थी। हाल में जब इस मामले में एनआइए की अदालत ने निर्णय सुनाया तो उसमें यह चिंता व्यक्त की गई कि कुछ एनजीओ दंगाइयों को हरसंभव कानूनी सहायता पहुंचा रहे थे। इनमें सिटीजन आफ जस्टिस एंड पीस, पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, रिहाई मंच, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसे देसी और अलायंस फार जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और साउथ एशिया सालिडेरिटी ग्रुप जैसे विदेशी एनजीओ के नाम सामने आए। जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इस पर कहा, 'यह पता लगाने के लिए कि एनजीओ को धन कहां से मिल रहा है, उनका सामूहिक उद्देश्य क्या है और न्यायिक प्रक्रिया में उनके अवांछित हस्तक्षेप को रोकने का प्रभावी उपाय करने हेतु इस फैसले की एक प्रति बार काउंसिल आफ इंडिया और केंद्रीय गृह सचिव को भेजी जानी चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक और संकीर्ण सोच को बढ़ावा दे रही है।'

सिटीजन आफ जस्टिस एंड पीस की संस्थापक ट्रस्टी और सचिव तीस्ता सीतलवाड़ हैं, जिनके खिलाफ सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर गुजरात दंगा मामले में झूठी कहानी गढ़ने और फर्जी गवाही दिलाने का मामला दर्ज है। किसी संदिग्ध किस्म के एनजीओ की पड़ताल पर कुछ तबकों के विरोध का सिलसिला बहुत पुराना है। इसके लिए लोकतंत्र पर आघात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश जैसे आरोप भी लगाए जाते हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर स्वर मुखर भी होते रहे हैं। 2005 में माकपा के अधिवेशन में पार्टी नेता प्रकाश करात ने कहा था, 'हमारी पार्टी ने चेतावनी दी है कि एनजीओ की कई गतिविधियों को वित्तपोषित करने हेतु बड़ी मात्रा में विदेशी धन आ रहा है। पश्चिमी एजेंसियों से मिलने वाले ऐसे धन का उद्देश्य लोगों का राजनीतिकरण करना होता है।' ऐसी बातें निराधार नहीं हैं। भारतीय विकास गाथा में एनजीओ लाबी द्वारा गतिरोध पैदा करने के अंतहीन उदाहरण हैं।

वर्ष 1985 में चीन और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 293 डालर थी। अभी चीन में यह 13,000 डालर से अधिक तो भारत में महज 2,700 डालर है। करीब 18.5 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की चीनी आर्थिकी भी भारत से करीब पांच गुना विशाल है। विकास की इस दौड़ में भारत के पिछड़ने को एक परियोजना के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक थ्री गोर्जेस डैम, जो चीन में 10 वर्षों से कुछ अधिक में बनकर तैयार हो गया, जबकि उसकी तुलना में कहीं छोटे सरदार सरोवर बांध को पूरा करने में भारत को 56 साल लग गए। इसका एक बड़ा कारण देश में समझौतावादी खिचड़ी गठबंधन सरकारें भी रहीं। इसका लाभ मानवाधिकार-पर्यावरण संरक्षण के नाम पर नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी एनबीए जैसे संदिग्ध मंशा वाले संगठनों ने उठाया। इस दौरान जहां देश का विकास अवरुद्ध रहा, वहीं एनबीए नेता मेधा पाटकर को दुनिया भर में प्रचार मिला। आज सरदार सरोवर बांध से गुजरात के साथ मप्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के करोड़ों लोगों को बिजली, सिंचाई हेतु पानी और स्वच्छ पेयजल मिल रहा है।

तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु परियोजना को भी एनजीओ के हस्तक्षेप की तपिश झेलनी पड़ी। फरवरी 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा था, 'कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुश्किलों में घिर गया है, क्योंकि अमेरिका स्थित कई एनजीओ हमारे देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति वृद्धि की आवश्यकता की कद्र नहीं करते।' रूस समर्थित इस परियोजना का एनजीओ लाबी द्वारा भारी विरोध हुआ था। इससे उसके परिचालन में आठ साल की देरी हुई और परियोजना लागत दस हजार करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई। केरल में विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण के समय भी यही देखने को मिला। तब चर्च के समर्थन से स्थानीय मछुआरों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस पर केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा था कि यह विरोध स्थानीय मछुआरों का न होकर संगठित प्रतीत हो रहा है। कथित पर्यावरणीय चिंताओं के नाम पर योजनाबद्ध उग्र प्रदर्शन और चर्च प्रेरित विरोध के बाद तूतीकोरिन में वेदांता को स्टरलाइट तांबा स्मेलटर कारखाना 2018 में बंद करना पड़ा। इससे भारतीय तांबा उद्योग को इतनी क्षति पहुंची कि 2017-2018 तक जो भारत विश्व के शीर्ष पांच तांबा निर्यातकों में से एक था, वह तांबे का आयातक बन गया।

निःसंदेह कुछ एनजीओ समाज कल्याण कार्यों में संलग्न हैं, लेकिन कई शक्तियां एनजीओ का रूप धारण करके देश और समाज को कमजोर करने के प्रयासों में शामिल हैं। इसे देखते हुए 2012 से 2024 तक गृह मंत्रालय कुल 20,721 एनजीओ का विदेशी अंशदान पंजीकरण रद कर चुका है। फिर भी वित्त वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच एनजीओ को लगभग 89 हजार करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ। आखिर विदेश से एनजीओ को मिल रहे अकूत धन का उद्देश्य क्या है? आधुनिक युद्ध सीमाओं की मोहताज नहीं, इसलिए देश के भीतर पल रहे दुश्मनों पर भी नकेल कसने की भी जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

अवधेश राजपूत

# आसान नहीं हाथ के हालात बदलना

राजकुमार सिंह

**कांग्रेस को तय करना होगा कि उसे जुगाड़ से सत्ता चाहिए या संगठनात्मक सक्रियता से जनाधार पाकर अपने बल पर?**

कांग्रेस का नया चुनावी नारा: हाथ बदलेगा हालात, न हरियाणा में हालात बदल सका और न ही महाराष्ट्र में। हां, उसके नेतृत्व वाले गठबंधन के हालात अवश्य बदल गए। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद आइएनडीआइए के नेतृत्व को लेकर उठे सवालों पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तेवर बता रहे हैं कि हाथ ने अपने हालात बदलने का मन बना लिया है। लगभग छह महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिस आप के साथ युगल गीत गाते हुए वोट मांग रही थी, अब वह उसे एंटी नेशनल, भ्रष्ट और धोखेबाज दिखने लगी है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बताते हुए आप से दोस्ती को गलती माना। इसके बाद आप और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ गई। दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू करते हुए राहुल गांधी ने तो केजरीवाल को मोदी की तरह झूठे वादे करने वाला करार दिया। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि राहुल कांग्रेस बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मैं देश बचाने की। राजनीतिक टीका-टिप्पणी से इतर देखें तो सच यही है कि दोनों अपनी राजनीति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

जब 2023 में दो दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी दलों ने अपना मोर्चा-आइएनडीआइए बनाया था तो मंच पर बैनर टंगा था: यूनाइटेड वी स्टैंड। एक और बैठक में मंच पर स्लोगन लिखा था, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लेकिन देश को दिखाए गए उन सपनों का सच डेढ़ साल में सामने आ गया। तनातनी पहले भी दिखती रही, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बात आर-पार तक पहुंच गई। फिलहाल सीधी जंग कांग्रेस और आप के बीच है, जबकि अन्य घटक दर्शक दीर्घा से अपनी पसंद के पक्ष का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जब चुनावी जंग अन्य राज्यों में पहुंचेगी तो वहां भी ऐसे परिदृश्य की संभावना से इन्कार नहीं। गठबंधन बनने के समय ही यह तथ्य रेखांकित किया गया था कि घटक दलों में मोदी और भाजपा के विरोध के अलावा कोई साझा उद्देश्य नहीं है, उलटे उनमें दलगत हितों और महत्वाकांक्षाओं का तल्ख टकराव है। दो लोकसभा चुनावों में हाशिये पर रहे विपक्षी दल तीसरे चुनाव के लिए एक साथ तो आए, पर मकसद पूरा न होने पर वापस अपनी-अपनी राह चलने को बेताब हैं। लोकसभा चुनाव में भी बंगाल, केरल और पंजाब में मित्र दल आपस में ही जोर आजमाइश कर रहे थे। अब यदि दिल्ली में भी कांग्रेस और आप ताल ठोंकते दिख रहे हैं तो आश्चर्य नहीं।

दिल्ली में प्रचार करता कांग्रेस कार्यकर्ता। एएनआइ

दिल्ली में कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकामी के बाद उसने शायद अपने पुनरुत्थान के प्रयास का मन बना लिया है। इसमें कोई बुराई नहीं, पर यह काम आसान नहीं। दशकों तक देश और प्रदेशों पर एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस की दुर्दशा अचानक नहीं हुई। बेशक उसका ऐतिहासिक चुनावी पराभव 2014 में हुआ, लेकिन अपनी कमजोरियों-गलतियों से वह बहुत पहले से जर्जर होने लगी थी। कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु और बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रह गई है। दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार उसके शक्ति स्रोत थे, लेकिन अब वहां भी वह दशकों से क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। आंध्र, झारखंड में भी यही स्थिति है। यह सब हाल-फिलहाल नहीं हुआ। दरअसल सत्ता पाने के खेल में कांग्रेस इतनी आत्ममुग्ध हो गई कि संगठन खोखला होता गया। जनाधार वाले क्षत्रपों के बजाय आलाकमान की पर्चियों से मुख्यमंत्री बनने लगे। जैसे नेता आगे बढ़े, उन्होंने वैसे ही कार्यकर्ता भी आगे बढ़ाए।

आप समेत ज्यादातर क्षेत्रीय दल न केवल कांग्रेस के बिखरते जनाधार पर खड़े हैं, बल्कि कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। देश पर शासन को अपना एकाधिकार समझने वाली कांग्रेस की अहमन्यता उसकी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। इसके चलते उसकी रणनीति एक कदम आगे-दो कदम पीछे वाली हो गई। 2013 में आप ने ही दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल किया, लेकिन उसने भाजपा को रोकने के लिए उसी की सरकार बनवा दी। फिर भला 2015 और 2020 के चुनाव में मतदाता उस पर कैसे विश्वास करते? अब डेढ़ साल साथ रहने के बाद दोनों फिर आमने-सामने हैं। कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में दिशाहीन नहीं रही। जिस उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर नेहरूजी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वहां कांग्रेस कभी सपा से गठबंधन करती रही, तो कभी बसपा से, जबकि दोनों पार्टियां उसके परंपरागत वोट बैंक रहे जनाधार पर खड़ी हैं। जिन अखिलेश यादव की सरकार को जंगलराज बताते हुए राहुल गांधी विरोध में पदयात्रा कर रहे थे, उन्हीं से फिर गठबंधन भी कर लिया। नेताओं के लिए इस तरह मौके के मुताबिक हाथ मिला लेना मुश्किल नहीं होता, पर जो कार्यकर्ता दशकों तक एक-दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और राजनीतिक विरोध की कीमत चुकाते हैं, वे अचानक कैसे गलबहियां कर युगल गीत गाते हुए मतदाताओं के बीच जाएं? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। आखिर भाजपा भी तो दो लोकसभा सीटों से 303 तक पहुंची ही, पर कांग्रेस को अपने हालात बदलने के लिए सबसे पहले यह तय करना होगा कि उसे जुगाड़ से सत्ता चाहिए या फिर संगठनात्मक सक्रियता से जनाधार वापस पाकर अपने बल पर।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

## ऊर्जा

### वेदना

वेदना मनुष्य को संवेदनशील बनाती है और संवेदना के अभाव में मनुष्य कई मानवीय मूल्यों से वंचित रह जाता है। वेदना न केवल हमें अपने अस्तित्व का बोध कराती है, अपितु हमारे आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। यह एक भावनात्मक और शारीरिक अनुभव है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, दुख, संघर्ष और पीड़ा से उत्पन्न होता है। महात्मा गांधी ने यथार्थ ही कहा है, 'वेदना हमें विनम्र बनाती है और जीवन के उच्चतम सत्य को समझने में सहायक होती है।' गांधीजी का सत्याग्रह इसी सिद्धांत पर आधारित था कि अन्याय और पीड़ा का सामना करते हुए भी अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए। उन्होंने व्यक्तिगत वेदना को सामूहिक मुक्ति का साधन बनाया।

गीता में भी श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन की वेदना और संघर्षों को स्वीकार करने का यही संदेश दिया है, 'सुख-दुख, लाभ-हानि और विजय-पराजय को समान समझकर कर्म करो।' यह संदेश यही इंगित करता है कि वेदना को समझना और स्वीकार करना ही वास्तविक संतुलित जीवन का आधार है। जो वेदना सह सकता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

संप्रति, वेदना का रूप बदल गया है। वेदना के इस परिवर्तित स्वरूप को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे समाज सेवा का साधन बनाना चाहिए। वेदना न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव, बल्कि यह मानवता को जोड़ने वाला एक सूत्र भी है। यह हमें जीवन के प्रति विनम्रता, सहिष्णुता और करुणा सिखाती है। वेदना को केवल पीड़ा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें आत्मबोध और सामाजिक उत्थान के पथ पर ले जाती है। कई मनीषियों ने अपनी वेदना को गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन का सार ही यही है कि दुख और पीड़ा हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

# 'कृत्रिम सूर्य' से असीमित स्वच्छ ऊर्जा!

प्रदीप

> पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित ऊर्जा स्रोत को विकसित करने की ओर अग्रसर हैं विज्ञानी

विश्व में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच एक स्वच्छ, टिकाऊ और असीमित ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में चीन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। चीन के 'कृत्रिम सूर्य' यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक (ईस्ट) ने 17.76 मिनट तक अत्यधिक गर्म (सुपर-हाट) प्लाज्मा को बनाए रखने का विश्व रिकार्ड स्थापित किया है। यह सफलता विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा संकट का समाधान करने की उम्मीद जगाती है।

लंबे समय से विज्ञानी ऐसे ऊर्जा स्रोत की तलाश में हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा की मांग को पूरा कर सके। यह खोज अब नाभिकीय संलयन (न्यूक्लियर फ्यूजन) पर आकर रुकती प्रतीत हो रही है। यही प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का मूल स्रोत है। विज्ञानी कई वर्षों से इस प्रक्रिया को पृथ्वी पर दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। चीन का ईस्ट रिएक्टर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को धरती पर सफलतापूर्वक दोहराने का प्रयास कर रहा है। यह कार्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। फिर भी, यह उपलब्धि दिखाती है कि चीन इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।

संलयन ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता और कचरा भी न्यूनतम उत्पन्न होता है। इसका ईंधन समुद्र के पानी से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इसे व्यावसायिक स्तर पर लागू करने में अभी कई चुनौतियां हैं। इसकी उच्च लागत और तकनीकी जटिलताएं बड़े पैमाने पर उत्पादन के मार्ग में बड़ी बाधा हैं।

नाभिकीय संलयन पर आधारित ऊर्जा को लेकर आइटीईआर (इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर) परियोजना पूरी दुनिया का साझा सपना है। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसा नाभिकीय रिएक्टर बनाया जा रहा है, जिसमें संलयन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा के शोध और विकास कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना में भारत, रूस, जापान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। इस परियोजना में टोकामक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन के भारी समस्थानिकों की पतली धार को चुंबकों की मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसे लेजर के माध्यम से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा।

ईस्ट रिएक्टर की सफलता यह संकेत देती है कि विज्ञानी इन तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर विकसित किया जाता है, तो यह मानवता को स्वच्छ और असीमित ऊर्जा का स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है।

**(लेखक विज्ञान संचारक हैं)**

### सतर्क रहे भारत

'ट्रंप की नीतियों से लाभ उठाए भारत' शीर्षक से प्रकाशित डा. जयंतीलाल भंडारी के आलेख में ट्रंप की नीतियों से चीन को होने वाले नुकसान और भारत को संभावित लाभ का उल्लेख है। ट्रंप के भारत के प्रति उदार रिश्ते तो जगजाहिर हैं, लेकिन शपथ के बाद उनका रुख बदला नजर आ रहा है। चाहे वह हजारों प्रवासियों को वापस भारत भेजना हो या टैक्स पर पुनर्विचार की बात, उनके तेवर बदले हुए हैं। ट्रंप के फैसलों पर एलन मस्क की छाप को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह किसी से छिपा नहीं रहा कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति मस्क ने सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और जीतने के बाद उन्होंने अपनी पसंद का विभाग गठित कराकर उसकी कमान भी अपने हाथ में ले ली। मस्क के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्टार लिंक और ई वाहन टेस्ला को भारत में हरी झंडी नहीं मिल पाई है। इसका मलाल मस्क के बयानों में झलकता भी है। भारत अपनी स्पेक्ट्रम नीति के कारण स्टार लिंक को बढ़ावा नहीं दे सकता तथा टेस्ला की गाड़ियों पर लगने वाला शुल्क मस्क को स्वीकार्य नहीं है। इसके पहले मस्क दो बार भारत आने का कार्यक्रम बनाकर रद कर चुके हैं। मस्क अब ट्रंप के माध्यम से स्टार लिंक और टेस्ला को भारत में लाने का प्रयास करेंगे। पिछले कार्यकाल में ट्रंप भी हार्ले डेविडसन जैसे कुछ मुद्दों को लेकर अपनी खीझ जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में नए ट्रंप प्रशासन में भारत को सतर्क रहने की जरूरत होगी।

करन त्रिपाठी, गोरखपुर

## मेलबाक्स

### मुफ्त घोषणाओं का दुष्प्रभाव

रेवड़िया बांटती राजनीति- शीर्षक से 23 जनवरी को प्रकाशित संपादकीय अग्रलेख पढ़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा की गई घोषणाएं वास्तव में चिंताजनक हैं। महिलाओं को प्रतिमाह 2100 से 2500 रुपये देने, गैस सिलिंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराने और बेरोजगारों को मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणाएं निश्चित रूप से मतदाताओं को आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन ये योजनाएं दिल्ली के विकास को गड्ढे में धकेलने वाली सिद्ध हो सकती हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल लगभग सभी राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि मुफ्त की योजनाएं निश्चित रूप से लोकप्रिय हो सकती हैं, लेकिन ये योजनाएं राज्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद नहीं करेंगी। इसके बजाय, राजनीतिक दलों को विकास और ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सुभाष, रतलाम, मध्य प्रदेश

### बच्चों में सामाजिकता का विकास

आज की पीढ़ी और पुराने लोगों में काफी अंतर है। यह अंतर है मेल-जोल का, अपनत्व का। पुराने समय में दो या दो से ज्यादा ज्यादा भाई बहन होते थे, साथ ही चचेरे-ममेरे-मौसेरे-फुफेरे भाई-बहन भी होते थे, जिनसे समय-समय पर मिलना जुलना होता था। पड़ोसियों से बातचीत और मेल मिलाप रहता था। परंतु धीरे धीरे यह सब बीते दिनों की बात होती जा रही है। व्यस्तता और फ्लैट सिस्टम के चलते पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या असर पड़ रहा है इन सब का बच्चों पर? बच्चे अपने भाई बहन, रिश्तेदारों और पड़ोस के बच्चों से मेलजोल, अपनी कोई चीज साझा करना, बातें करना, टीम में रहना और खेलना भूल गए हैं। जो भी समय बचता है वे मोबाइल में बिता देते हैं। इससे बच्चों के सोशल स्किल पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वे समाज में लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने और व्यावहारिक बनने से वंचित होते जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाना चाहिए, आस पड़ोस और रिश्तेदारों से सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उनमें सोशल स्किल बढ़ने के साथ ही आत्मविश्वास भी जागृत होगा।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली, पंजाब

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एमेरिटस-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

## सम्पादकीय

# ट्रंप की नीतियों से लाभ उठाए भारत, चीन से रहे सावधान

इसमें कोई संशय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कहीं अधिक ताकतवर राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। उनकी नई आर्थिक रणनीति में जहां समृद्ध अमेरिका के सपने को साकार करने के लिए आयात शुल्कों को बढ़ाना शामिल है, वहीं अमेरिका को चुनौती दे रहे चीन के आर्थिक दबदबे को कारोबारी प्रतिबंधों और ऊंचे शुल्कों से नियंत्रित करना भी। ट्रंप ने सबसे पहले चीन, कनाडा, मेक्सिको सहित उन शीर्ष पांच-छह देशों पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का संकेत दिया है, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सर्वाधिक है। चूंकि ट्रंप ने भारत को भी कुछ उत्पादों के लिए अधिक आयात शुल्क वाला देश कहा है, ऐसे में भारत द्वारा कुछ उत्पादों से शुल्क घटाने से उसे अमेरिका में निर्यात के अधिक मौके प्राप्त हो सकते हैं। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में वैश्वीकरण की जगह 'मेरा अमेरिका प्रथम' की धारणा को प्राथमिकता देते हुए परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की जगह अमेरिकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ने के इरादे जताए हैं। इसका कारण यह भी है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व में जो आर्थिक-कारोबारी नियम, समझौते और सहकारी एजेंडे बनाए गए, वे सब ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन ने स्वीकार्य वैश्विक कारोबारी नियमों का पालन नहीं किया है। उसने न केवल रणनीतिक रूप से पश्चिम का औद्योगीकरण समाप्त करने का काम किया है, बल्कि उसने पश्चिम की कई नई तकनीकें भी चुराई हैं। इसके चलते चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 2024 में अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन से रहा। 2030 तक चीन का विनिर्माण क्षेत्र समूचे पश्चिम के विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक हो जाने का अनुमान है। हाल में चीन ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की चुनौती से निर्मित कुछ पहलुओं पर अमेरिका से मुकाबले की नई आर्थिक रणनीति बनाई है। इसके तहत चीन में मांग में ठहराव, बिगड़ती बाहरी आर्थिक चुनौतियों और चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट की बात स्वीकार करते हुए बड़े आर्थिक प्रोत्साहन का रास्ता चुना गया है। रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि ट्रंप की नीतियों से चीन को भारी नुकसान हो सकता है और भारत समेत आसियान देशों को फायदा होगा। मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते तनाव और रणनीतिक क्षेत्रों में संभावित निवेश प्रतिबंधों के कारण भारत और अन्य एशियाई देशों को लाभ मिल सकता है। एशिया-प्रशांत में व्यापार और निवेश प्रवाह चीन से छिटक सकता है, क्योंकि अमेरिका रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को सख्त कर रहा है, जिसका चीनी आर्थिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई के अनुसार ट्रंप की आर्थिक नीतियों से यद्यपि भारत भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा, लेकिन दीर्घावधि में उनकी नीतियों का भारत पर सकारात्मक असर होगा।

भारत के लिए आर्थिक मौके बढ़ेंगे। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप की नीतियों से भारत के शेयर बाजार में और मजबूती आ सकती है। चीन में मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कई विदेशी कंपनियां भी भारत का रुख कर सकती हैं। भारत को अब तक चीन प्लस वन रणनीति अपनाने में सीमित फायदा ही मिला है। ट्रंप के कार्यकाल में यह फायदा बढ़ सकता है। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में ही अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से भारत-अमेरिका व्यापार बढ़ सकता है। भारत अमेरिका में निर्यात बढ़ाते हुए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भी आगे बढ़ सकता है।

## आज का इतिहास
बढ़ता राजस्थान

### 24 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- भारत के कोलकाता शहर में 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई।
- 1859 में 230 मीटर गहराई तक तेल के लिए खोदे गये कुएं से पहली बार तेल निकला।
- रूस में 1924 में पेट्रोग्राद का नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया।
- 1936 को अलबर्ट सैरुट फ्रांस के प्रधानमंत्री बने।
- चिली में 1939 में आये भूकंप से लगभग 50 हजार लोग मरे।
- संविधान सभा ने 1950 में राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना।
- जन-गण-मन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला।
- प्रेम माथुर 1951 में भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनीं।
- बंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1952 में हुआ।
- आल्प्स की पहाड़ियों में 1966 में मौंब्लां के शिखर के पास एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान दुर्घटना में लगभग 120 लोगों की मौत हो गई।
- नेवादा में परमाणु परीक्षण अमेरिका ने 1979 में किया।
- पेरू में सोने की खान में 1989 में 125 से अधिक मजदूर फँस गये।
- जापान ने 1990 में पहला लूनर प्रोब लॉन्च किया।
- लिथुआनिया गणराज्य ने 1991 में सोवियत संघ के सैनिकों हटाने की मांग की।
- 1993 को सोयूज टी.एम. 16 प्रक्षेपित किया गया।
- 1996 को सं.रा. अमेरिका के इतिहास में पहली बार देश की प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया।
- चुनावों में दलितों का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने हेतु संविधान के 79वें संशोधन को 2000 में राष्ट्रपति की मंजूरी।
- भारतीय उपग्रह इनसेट-3सी सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में 2002 में स्थापित।
- फ्रांस और भारत के बीच 2003 में प्रत्यर्पण संधि।
- आंध्र प्रदेश के तेलगुदेशम के विधायक परिताला रवि की 2005 में गोली मारकर हत्या करा दी गयी।
- मॉस्को के डोमोडिडोवो हवाई अड्डे पर 2011 में हुए बम विस्फोट से 40 लोगों की मौत, 200 घायल।

### 24 जनवरी को जन्मे व्यक्ति

- जर्मनी के लेखक अर्नेस्ट हूफमैन का 1776 में जन्म हुआ।
- फ्रांस के लेखक और कवि अलफ्रेड डो.वीनी का 1797 में जन्म हुआ।
- प्रथम भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का 1826 में जन्म हुआ।
- महान् स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का 1877 में जन्म हुआ।
- स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 1924 में जन्म हुआ।

## विशेष आलेख

# राष्ट्रीय बालिका दिवस : नये भारत के लिये बालिकाओं की बंद खिड़कियां खुलें

**सरकार का उद्देश्य बालिका दिवस के माध्यम से बालिकाओं के साथ समान व्यवहार करने और उन्हें वे अवसर प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता को व्यक्त करना है, जिनकी वे हकदार हैं। यह दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की तिथि भी है। इसका लक्ष्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना भी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम 'उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना' है। इसके लिये भारत में बालिकाओं के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन कई प्रभावी सरकारी योजनाओं के बावजूद भारत में बालिकाओं की स्थिति चिन्ताजनक है। देश में हुई 2016 की जनगणना में लड़कों की तुलना में लड़कियों की घटती संख्या के आंकड़े चौंकाते ही नहीं बल्कि दुखी भी करते हैं।**

ललित गर्ग

जहां पांव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया- जब भी कानों में इस गीत के बोल पड़ते है, गर्व से सीना चौड़ा होता है। जब नवरात्र के दिनों में कन्याओं को पूजित होने के स्वर सुनते हैं तब भी शकुन मिलता है लेकिन जब उन्हीं कानों में यह पड़ता है कि इन पायल, कंगन और बिंदिया पहनने वाली बालिकाओं के साथ कैसे अत्याचार, यौन-शोषण इंडिया क्या करता है, तब सिर शर्म से झुकता है। भारतीय समाज में लड़कियों को अक्सर भेदभाव, यौन-शोषण और अन्याय का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित रखा जाता है और उन्हें बहुत कम उम्र से ही घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। इन्हीं विडम्बनाओं एवं विसंगतियों को नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन समाज में लड़कियों के खिलाफ लैंगिक असमानता, रूढ़िवादिता, भेदभाव, यौन-शोषण और हिंसा की मौजूदा समस्याओं पर प्रकाश डालता है, बालिकाओं को सशक्त बनाता है और शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के महत्व का संदेश देता है। बालिकाओं की बन्द खिड़कियां खुलें, तभी नया भारत-सशक्त भारत बन सकेगा। जिस तरह से लड़के-लड़कियों का अनुपात असंतुलित हो रहा है, उससे ऐसी चिन्ता भी जतायी जाने लगी है कि यही स्थिति बनी रही तो लड़कियां कहां से लाएंगे? हालत यह है कि आंध्र प्रदेश में 2016 में प्रति एक हजार लड़कों के मुकाबले महज आठ सौ छह लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया। यह आंकड़ा सबसे निम्न स्तर पर मौजूद राजस्थान के बराबर है। तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी तस्वीर बहुत बेहतर नहीं है। बालिकाओं की घटती संख्या एक गंभीर चिन्ता का विषय है। हालांकि, बहुत से लोगों का मानना है कि 21वीं सदी तक आते-आते बालिकाओं एवं महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए अब हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। कहने को भले ही लड़कियां हर मामले में लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हो, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, क्षमता एवं कौशल का लोहा मनवा रही है लेकिन उनके सामने हर रोज एक लंबी चुनौती भी खड़ी है। भारतीय बालिकाओं एवं महिलाओं की समस्याएं केवल सामाजिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि कार्यस्थलों और घरों में भी वह मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित होती हैं। बालिकाओं एवं महिलाओं की सोच में भले ही पिछले कुछ सालों की तुलना में बदलाव आए हों लेकिन मर्दों की सोच और रवैये में कुछ खास फर्क नजर नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़क पर छोटे कपड़े पहनकर चलने में लगभग हर महिला ही असुरक्षित महसूस करती है। चीरहरण करती आंखें, अंजाने में छूने वाले हाथ और सीटियों की गूंज का सामना किसी लड़के को नहीं बल्कि लड़की को ही हर रोज करना पड़ता है। कुछ घरों में आज भी लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। वह कैसे बोलती है, कैसे कपड़े पहनती है, अपना जीवन जीने का तरीका किस तरह चुनती है, भले ही इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इससे असुरक्षित वातावरण महसूस करने लगते हैं। ज्यादातर लोगों ऐसा मानना है कि एक बालिका को मिलनसार होना चाहिए। उसे हमेशा ही समझौता करना चाहिए। भले ही वह बातें उसे नुकसान क्यों न पहुंचा रही हों। जन्म से पहले ही पता चल जाए कि बच्ची पैदा होगी तो ये उसकी जान लेने से भी नहीं कतराते। पिछली सदी में समाज के एक बड़े वर्ग में यह एक विभीषिका ही थी कि परिवार की धुरी होते हुए भी नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं था जिसकी वह अधिकारिणी थी। उसका मुख्य कारण था सदियों से चली आ रही कुरीतियाँ, अंधविश्वास व बालिका शिक्षा के प्रति संकीर्णता।

# त्रिपोलिये का दु:ख...

रूपक शर्मा

**त्रिपोलिया की ओट से निकलते भगवान भास्कर पूछ रहे है सबस, क्या ये वही तपोभूमि है या मैं कहीं और उदय हो गया हूँ? तो त्रिपोलियें के नेत्र शर्मसार हो गए हैं। त्रिपोलिया अपने दुःख के भाव को कुछ ऐसे बता रहा है..यहाँ तो यात्रियों के अभाव में तेजी से बढ़ते होटल्स अय्याशी के अड्डे बन गए हैं, हर पांचवा रोजगार अय्याशी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या ये वही तपोभूमि है यहां राजऋषि भर्तहरि लोक देवता के रूप में जनजन की आस्था बने थे।**

सरिस्का की वादियों में अरावली का सीना चीरकर तथाकथित होटल्स तेजी से रुपया कमाने का सबसे बड़ा जरिया बन बैठे हैं, जहाँ बाबा भर्तहरि के जयकारे गुंजायमान होते थे वहां बीयर व शराब की बोतलें कब्जा कर बैठी हैं,मेरे हिसाब से 1 प्रतिशत गेस्ट हाउस बचे होंगे जहां सिर्फ चादर धोने का खर्चा न हो,बाकी तो इसी खर्चे में चांदी कूट रहे हैं। ऐसा ही हाल रेस्टोरेंट व कैफेज का भी हुआ पड़ा है यहां पर्दे,सोफे,पार्टिशयन और अंधेरा इस बात को प्रकाशित कर रहा है यहाँ लोग पेट की पिपासा की जगह दूषित मन की पिपासा को को शांत करने का असफल प्रयास करते हैं। छोटी उम्र की बालिकाए जिनकी रक्षा व संरक्षण ये तपोभूमि करती थी आज उनके अबोधपन का लाभ उठाकर वहशी भेड़िए मौके की तलाश में रहते हैं, यूं तो खाकी सब जानती है पर व्यवस्थाओ के डीजल खर्चे के चक्कर मे आंखे मूंद लेती है। किस सभ्य व शिक्षित समाज के निर्माण कर रहे हैं हम।

बस इसे सुधारने के प्रयास हम सभी ऐसे कर रहे हैं जैसे अज्ञानी कम प्रजवलित हवन यज्ञ की अग्नि को जल छिड़क कर प्रजवलित करने का असफल प्रयास करता है। भगवान भास्कर भी आज टैंशन में हैं कि वास्तव में मैं कहीं और तो उदय नहीं हो गया ये तो वह तपोभूमि नहीं बल्कि अय्याशों का अड्डा बन चुकी है।

## शख्सियत
बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम की स्टार हैं दंबग शैली की आरएएस अधिकारी श्रीमती नीलिमा तक्षक। 15 मार्च सन1977 अलवर मे जन्मी नीलिमा शुरू से ही महत्वकांक्षी रहीं। एम.ए (इतिहास) बी.ए. (ऑनर्स) से शिक्षा पूर्ण करने के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा मे आईं। आज निदेशक हैं मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर। इससे पूर्व ये राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) जयपुर प्रथम। रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। विशेषाधिकारी, जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड जयपुर। परियोजना निदेशक कम उप सचिव, ईजीएस शासन सचिवालय, जयपुर। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर। आयुक्त, नगर परिषद भरतपुर। उप सचिव, अल्पसंख्यक मामलात जयपुर। उप निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर .। रजिस्ट्रार, बृज विश्वविद्यालय,भरतपुर। विशेषाधिकारी, जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर। अतिरिक्त निदेशक (दक्षिण) पर्यटक सूचना केन्द्र, चेन्नई। रजिस्ट्रार, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर। परियोजना प्रबंधक, एससी विकास निगम, अलवर। आयुक्त, नगर निगम, जयपुर। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अलवर। सहायक आयुक्त सह-सहायक सचिव, राहत, जयपुर। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिलापरिषद सह एडीपीसी द्वितीय ईजीएस अलवर। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) भरतपुर। कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस टोडाभीम (करौली) उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर। एलएओ, यूआईटी अलवर। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर। कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षणाधीन) अलवर रही। बेहद दबंग शैली के साथ सरकारी की योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने का प्रयास करती हैं। जहां भी रहीं वहां पूरी शिद्दत के साथ कार्य किया।

श्रीमती नीलिमा तक्षक
( राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी )

अनूठी छवि के कारण चाहे सुर्खियों मे रहीं हो लेकिन सच बोलने व कहने से कहीं नही चूकी। इसलिए आज इनका नाम पूरे गौरव और गर्व के साथ लिया जाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

## 2025_024
बढ़ता राजस्थान

Suduko

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| | | 5 | 7 | 1 | 9 | | 6 | 2 |
| | 3 | | | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| 6 | | 4 | | 8 | 7 | | 1 | |
| | 2 | 9 | 1 | | 6 | 8 | 5 | 7 |
| | 7 | | | 9 | 3 | | 4 | 6 |
| 9 | | | 6 | | 4 | 5 | 2 | |
| | 6 | 7 | 9 | 5 | | 4 | 3 | 1 |
| | 4 | | | | | 6 | | 9 |

Ans_2025_023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 |

### कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

## आज का राशिफल

[illegible]

### मेष
परिजनों के साथ सम्बंध मधुर होंगे। हेल्थ आज अच्छी रहेगी। हालांकि बाहर खाने-पीने से बचें। दोपहर के बाद अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ होगा। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना है।

### वृष
आज नए काम का आरंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अधिक कार्य से आलस्य और मानसिक चिंता का अनुभव करेंगे। यात्रा आज लाभदायी नहीं है, परंतु दोपहर के बाद आपको कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी।

### मिथुन
आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी है। आज आप चिंता से घिरे रहेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में भी किसी से मतभेद रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद आप सभी कामों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे।

### कर्क
आपको काम पूरा होने का उत्साह बना रहेगा। परिवार का वातावरण भी परिवर्तित होगा। आर्थिक लाभ की भी संभावना है। आज का दिन पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ का अवसर लाया है। किसी प्रिय पात्र से मुलाकात होगी।

### सिंह
गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। किसी छोटी यात्रा का आयोजन कर पाएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेंगे। परिश्रम की अपेक्षा फल कम मिलेगा।

### कन्या
परिजनों के साथ कोई विवाद हो सकता है। आपका आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। दिन की शुरुआत में स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। आपकी रचनात्मकता से आप कठिन काम भी आसानी से बना पाएंगे। काम का उत्साह बना रहेगा।

### तुला
संतान की ओर से भी अच्छे समाचार मिलेंगे। किसी मीटिंग के लिए छोटी यात्रा हो सकती है। नए काम शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा।

### वृश्चिक
किसी प्रिय मित्र या रिश्तेदार से बातचीत करके मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। सुबह के समय आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मन से खुश रहेंगे। परिजनों और मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

### धनु
कार्यालय या व्यवसाय में काम अधूरा रहने से मन निराश रहेगा। यात्रा में विघ्न आ सकता है। आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि आप के काम योजनानुसार पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। धन लाभ की संभावना है।

### मकर
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है। परिजनों तथा मित्रों के साथ अच्छे पलों को गुजारेंगे। किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है।

### कुंभ
विदेश जाने के इच्छुक लोग आज सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। दोपहर के बाद नया काम या टारगेट मिल सकता है। कोई अधूरा काम आज पूरा हो सकेगा। व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी।

### मीन
दिन की शुरुआत में आप थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे। आज आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दें। वाणी मधुर बनाए रखें, इससे कोई भी काम आसानी से बना पाएंगे, हालांकि किसी तरह के नए काम आज शुरू ना करें। आज आप कुछ धार्मिक बने रहेंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

# प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

अहिंसा सबसे शक्तिशाली और अनोखा हथियार है, जो इसे चलाने वाले को उदात्त बनाता है। -मार्टिन लूथर किंग जूनियर

**पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद कुछ यात्रियों के ट्रेन की चेन खींचकर बाहर कूदने और दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस द्वारा उन्हें रौंदे जाने की घटना बेहद हृदयविदारक है, जो यह भी दर्शाती है कि एक छोटी-सी अफवाह किस तरह हादसे का रूप ले सकती है।**

## अफवाह और हादसा

लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद कुछ यात्रियों के ट्रेन की चेन खींचकर बाहर कूदने और दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस द्वारा उन्हें रौंद दिए जाने से बारह लोगों की मौत वाकई दिल दहलाने वाली है, जो यह भी दर्शाती है कि एक मामूली-सी अफवाह किस कदर खतरनाक, इस मामले में तो जानलेवा भी, हो सकती है। गौरतलब है कि यह हृदयविदारक हादसा तब हुआ, जब ट्रेन महाराष्ट्र के जलगांव से गुजर रही थी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, जनरल बोगी यात्रियों से खचाखच भरी थी, तभी वहां मौजूद वेंडरों में से किसी एक ने ट्रेन में आग लगने की चीख लगाई। कुछ सेकंड बाद जब ट्रेन रुकी, तो कूपे के दोनों दरवाजों में से बाहर कूदने के लिए भगदड़ मच गई। दूसरी पटरी पर बंगलूरू से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस के लोको पायलट को मोड़ की वजह से पुष्पक के लोको पायलट द्वारा जलाई गई फ्लैश लाइट देर से दिखी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे यात्री इसकी चपेट में आ गए। गनीमत है कि कर्नाटक एक्सप्रेस के लोको पायलट ने ब्रेक लगा दिए थे, वरना यह हादसा और भी भयावह हो सकता था। लेकिन यह भी है कि जलगांव खंड में ट्रेनों की औसत रफ्तार सौ किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ही होती है, लिहाजा ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन को रुकने में समय लगा, जो एक अफवाह के मानवीय त्रासदी का रूप लेने के लिए काफी था। ये अफवाहें दरअसल सूचनाओं का अराजक प्रवाह होती हैं, जो मनुष्य में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। मुश्किल यह है कि जब कोई सूचना डर पैदा करती है, तो लोग बगैर पुष्टि किए, उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। इसे ही मनोविज्ञान में फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स कहा जाता है, जहां व्यक्ति त्वरित निर्णय लेकर खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। ट्रेन में आग लगने की अफवाह ने भी कुछ ऐसा ही किया। भीड़ में अफवाह तेजी से फैलती है, और लोग 'भीड़ मनोविज्ञान' के अनुसार दूसरों का अनुसरण करने लगते हैं। इस मामले में भी यकीनन ऐसा ही हुआ, जब कुछ यात्रियों को ट्रेन से कूदते देख बाकी भी बगैर सोच-विचार किए कूद गए। जबकि ट्रेन में कहीं कोई आग नहीं लगी थी, जिसकी पुष्टि रेलवे भी कर चुका है। बहरहाल, ताजा हादसा सभी के लिए एक सबक होना चाहिए। रेलवे तंत्र की बेशक इसमें कोई चूक न हो, फिर भी यात्रियों को आपातकालीन प्रक्रियाओं को लेकर जागरूक बनाने के प्रयास तो किए ही जा सकते हैं।

## खूनी संघर्ष के मुहाने पर म्यांमार

**म्यांमार में अराकान आर्मी ने सितवे को जोड़ने वाले सभी सड़क मार्ग काट दिए हैं। अगर विद्रोही स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, तो यह बांग्लादेश निर्माण के बाद एशिया में पहला सफल अलगाववादी अभियान होगा। भारत के लिए भी बड़ा दांव होगा, क्योंकि कलादान परियोजना में रखाइन की स्थिति महत्वपूर्ण है।**

सितवे (पूर्व में अक्याब) शहर को यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान (यूएलए) की सैन्य शाखा अराकान आर्मी (एए) के लड़ाकों ने पूरी तरह घेर लिया है। वे रखाइन (पूर्व में अराकान) राज्य को म्यांमार की जुंटा सेना के नियंत्रण से मुक्त कराना चाहते हैं। एए के करीब 18,000 लड़ाकों ने रखाइन राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय सितवे को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले सभी भूमि मार्गों को काट दिया है। अगर सितवे अराकान आर्मी के कब्जे में आ गया और विद्रोही स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, तो यह 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में पहला सफलतापूर्वक अलगाववादी अभियान होगा।

सुबीर भौमिक
वरिष्ठ पत्रकार

सेना और एए समेत कई सूत्रों के अनुसार, फिलहाल सितवे बंदरगाह और आसपास के तटीय गांवों पर म्यांमार की सेना का नियंत्रण है। अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर सेना के एक भगोड़े ने बताया, 'सेना समुद्री और हवाई मार्ग से भारी संख्या में सुरक्षा बल भेज रही है, लेकिन सड़क मार्गों को एए के लड़ाकों द्वारा काट दिया गया है।' शीर्ष सूत्र ने *म्यांमार नाउ* वेबसाइट को बताया, 'सेना सितवे को अराकान आर्मी के हाथों में जाने से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है।' उसी सूत्र के अनुसार, एए लड़ाकों ने सितवे को घेर लिया और वे किसी भी वक्त बड़ा हमला बोल सकते हैं। *म्यांमार नाउ* ने कहा कि शासन ने एए से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने से पहले आह म्यिंट क्यून, पा दा लेइक और बायिन फ्यू गांवों के निवासियों को बाहर निकाल लिया है।

एए सूत्रों का कहना है कि विद्रोही निर्णायक हमला करने से पहले भोजन और गोला-बारूद जमा कर रहे हैं। म्यांमार सेना के भगोड़े ने कहा, 'इस सफलता के लिए एए की घेराबंदी तकनीक जटिल है। कस्बों की घेराबंदी इतनी गहन और पूर्ण है कि घटती आपूर्ति के कारण सेना का मनोबल कमजोर हुआ है।' लेकिन सितवे में बंदरगाह और आसपास के समुद्र तट पर नियंत्रण से सेना को आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेना के भगोड़े ने कहा, 'जुंटा अब अपनी वायु शक्ति का अंधाधुंध और बेरहमी से उपयोग करेगी, इसलिए हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी।'

रखाइन राज्य के 18 में से 15 नगर यूएलए-एए के नियंत्रण में हैं। इन क्षेत्रों में यूएलए-एए राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासकों की जगह अपना खुद का शासन तंत्र स्थापित कर रहा है। मरौक-यू नगर के एक निवासी ने *वेस्टर्न न्यूज* को बताया कि प्रशासकों के बदलाव के पीछे एए को आशंका है कि जुंटा द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हवाई हमलों के लिए जुंटा को मुखबिरी कर सकते हैं। मिनब्या के एक निवासी ने बताया कि एए ने जुंटा द्वारा नियुक्त कुछ अधिकारियों को पदों पर बरकरार रखा है, क्योंकि उन्हें 'भरोसेमंद' माना गया था। आशंका है कि अंततः सितवे को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ेगा। एए के एक अधिकारी ने कहा, 'सेना ऐन या उत्तर में लैशियो (पूर्वोत्तर कमांड का पूर्व मुख्यालय) की तुलना में उनकी स्थिति का अधिक तीव्रता से विरोध करेगी। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है।'

अराकान आर्मी के लड़ाके रखाइन राज्य को हासिल करने के लिए सितवे के संघर्ष को स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के रूप में देखते हैं, जिसे अराकानियों ने वर्ष 1784 में गंवा दिया था। एए अधिकारी ने क्रूर और भीषण संघर्ष के संकेत दिए हैं। लेकिन यूएलए-एए को राजनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके लड़ाके रखाइन राज्य को मुक्त कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एए थ्री ब्रदरहुड गठबंधन का हिस्सा है (कोकांग समूह एमएनडीडीए और टैंग समूह टीएनएलए गठबंधन के अन्य सदस्य हैं)। इसका काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिसने 2007-08 में एए को बढ़ाने में मदद की और बर्मी मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के पूर्व सांसदों और नेताओं से बनी राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) के साथ कार्यात्मक संबंध बनाए रखा है।

क्या यूएलए-एए रखाइन से म्यांमार की सेना को खदेड़ने के बाद स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा या फिर सेना के हार मानने के लिए मजबूर होने और संघीय सरकार के गठन होने तक अपने पत्ते नहीं खोलेगा? बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य प्रतिरोधी ताकतें कितनी सफल हैं और सेना कितनी जल्दी इसे खत्म कर देगी। भारत के लिए बड़ा दांव है। समुद्र-नदी-सड़क द्वारा भूमि से घिरे पूर्वोत्तर से जुड़ने के दूसरे विकल्प के रूप में भारत द्वारा वित्त पोषित कलादान मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना की सफलता रखाइन और चिन राज्यों की स्थिति पर निर्भर करती है। एए न केवल रखाइन के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है, बल्कि चिन राज्य में पलेटवा के महत्वपूर्ण नदी संगम को भी नियंत्रित करता है। हालांकि एए शुरू में दक्षिणी मिजोरम में अपने ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान 'सनराइज' के लिए भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण था, लेकिन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पिछले कुछ समय में गुप्त प्रयास किए गए हैं। इसके बाद विद्रोही समूह ने कहा है कि वह रखाइन अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद विदेशी निवेश का समर्थक है।

एए सितवे पर हमला करने के लिए पूरी तरह से बेशक तैयार है, लेकिन वह चीन द्वारा वित्तपोषित गहरे समुद्री बंदरगाह क्याउकफ्यू पर किसी हमले की योजना नहीं बना रहा है और उस क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के जारी हैं। भारत को म्यांमार में अपने हितों की रक्षा के लिए चीन से सीख लेते हुए जुंटा और विद्रोही बलों, दोनों से बातचीत करनी चाहिए, जो भारत की महत्वाकांक्षी 'एक्ट ईस्ट' नीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस बीच, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के विदेश मंत्रियों ने म्यांमार के सैन्य शासन से फिलहाल चुनाव कराने के बजाय सभी विद्रोही समूहों से बातचीत कर सुलह करने की सलाह दी है। मलयेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर म्यांमार के मन में क्या है। चुनाव समावेशी आधार पर हो, जिसमें सभी शामिल हों। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हिंसा रोकना है, न कि चुनाव।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

जॉन होल्ट

**शिक्षा वह चीज है, जिसे हर व्यक्ति अपने लिए खुद हासिल करता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं, जो कोई दूसरा उसे देता हो या दे सकता हो। स्कूल शिक्षा पाने का एक साधन है, लेकिन एकमात्र साधन नहीं।**

### सबसे पहले आसपास की दुनिया को समझें

*सच्ची सीख-ऐसी सीख जो स्थायी और उपयोगी हो, जिससे हम समझदारी के काम कर सकें और आगे भी सीख सकें, केवल सीखने वाले के अनुभवों, रुचियों और सरोकारों में से पैदा हो सकती है। हरेक बच्चे में, बिना किसी अपवाद के, अपनी दुनिया को समझने की एक असीमित अंदरूनी ललक होती है और वह इस दुनिया में सक्षम बनना चाहता है, उसमें स्वतंत्रता चाहता है। शिक्षा वह चीज है, जिसे हर व्यक्ति अपने लिए खुद हासिल करता है। वह कोई ऐसी चीज नहीं, जो कोई दूसरा उसे देता हो या दे सकता हो। नवयुवकों को अपनी शिक्षा से जिस चीज की जरूरत है और जो वे उससे चाहते हैं, वह यह है, पहला, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझना। दूसरा, अपने आपको विकसित करना। तीसरा, ऐसे काम कर पाना, जिनमें वे अपनी विशेष रुचियों और कुशलताओं का इस्तेमाल करके अपने आसपास की दुनिया की असली समस्याओं से जूझ सकें और इन्सानियत का भला कर सकें। हमारा समाज चाहता है कि स्कूल बच्चों के लिए और उनके बारे में तीन चीजें करे। पहली, उन्हें हमारी परंपराओं और संस्कृति के उच्च मूल्यों को सिखाना। दूसरी, बच्चे जिस दुनिया में जीते हैं, उससे उन्हें अवगत कराना। तीसरी, बच्चों को किसी रोजगार और यदि संभव हो सके, तो सफलता के लिए तैयार करना। परंपरागत तौर पर इन सभी जिम्मेदारियों को समाज ने स्वयं ही निभाया है। इनमें से एक भी काम स्कूल अच्छी तरह नहीं करता है। अगर आज स्कूल मुश्किल में हैं, तो उसका कारण यह है कि उन्हें कई ऐसे काम सौंप दिए गए हैं, जिन पर उनका सर्वाधिकार है ही नहीं। स्कूल एक साधन हो, परंतु एकमात्र साधन नहीं। एक ऐसा साधन, जहां से बच्चे और केवल बच्चे ही नहीं, अपनी सतत शिक्षा के लिए जिस चीज की उन्हें जरूरत हो और जो चाहें ले सकें। स्कूल ऐसी जगह हो, जहां जाकर लोग वह सब खोज सकें, जो वे खोजना चाहते हैं और अपनी उन कुशलताओं को विकसित कर सकें, जिन्हें वे विकसित करना चाहते हैं। अगर बच्चा खुद को शिक्षित कर रहा है, क्योंकि कोई और उसे शिक्षित नहीं करेगा, तो वह स्कूली संसाधनों को, किसी वयस्क की ही भांति, जब और जैसे वह चाहे इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो। शिक्षा की अनंत राहें हैं। सीखने वाला अपना पथ खुद खोजने, चुनने, बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। बच्चे चाहते हैं कि वे जल्दी-से-जल्दी समाज में किसी-न-किसी रूप में उपयोगी हों। हमें उन्हें इस बात के मौके देने चाहिए। अगर कोई बच्चा या वयस्क समाज के लिए उपयोगी काम करना चाहता है, तो उसे उससे वंचित रखना इन्सानियत के खिलाफ एक अपराध होगा। दरअसल, शिक्षा और काम के बीच यह विरोध जो हमने पैदा कर दिया है, एकदम मनमाना, अवास्तविक और हानिकारक है। जब तक बच्चों की सीखने और अपने आपको विकसित करने की ललक व क्षमता में हमारा विश्वास नहीं होगा, तब तक उनकी सहायता करना तो दूर, हम उनकी शिक्षा को नुकसान ही पहुंचाएंगे।*

*'द अंडर-अचीविंग स्कूल' के अनूदित अंश*

### सीखना जारी रखें

सूत्र

*पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सीखने की प्रक्रिया है। बुद्धि स्कूली शिक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए जीवन भर के प्रयासों का नतीजा है। जो कोई भी सीखना बंद कर देता है, वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे वह बीस साल का हो या अस्सी साल का। जो सीखता रहता है, वह हमेशा जवान रहता है।*

## दूसरा पहलू

चेक गणराज्य ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए कपड़ों के पुनर्चक्रण का फैसला किया है।

### एक जोड़ी जींस और 3,781 लीटर पानी

चेक गणराज्य ने 2025 से अपने देश में कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट कपड़े का पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके और पर्यावरण को इसके व्यापक दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां का प्रत्येक नागरिक सालाना वजन के हिसाब से लगभग 10-12 किलोग्राम कपड़ा फेंक देता है। ऐसे में यह निर्णय कपड़ा कचरे की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से के लिए कपड़ा उद्योग से जुड़ी प्रक्रियाओं को जिम्मेदार माना जाता है।

एक जोड़ी जींस बनाने में कपास के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद को स्टोर तक पहुंचाने तक 3,781 लीटर पानी लगता है। वहीं, विश्व बैंक के अनुसार, हर साल फैशन उद्योग 93 अरब घन मीटर पानी का उपयोग करता है।

परिधान उद्योग दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में शुमार है। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से के लिए कपड़ा उद्योग से जुड़ी प्रक्रियाओं को जिम्मेदार माना जाता है। तंतु के लिए कपास उत्पादन से लेकर निर्माण, विक्रय, इस्तेमाल और उसके अंतिम रूप से नष्ट होने तक एक कपड़ा व्यापक कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करता है। कपड़ा निर्माण के दौरान पानी की अंधाधुंध खपत होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, एक जोड़ी जींस बनाने में कपास के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद को स्टोर तक पहुंचाने तक 3,781 लीटर पानी लगता है। विश्व बैंक के अनुसार, हर साल फैशन उद्योग 93 अरब घन मीटर पानी का उपयोग करता है, जो पचास लाख लोगों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। दरअसल, कपड़े के उत्पादन से इतर उसके रखरखाव में भी बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ऐसा अनुमान है कि वस्त्र उत्पादन, रंगाई और परिष्करण उत्पादों से होने वाले वैश्विक स्वच्छ जल प्रदूषण के लगभग 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। कपड़े से निकला अपशिष्ट भूमि व जल प्रदूषण का कारण बनता है। यही नहीं, कपड़ों को बार-बार धोने से उसमें से माइक्रोप्लास्टिक भी निकलते हैं।

यूरोपियन संसद की एक रिपोर्ट बताती है कि पॉलिएस्टर कपड़ों की एक धुलाई से सात लाख माइक्रोप्लास्टिक फाइबर निकलते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं। सिंथेटिक उत्पादों को धोने से हर साल समुद्र तल पर पांच लाख टन से अधिक माइक्रोप्लास्टिक जमा हो जाते हैं। पल-पल बदलते फैशन के कारण उत्पादित और फेंके जाने वाले कपड़ों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है, जो चिंता की बात है। इससे पारिस्थितिकीय असंतुलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। 'फास्ट फैशन' की बढ़ती प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के लिए भले ही हितकारी हो, लेकिन इसका पर्यावरण एवं समाज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। हमें अपने क्रय और उपयोग के तरीकों पर पुनर्विचार करना चाहिए। कपड़ों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण में भागीदारी करनी चाहिए और 'फास्ट फैशन' के बजाय टिकाऊ विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए। -सुधीर कुमार

## आंकड़े

### डीमैट खाते

बीते दस वर्षों में भारत में डीमैट खाते करीब नौ गुना बढ़ गए हैं। इससे पता चलता है कि लोग अब शेयर बाजार में ज्यादा निवेश कर रहे हैं।

| वर्ष | डीमैट खाते |
|---|---|
| 2014 | 2.2 |
| 2020 | 4.1 |
| 2022 | 9.0 |
| 2023 | 11.4 |
| 2025 | 18.5 |

आंकड़े संबंधित वित्त वर्ष में डीमैट खातों के, करोड़ में | स्रोत : RBI, GS, MO& Cd

**सावंतवाड़ी जाते वक्त दिव्य पुरुष के दर्शन करने के बाद श्रीसोहिरोबा की चित्तवृत्ति ही बदल गई। वह महाराज की नौकरी छोड़कर भगवान की भक्ति में रम गए।**

### श्रीसोहिरोबा महाराज

भक्त श्रीसोहिरोबा के पिता व्यवसाय करते थे और सावंतवाड़ी के बांदा गांव में आकर रहने लगे थे। वहीं पर श्रीसोहिरोबा का जन्म संवत 1692 में हुआ। उनके अंदर बचपन से ही भक्ति के लक्षण दिखते थे। युवा होने पर वह कुलकर्णी (पटवारी) नियुक्त हुए। बताया जाता है कि वह अपना काम बड़ी दक्षता और ईमानदारी के साथ करते थे।

उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर सावंतवाड़ी के महाराज खेम सावंत ने श्रीसोहिरोबा को बुलावा भेजा। श्रीसोहिरोबा सावंतवाड़ी के लिए निकल पड़े। रास्ते में भूख लगने पर उन्होंने एक कटहल लिया और पेड़ की छाया में बैठ गए। कटहल को दो हिस्सों में बांटकर वह पहला निवाला खाना ही चाहते थे कि उन्हें आवाज सुनाई दी कि बेटा हमें कुछ देगा! उन्होंने देखा, तो एक दिव्य पुरुष सामने खड़े थे। श्रीसोहिरोबा ने प्रणाम कर कटहल उनके सामने रख दिया। वह दिव्य पुरुष पूरा कटहल खा गए और पांच छोटे से टुकड़े प्रसाद के रूप में उन्हें दे दिए। वह दिव्य पुरुष श्रीसोहिरोबा के सिर पर हाथ रखकर अंतर्धान हो गए। उनके दिए हुए टुकड़े खाने के बाद श्रीसोहिरोबा की चित्तवृत्ति ही बदल गई। महाराज सावंत ने जिस काम के लिए श्रीसोहिरोबा को बुलाया था, उसे पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भगवान की भक्ति में रम गए। वह बाद में उज्जैन जाकर एक मठ में रहकर तपस्या करने लगे थे। एक दिन वह जैसे ही मठ से बाहर आए, तो अदृश्य हो गए।

अंतर्यात्रा
संकलित

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 29 अक्तूबर, 1963

### ख्रुश्चेव ने आर्थिक कठिनाइयों से यात्रा स्थगित कर दी

ख्रुश्चेव ने आर्थिक कठिनाइयों से यात्रा स्थगित करदी

रूस के प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने घोषणा की कि रूस अपने आर्थिक संकट व अन्य परेशानियों के कारण चंद्रलोक पर सर्वप्रथम कम्युनिस्ट क्रांति का लाल झंडा फहराने के प्रयास को स्थगित कर रहा है।

## इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का वक्त आ गया है

**इलेक्ट्रिक कारें महंगी होने की वजह से फिलहाल कम बिक रही हैं, लेकिन अब कई कंपनियां बाजार में किफायती कारें उतारने की तैयारी में हैं।**

मधुरेंद्र सिन्हा

परिवहन

अस्सी के दशक में देश में कार क्रांति का सूत्रपात हुआ था और मारुति को उसका श्रेय जाता है। चार दशकों के बाद अब फिर एक कार क्रांति होती दिख रही है। इस बार यह इलेक्ट्रिक कारों के रूप में होगी। पिछले कुछ वर्षों से भारत के वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक कारें दिखने लगी हैं। टाटा मोटर्स ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद तो लगभग हर ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऐसी कारें बनानी शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन में अग्रणी है, भारत में आने के लिए उत्सुक है, लेकिन समस्या है कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क भारत सरकार की शर्तों पर यहां आने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वह आते हैं तो फिर बाजार में जबर्दस्त स्पर्धा होगी।

बहरहाल, भारत में काम कर रहीं तमाम कार कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें बनाने लगी हैं, मारुति को छोड़कर। टाटा मोटर्स के अलावा, भारत की दूसरी बड़ी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा भी उतर चुकी है।

कोरियाई कंपनी हुंडई, एमजी, चीनी कंपनी बीवाईडी, विदेशी लग्जरी कार निर्माता कंपनियां जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी आदि ने भी अपनी कारें पेश कर दी हैं। इनके अलावा हाई एंड कार कंपनी रॉल्स रॉयल भी इलेक्ट्रिक कारें लेकर हाजिर है। बेशक उसकी कीमत सात करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। लेकिन जिस कार कंपनी को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है वह है मारुति, जो इसी साल इलेक्ट्रिक कारें लेकर आ रही है। बताया जाता है कि वह तीन तरह की इलेक्ट्रिक कारें लेकर आएगी।

इस साल कार बाजार में स्पर्धा तेज होगी। जापानी कंपनी टोयोटा मारुति के साथ मिलकर अपनी इलेक्ट्रिक कारें उतारेगी। मारुति बाजार की स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए शक्तिशाली बैटरी वाली कारें उतारने जा रही है। कहा जा रहा है कि ये कारें एक चार्ज में 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। कंपनी कीमतों को वहन करने लायक रखेगी, ताकि अधिक बिक्री हो। इलेक्ट्रिक कारों के साथ यह समस्या आ रही थी कि ये एक चार्ज में लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पा रही थीं। इसके अलावा उनके चार्जिंग की भी समस्या थी। ठीक वैसी स्थिति है, जैसी सीएनजी वाली कारों के मालिकों को एक जमाने में झेलनी पड़ी थी।

ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) की बैटरियों का सबसे बड़ा निर्माता देश चीन है, जो दुनिया की कुल खपत का 79 फीसदी उत्पादन करता है। उसके बाद अमेरिका का स्थान है। विदेशों से आयातित होने के कारण इन बैटरियों की कीमतें भी ज्यादा हैं। भारत में बैटरियां बनती हैं, लेकिन कम। कारों की बैटरियां लीथियम से बनती हैं। अभी भारत में लीथियम की खोज चल रही है। भारत जितनी जल्दी बैटरी बनाने में स्वावलंबी होगा, ग्राहकों को उतना ही फायदा होगा। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां बहुत महंगी हैं और उनकी कुल कीमतें कार की कीमतों का 70 फीसदी तक हो सकती हैं। दूसरी ओर, अब कार कंपनियां शक्तिशाली बैटरियों की तलाश में हैं। बताया जा रहा है कि मारुति दो पैक वाली 60 किलोवाट की बैटरी लेकर आ रही है। इससे कारों के ज्यादा दूर बिना चार्ज के जाने की क्षमता बढ़ जाएगी।

महंगी होने की वजह से अभी देश में कुल कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या एक फीसदी से कुछ ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन मुफ्त कर दिया गया है। भारत सरकार की नीति भी यही है कि इन कारों को 2030 तक कम से कम 30 फीसदी की सब्सिडी मिले। यह सब्सिडी ही कारों को खरीदने के योग्य बना रही है। इलेक्ट्रिक कारों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इनके रखरखाव पर खर्च नहीं के बराबर है। ऐसा इसलिए है कि जहां परंपरागत कारों में इंजन सहित सैकड़ों पुर्जे होते हैं, वहीं इन कारों में महज आठ-दस ही होते हैं। इसलिए पुर्जे वगैरह खराब होने की आशंका खत्म हो जाती है। और बार-बार सर्विसिंग से छुटकारा मिल जाता है। कारों का वजन कम हो जाने के कारण टायरों की भी लाइफ बढ़ जाती है।

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी हाइब्रिड गाड़ियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियां पेट्रोल और बिजली, दोनों से चलती हैं, जिससे बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। इससे परंपरागत कारों का उद्योग बचा रह जाएगा और वे तमाम पुर्जा बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाने से बच जाएंगी। अभी इन कंपनियों में लाखों लोग काम करते हैं और वहां अरबों रुपये का व्यवसाय होता है। बहरहाल, अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, तो इसके चार्जिंग की व्यवस्था घर पर ही करें। कमर्शियल चार्जिंग महंगी है। ऐसे में चार्जिंग लागत आधी हो जाएगी। आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी एक अच्छा सौदा हो सकता है।